छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

चतुर्थ विधान सभा **सप्तदश सत्र**

बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

(भाद्रपद 21, शक सम्वत् 1940)

[अंक 02]

छत्तीसगढ़ विधानसभा

बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

(भाद्रपद 21, शक संवत् 1940)

विधानसभा पूर्वान्ह 11.01 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>कार्यमंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय कार्य एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

1. **वित्तीय कार्य** :-

वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	3 घंटे

2. **विधि विषयक कार्य**

(1)	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018	15 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

चौधरी\12-09-2018\a10\11.00-11.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन मरकाम (कोन्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने मंहगाई लगातार बढ़ रही है, इसके बारे में स्थगन दिया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आम जनता बहुत परेशान है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग डेंगू से भी कर रहे हैं। 42 लोग डेंगू से मर गये हैं, 4 हजार लोग हास्पिटल में भर्ती हैं। हम लोग जनता के हित की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि सभापति तालिका तक वेट करें। इतना तो विश्व में किसी भी विधानसभा या लोकसभा में ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष के निवेदन को भी आप नहीं मान रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तीजा का पर्व चल रहा है, दुर्ग भिलाई में बहनें नहीं आ पा रहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह।

समय : **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

11:01 बजे **<u>भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-1)</u>**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद- 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, (वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-1) पटल पर रखता हूं।

समय : **जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन**
11:02 बजे **सदन के पटल रखा जाना।**

अध्यक्ष महोदय :- जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय : **नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं**
11:03 बजे **तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना।**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- मैं नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

माननीय राष्ट्रपति/ राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- चतुर्थ विधानसभा के मार्च, 2016 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा अगस्त, 2017 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं जुलाई, 2018 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से पारित सभी विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा (श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े) :- चतुर्थ विधानसभा के मार्च, 2016 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा अगस्त, 2017 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं जुलाई, 2018 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से पारित सभी विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\a11\11.05-11.10

समय

11.05 बजे **<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>**

सभापति महोदय:- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूँ:-

1. श्री देवजी भाई पटेल,
2. श्री सत्यनारायण शर्मा,
3. श्री संतोष बाफना,
4. श्री शिवरतन शर्मा,
5. श्री धनेन्द्र साहू

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार चाहे तो छत्तीसगढ़ के निवासियों को वेट टैक्स कम करके राहत दे सकती है। इसलिए हमने स्थगन लाया है। इस पर चर्चा कराकर के छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ आम जनता को राहत दे सकती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं। इसलिए शायद उनको पता नहीं होगा कि महंगाई राज्य का विषय नहीं है। विधान सभा में राज्य के विषय पर ही चर्चा होती है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों ने, राजस्थान ने वेट टैक्स कम करके वहां की जनता को राहत दी है। आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिये, वहां आपकी सरकार है। 4 प्रतिशत वेट टैक्स कम करके वहां के आम जनता को राहत दिया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार वेट टैक्स कम करके यहां की जनता को भी राहत दे सकती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जय सिंह अग्रवाल जी गाड़ी में चलकर आ रहे हैं। महान किसान नेता माननीय जय सिंह अग्रवाल।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट अध्यक्ष महोदय। आज तीजा है। पोला कौन किसान मनाते हैं, आप एक मिनट बोल दो। छत्तीसगढ़ में पोला का किसानी से क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपस में डिस्कशन नहीं होगा। बैठिये। डॉ0 रमन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 लाख करोड़ रूपया पेट्रोल डीजल से वेट लगाकर मुनाफा कमा लिये।

समय
11.07 बजे **<u>वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन</u>**

मुख्यमंत्री (डॉ0 रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज बुधवार दिनांक 12 सितम्बर, 2018 की ही तिथि निर्धारित करता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

11.08 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

अध्यक्ष महोदय :- मैंने, सत्र की अल्प अवधि को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्नलिखित विधेयक :-

1. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018)

2. छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)

3. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) को आज ही पुर:स्थापित, विचार तथा पारण करने की अनुमति प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री।

1. **छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018)**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2. **<u>छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)</u>**

मुख्यमंत्री (डॉ0 रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (डॉ0 रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूँ।

.....श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\a11\11.05-11.10

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक 2018 (क्रमांक 16 सन 2018) का पुर:स्थापन करता हूॅ ।

<u>3. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन 2018) का पुर:स्थापन</u>

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूॅ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन 2018) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन 2018) का पुर:स्थापन करता हूॅ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

11.07 बजे **वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परम्परानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं, माननीय यमुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा प्रदेश जानता है, आज विशेष सत्र है और यह किसानों को बोनस देने के लिए बुलाया गया है । नेता प्रतिपक्ष और पी.सी.सी. के अध्यक्ष दोनों नदारद हैं । क्या वे किसानों को बोनस देने का विरोध कर रहे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- नहीं वह बैलगाड़ी में आ रहे हैं । महंगाई बढ़ रही है ।

एक माननीय सदस्य :- विधायक दल के सारे साथी बैलगाड़ी से आ रहे हैं । क्योंकि डीजल और पेट्रोल .....(व्यवधान)

श्री नवीन मारकण्डेय :- इस तरह की नौटंकी करना इनकी आदत में है । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक अखबारों में लीक हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इसे आपकी और सदन की जानकारी में लाते हुये मैं इस जानकारी को पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अनुमति नहीं दी है ।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं,राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि-

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 13, 29, 36, 41, एवं 64 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय को कुल मिलाकर दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ- श्री मोहन मरकाम ।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में दूसरी अनुपूरक प्रस्तुत की है । माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथे विधान सभा का समापन हो जाता है, फोटो सेशन हो जाता है, उसके बाद बिदाई समारोह भी हो जाती है । उसके बाद क्या जरूरत पड़ी कि दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर, अनुपूरक बजट के माध्यम से ....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- यह जो सत्र है, जयसिंह जी की छबि किसान नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए बुलाई गई है । 2400 करोड़ कहां समझ में आयेगा ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आनुवांशिक संगठन है । अभी सर्वे कराया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 22 सीट से ज्यादा नहीं जीत पा रही है । सरकार ने सर्वे कराया था तो 28 सीट से ज्यादा कहीं जीत नहीं पा रही है । मगर सरकार ने विदाई समारोह के बाद आनन-फानन में किसानों को धान का समर्थन मूल्य ....

अध्यक्ष महोदय :- बोलने तो दो ।

श्री मोहन मरकाम :- किसानों को बोनस देने की बात, इस पवित्र सदन में पास करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है । आज सरकार में इतनी घबराहट क्यों है । क्या सत्ता जाने का डर सता रहा है । आज सब लोग डरे हुये हैं । आनन-फानन में चैनलों को खरीदकर सर्वे दिखाया जाता है कि बस्तर से 12 में 11 सीट जीत रहे हैं । आप 12 में 12 क्यों नहीं दिखाते?

श्री अजय चन्द्राकर :- एक लाईन को तो पहले बोलो । 2400 करोड़ रूपये के समर्थन में हो कि नहीं हो । बोनस के समर्थन में हो कि विरोध में हो । उसके बाद बाकी बात । मोहन जी .....

श्री मोहन मरकाम :- जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि हम किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे और हम पांच साल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तक प्रतिवर्ष तीन सौ रूपये किसानों का बोनस देंगे । माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले 2015-2016 में आपने नहीं दिया, आज अचानक जरूरत क्यों पड़ी । आपको लगता है कि आपके जितने सर्वे हैं, आपसे किसान बहुत ज्यादा परेशान है । आज आपके विधान सभा क्षेत्र राजनांदगांव में लाखों की संख्या में किसान रैली निकालते हैं आंदोलन करते हैं । आप अपने विधान सभा क्षेत्र में इतने डरे हुये हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए आनन-फानन में विशेष सत्र बुलाकर आप बोनस दे रहे हैं । सरकार से हमारी मांग है कि आप सचमुच में बोनस देना चाहते हैं तो ....

जारी...श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\a13\11.15-11.20

जारी......श्री मोहन मरकाम :- आप अपने ही विधानसभा क्षेत्र में इतने डरे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिये आनन-फानन में आज विशेष सत्र बुलाकर आप बोनस दे रहे हैं। इस सरकार से हमारी मांग है कि यदि आप सचमुच में बोनस देना चाहते हैं तो आप 5 साल का बोनस दीजिये क्योंकि आपने इसी पवित्र सदन में घोषणा की थी और हर साल बोनस देने की बात की थी । माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपका घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र नहीं है बल्कि आपका संकल्प पत्र है, आज छत्तीसगढ़ में भी है और केंद्र में भी है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मरकाम जी, एक मिनट । श्री वोरा जी बहुत देर से उठना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब 1500 किसानों ने आत्महत्या की थी तो उस समय आपने 24,00 करोड़ रूपये क्यों नहीं बढ़ाया ? श्री चंद्राकर जी, 1500 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और बढ़ाना ही था तो 15 क्विंटल की बजाय 35 क्विंटल देना था।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- श्री वोरा जी, अपन वह बात करें जो समझ में आये । एक-दूसरे की समझ में आये ऐसी बात करें ।

श्री अरूण वोरा :- दोनों की समझ में आ रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- श्री मोहन मरकाम जी, पहली बात यह है कि अनुपूरक में 2400 करोड़ रूपये के लगभग जो राशि किसानों के बोनस के लिये दी गयी है उसके समर्थन में हैं कि विरोध में हैं यह स्पष्ट करना चाहिए । बाकी किस्सा-कहानी तो चलते रहेगा । आज मालूम नहीं क्यों वे भाषण देने की बजाय चिल्ला रहे हैं ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप 5 सालों का बोनस दीजिये न, हम तो चाहते हैं । हम भी किसान पुत्र हैं और मैं खुद किसान हूं । मैं भी चाहता हूं कि हमको लाभ मिले मगर आप चुनावी लॉलीपाप क्यों देना चाहते हैं ? आप 5 साल का बोनस दीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपसे बड़े किसान श्री जयसिंह अग्रवाल जी हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- आपने जो कहा था कि 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे उसका क्या हुआ ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- श्री मरकाम भाई, बोनस मिलेगा तो लोगे कि नहीं लोगे यह बताओ । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- देखिये वह पैसा हमारा पैसा है ।

श्री राजेश मूणत :- जितने कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जब सरकार बोनस देगी तो लेंगे कि नहीं लेंगे ? यह बोल दीजिये कि बोनस नहीं लेंगे । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पैसा हमारी जनता का पैसा है । इस प्रदेश की जनता का पैसा है, हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा है कि हम टैक्स के रूप में जमा करते हैं, सरकार के खजाने में जमा होता है वह हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमको लेने में कोई एतराज नहीं है । माननीय मंत्री जी, आप इस चीज को क्यों भूल रहे हैं कि वह सरकार का पैसा नहीं है । सरकार का पैसा नहीं है बल्कि हमारा पैसा है । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- बहुत अच्छे ।

श्री अरूण वोरा :- श्री मूणत जी, कांग्रेस ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है । कांग्रेस किसान के साथ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- इस प्रदेश की आम जनता का पैसा है, जिसे टैक्स के रूप में जमा करता है ।

श्री देवजी भाई पटेल :- [XX][1]

श्री मोहन मरकाम :- हम वह पैसा क्यों नहीं लेंगे वह हमारी मेहनत का पैसा है ।

अध्यक्ष महोदय :- [XX] इसको हटा देंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार कहती है चूंकि पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 1350 किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन आज सरकार उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है ? आज लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलित हैं । आज उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है । आज मैं सबसे बड़ी बात, यदि मैं बस्तर की बात कहूं तो सरकार ने मक्का समर्थन मूल्य 1450 रूपये में खरीदने की बात की है, लैम्पसों में, सोसायटियों में बड़े-बड़े फ्लेक्स टांगे गये हैं कि हम 1450 रूपये में समर्थन मूल्य खरीदेंगे लेकिन आज बस्तर में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है, मेरे विधानसभा में होता है लेकिन 700-800 रूपये में किसान बेचने के लिये मजबूर है तो सरकार जो किसानों की आय को दुगूना करने की बात कर रही है । वह उसके बारे में क्यों बात नहीं करती ? आज सबसे ज्यादा हमारे कर्मचारी, हमारे व्यापारी अर्थात् हमारा हर वर्ग आंदोलित है उनके लिये इस अनुपूरक बजट में क्यों प्रावधान नहीं किया गया है ? डेढ़ लाख अनियमित कर्मचारी आज लगातार आंदोलित हैं, उनके लिये इस अनुपूरक बजट में क्यों प्रावधान नहीं किया गया ? आज लगातार चाहे वह रसोईया हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमें अपनी सेवायें देते हैं उनके ऊपर इस सरकार के द्वारा एस्मा लगाकर जेल में ठूंस दिया जाता है । दुर्भाग्यजनक की बात है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के ऊपर एस्मा लगाकर उनको अंदर किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है । छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, नर्स बहनें हैं, आज इस सरकार के अत्याचार- अन्याय के कारण लगातार सभी परेशान हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

[1] **(XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।**

श्री नवीन मारकण्डेय :- श्री मोहन भैया, आज के पेपर में आपने पढ़ा न कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि हुई है ।

मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि इस छत्तीसगढ़ सरकार के 93,000 करोड़ का जो बजट है उसके बाद भी **सी.एन.जी.ए.** की रिपोर्ट हमने देखी है जिसे सरकार ने पेश नहीं किया । लगभग 20,000 करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ सरकार खर्च नहीं कर पा रही है फिर इस अनुपूरक में और पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ी, जो मेन बजट में हमने 93,000 करोड़ लगभग इस सरकार को खर्च करने के लिये दिया है उसके बाद भी 20,000 करोड़ रूपये वर्तमान सरकार खर्च नहीं कर पा रही है ।.................जारी

.............श्री यादव

यादव\12-09-2018\a14\11.20-11.25

..........(जारी श्री मोहन मरकाम) :- हमने इस सरकार को मेन बजट में लगभग 93000 करोड़ को खर्च करने के लिए दिया है, उसके बाद भी वर्तमान सरकार 20000 करोड़ रूपए खर्च नहीं कर पा रही है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा करेंगे तो अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों की जो जायज मांगे हैं, उन मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 2014 के पहले भाषण में कहा था कि पांच साल का बोनस देंगे । आप पांच साल का बोनस क्यों नहीं देते? आखिरी साल में किसानों को ठगने के लिए, लालीपॉप देने के लिए यह सब क्यों कर रहे हैं

? मैं चाहता हूं कि किसानों को 2100 रूपए समर्थन मूल्य और पांच साल के 300 रूपए बोनस देने की घोषणा करें । माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ.रमन सिंह जी को एक किसान होने के नाते प्रदेश के लाखों किसानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं । (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय किया कि धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ ही किसानों को 300

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

रूपए क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाएंगे । इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए जहां सरकार को मैं बधाई देता हूं, वहीं किसानों की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में आज हमारे साथियों ने जो [XX] [2] प्रदेश की जनता के सामने दिखाई है, मैं उन विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह [XX] करने की बजाए...।

अध्यक्ष महोदय :- [XX] हटा देंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX] संसदीय शब्द है ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, सरकार [XX] [3] कर रही है । शीतकालीन सत्र भी था, वर्षाकालीन सत्र भी था, उसमें क्यों पास नहीं करवा लिया ? आज जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी शब्द को विलोपित करना आपका विशेषाधिकार है, पर मेरी जानकारी में [XX] शब्द संसदीय शब्द है, असंसदीय शब्द नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आसंदी तय करता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, यह तय करता है । यह तो आपका विशेषाधिकार है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको हटा दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथियों ने आज एक नाटक का प्रदर्शन किया है । नाटक यह है कि यह सरकार किसानों को किसी भी रूप में बोनस न दे पाए । जिस दिन सरकार ने, कैबिनेट ने निर्णय किया कि हम किसानों को बोनस देंगे तो इनके नेताओं का समाचार पत्रों में स्टेटमेंट आया कि सरकार चुनाव की दृष्टि से बोनस दे रही है ।

[XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार पहली बार बोनस दे रही है ?

श्री अजय चंद्राकर :- शर्मा जी, आप एक विषय भाषण में जरूर शामिल करिए हम सरकार खर्चे में पंजाब भेज देते हैं, कांग्रेस के पास एक मात्र राज्य है, वहां कितनी धान खरीदी हो रही है और कितना बोनस दे रहे हैं ? इसका अध्ययन कर लें । मिलीजुली कुश्ती में कर्नाटक में हैं, वहां क्या हो रहा है, यह देख लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ.रमन सिंह की सरकार बनने के पश्चात् किसानों को इन पन्द्रह वर्षों में नौ से दस वर्ष तक बोनस मिला है । हमने पहले 150 रूपए क्विंटल बोनस दिया, फिर 180 रूपए क्विंटल बोनस दिया, फिर 250 रूपए क्विंटल बोनस दिया और चौथी बार हम छत्तीसगढ़ के किसानों को 300 रूपए क्विंटल के हिसाब से बोनस देने जा रहे हैं । इस बड़े कार्य के लिए, किसानों को बोनस देने के लिए विपक्ष के साथियों को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए था तो उसके बजाए इनको लग रहा है............(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\a15\.-.5

जारी.. श्री शिवरतन शर्मा :- धन्यवाद देना चाहिए था तो उसके बजाय इनको लग रहा है कि सरकार राजनीति कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया और छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के 53 साल पूर्व 47 साल तक छत्तीसगढ़ और पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में इनकी सरकारें थीं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् भी छत्तीसगढ़ में शुरू के तीन साल इनकी सरकार थी। आज मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश में आपकी सरकार थी तो आपने किसानों के हित में कौन सा काम किया? आपने किसानों का भला हो उसके लिए क्या किया? विरोध करने के बजाय अपने गिरेबान में झांककर देखिए। सिर्फ 2 वर्ष के बोनस का जो रिकार्ड है कि वर्ष 2016 में 13 लाख 35 हजार किसानों को 2112 करोड़ रूपये का बोनस दिया गया, वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों को 1706 करोड़ 42 लाख रूपये का बोनस दिया गया। सिर्फ दो वर्ष में सरकार ने 3818 करोड़ का बोनस किसानों को

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया है। आज प्रदेश के किसानों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि केन्द्र और प्रदेश दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी इन दोनों ने मिलकर तय किया है कि वर्ष 2022 तक हम ये स्थिति निर्मित करेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जो वर्तमान इन्कम है उसको हम डबल कर सकें और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कुछ निर्णय जो केन्द्र की सरकार ने किसानों के हित में पूरे देश के लिए अभी किए हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने वह निर्णय किसानों के हित में केन्द्र में हमारी सरकार बनने के पहले किए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय अगर दुगुनी करना है तो सरकार को तीन स्थिति पर काम करना पड़ेगा। पहला विषय है कि किसानों की उत्पादन लागत कम हो, दूसरा विषय है कि किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिले और तीसरा विषय है कि किसानों के खेत को सिंचाई हेतु पानी मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीनों विषय में हमारी सरकार ने काम किया है। उत्पादन लागत कम हो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश का किसान कभी भी कृषि कार्य करता है तो कृषि के लिए ऋण लेता है। छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार बनने के बाद पहली बार किसानों को पिछले पांच वर्षों से बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जा रहा है। डॉ. रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले किसान ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों से जब अल्पकालीन ऋण लेता था तो उनको 16 रूपये सैकड़ा ब्याज लगता था। उसे कम करते गये और 16 से घटाकर 14, 12, 9, 7, 6, 3 और 1 प्रतिशत करने के बाद पिछले 6 वर्षों से हम किसानों को लगातार बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और इस ऋण उपलब्ध कराने का लाभ मिला है। वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ का किसान सहकारी समितियों के माध्यम से जो कर्ज लेता था वह पूरे छत्तीसगढ़ में 125 करोड़ रूपये का कर्ज लिया जाता था और पिछले वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ के किसानों ने जो कर्ज लिया वह 3500 करोड़ रूपये था और इस वर्ष सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 4200 करोड़ रूपये तक का कर्ज किसानों को देंगे और इस 4200 करोड़ रूपये के कर्ज देने के लिए सरकार ने 184 करोड़ रूपये के ब्याज अनुदान की व्यवस्था की है। (मेजों की थपथपाहट) इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस सरकार से किसानों की कर्ज लेने की सीमा बढ़ी है, कर्ज लेने वाली किसानों की संख्या बढ़ी है और डिफाल्टर किसानों की संख्या घटी है। वर्ष 2003 के पहले

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्थिति यह होती थी कि सहकारी समितियों से किसान जो कर्ज लेते थे, कर्ज नहीं पटा पाते थे, किसानों की जमीन नीलाम की जाती थी। वर्ष 2003 के बाद आज 2015 तक सरकार ने यह स्थिति निर्मित की है कि आज अगर किसान कर्ज लेता है तो कर्ज पटाने वाले किसानों की संख्या 90 प्रतिशत से ज्यादा है। (मेजों की थपथपाहट) किसान डिफाल्टर कम हुए हैं। सरकार ने किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं की, किसी को कुर्की का सामना नहीं करना पड़ा, ये सरकार का किसान के हित में बड़ा काम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन लागत कम करने के लिए जहां सरकार ब्याज में सब्सिडी दे रही है वहीं सरकार ने मिट्टी परीक्षण का काम पूरे देश में किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 43 लाख किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण हुआ है ताकि किसान जो फर्टीलाईजर का उपयोग करता है उसे वह अपनी मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार कर सके। किसानों की उत्पादन लागत कम करने के लिए यह सरकार ने व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान आधुनिक कृषि कर सके इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, छत्तीसगढ़ में 13 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना यह सरकार का किसानों के हित में बड़ा काम है। अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा उत्पादन लागत ..

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\a16\11.30-11.35

जारी.............श्री शिवरतन शर्मा :-

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय उत्पादन लागत का आता है । उत्पादन लागत कम करने के पश्चात् किसान के उत्पादन का वाजिब दाम माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने तय किया कि किसान जो अनाज उत्पादित करता है हम उसके उत्पादित अनाज का, उत्पादन लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य घोषित करेंगे ? इस वर्ष नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने धान का समर्थन मूल्य घोषित किया है । इतिहास में पहली बार सरकार ने एक साथ 200 रूपए मूल्य की वृद्धि की है (मेजो की थपथपाहट) । अध्यक्ष महोदय, किसान मोटा धान बेचने जाएगा 1750 रूपए क्विंटल उसका धान बिकेगा, किसान बारिक धान बेचने जाएगा 1780 रूपए क्विंटल उसका धान बिकेगा और उसमें 300 रूपए क्विंटल बोनस जोड़ दिया जाए तो 2100 रूपए के आसपास किसान को धान का समर्थन मूल्य मिलेगा (मेजो की थपथपाहट) ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, काम करना मुश्किल होता है । मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपको 53 साल का अवसर मिला था, ज़रा बताएं कि किसान को बिना ब्याज के कर्ज देने से किसने रोका था ? आपको 53 साल का अवसर मिला था किसान की उत्पादन लागत के हिसाब से समर्थन मूल्य बढ़ाने से आपको किसने रोका था, ज़रा बताएं ? आपको 53 साल का अवसर मिला था, किसान का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने से किसने रोका था, जरा बताएं ? माननीय अध्यक्ष जी, 2000 से 2003 तक इनकी सरकार थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, रोका किसी ने नहीं था, इनकी समझ में नहीं आया था कि ऐसा हो सकता है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- समझदार लोग सामने बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत समझदार लोग ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- शर्मा जी, आज़ादी के बाद कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस ने ही तो काम किया, आप उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं, अन्यथा यहां कैसे खड़े होते ? खाए पिए हो, तब तो यहां तक पहुंचे हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, माननीय वोरा जी, आप आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास पढ़ लो, कृषि प्रधान देश की दुर्दशा करने में सबसे बड़ी भूमिका रही है तो आपकी पार्टी के नेताओं की रही है (शेम शेम की आवाज) आप इतिहास पढ़ो ।

श्री अरूण वोरा :- कांग्रेस ने कृषि नीति बनाई, आप इतिहास पढ़िये ।

श्री देवजी भाई पटेल (धरसीवां) :- वोरा जी, आप ठीक कह रहे हैं । शायद यह पाप आपने नहीं किया होता तो हम यहां नहीं पहुंचते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [4](xx)

अध्यक्ष महोदय :- हटा दीजिएगा ।

---

[4] **(xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको काम करने का पर्याप्त अवसर मिला । लेकिन मन में किसानों के हित में काम करने का भाव हो, मन में किसानों की उन्नति का भाव होता तो ये काम करते, लेकिन इनके मन में तो नारा दो, चुनाव जीतो और पांच साल जनता को भूल जाओ । इस भाव से काम करने वाले ये लोग हैं । इन्होंने न कभी किसानों का हित किया है और न ही किसानों का हित कभी कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, 2003 में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार बनने के बाद, किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें, छत्तीसगढ़ का किसान स्वाभिमानी, स्वावलम्बी और सम्मान का जीवन जी सके इसके लिए सरकार ने काम किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, आज मोतीलाल जी भी किसान के ड्रेस में हैं। रेशम और बुनकर उद्योग को भी एलाइट सेक्टर में गिन लेते हैं, बुनकर सोसायटियों का कितना कर्जा माफी हुआ, कितना विस्तार हुआ, उन्हें कितना अनुदान मिला, उन्हें कितना बढ़ाया गया, अपने भाषण में यह भी मोतीलाल जी को बता देना।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी विधान सभा आ रहे थे, पुलिस ने हमारी सायकल को रोका है, अध्यक्ष महोदय, हमारे विशेषाधिकार का हनन् हुआ है । यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम विधायकों को विधान सभा आने से रोक रही है और यहां पर किसानों की बात करते हैं । (व्यवधान) । विधायकों को आने नहीं दे रहे हैं ।

श्री दीपक बैज (चित्रकोट) :- जब माननीय मुख्यमंत्री जी सायकल से आ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हम लोगों को वहां एक घंटा रोका गया, अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य यहां किसानों की बात करते हैं । जब हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं और यह किसानों के समर्थन मूल्य की बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संतराम जी, अगर इस प्रकार से कुछ हुआ है तो उसकी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं ।

श्री संतराम नेताम :- हम आपको अवगत करा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

-- श्री अग्रवाल --

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अग्रवाल\12-09-2018\a17\11.35-40

......(व्यवधान)......

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हम आपको अवगत करा रहे हैं।..(व्यवधान)..

श्री मोहन मरकाम :- अवगत करा रहे हैं ।

श्री दीपक बैज :- आपकी जानकारी में ला रहे हैं ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हम आपको अवगत करा रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, हम उन किसानों के लिए आते हैं, जो किसानों का मक्का खरीदी नहीं कर रहे हैं, 2100 रूपये नहीं कर रहे हैं, उस बात को लेकर हम सायकल में आ रहे थे, वहां पर पुलिस ने हमको एक घंटे तक रोका था । हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसके बाद आपका नम्बर है ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, सब विधायकों को रोकते हैं तो किसानों के साथ कैसे करेंगे । महंगाई की मार झेल रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठग है । ......(व्यवधान)......

श्री अरूण वोरा :- आज अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिए। आज अघोषित रूप से एमरजेंसी तो नहीं लगा दिए...(व्यवधान)...

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, ये सरकार विधान सभा सचिवालय आने से हमें रोकना चाहती है, ताकि हम किसानों की बात न करें, वहां की जनता की बात रख रहे हैं, हम लोग सायकल में आ रहे थे तो हमको यहां आने से रोका जा रहा है । हमें क्यों रोका जा रहा है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं । .....(व्यवधान)..... हम लोग चार चक्का से नहीं, सायकल से आ रहे थे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को रोका गया, हम लोग वहां एक घंटे बैठे रहे । हम लोग अपनी बात न रख पाए, इसलिए हम लोगों को रोका जा रहा था ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, एक घंटे तक रोका गया, सायकल से हम लोग आ रहे थे ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को एक घंटा रोका गया, यहां आने नहीं दिया जा रहा था ......(व्यवधान)......

अध्यक्ष महोदय :- अभी जितने माननीय विधायक खड़े हैं, सबका नाम इसके बाद है । आपको बोलने के लिए पूरा मौका मिलेगा, आप आराम से अपनी बात रखिए और किसी प्रकार से आपका विशेषाधिकार हनन हुआ है तो उसकी जानकारी आपने दे दी, मैंने सुन लिया, नोट कर लिया है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, सायकल में आने के कारण विलंब हो गया । हम सायकल में आ रहे थे ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, जब चार चक्का आ सकता है, हम तो सायकल से आ रहे थे तो विधान सभा में जगह भी कम लगता और सुविधा भी होती। उसके बाद ये सरकार हम लोगों को रोकने का काम कर रही है ।...(व्यवधान)..

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कांग्रेस को सायकल का सहारा लेना पड़ रहा है ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात है, हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ है । ......(व्यवधान)......

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कांग्रेस को सायकल के सहारे की जरूरत पड़ रही है ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है इसलिए हम लोग लगातार सायकल से सचिवालय आ रहे थे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, ये सरकार महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है इसलिए हम लोग सायकल से आ रहे थे । पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत बढ़ा चुकी है इसलिए हम लोग सायकल से आ रही थे तो सरकार हमें रोक रही थी ।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, अपनी बात बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आज मैं विधान सभा आ रहा था तो विधान सभा आने में 8 से 10 मिनट की देरी मुझे सिर्फ इसलिए हुई कि मेरी गाड़ी के सामने आदरणीय दीपक बैज जी, संतराम नेताम जी और इनके साथ कोई एक और साथी था, तीनों सायकल से विधान सभा आ रहे थे और इनके पीछे-पीछे मैं आ रहा था । एक घटना की जानकारी मैं आपको और दे देता हूं । मुझे अभी लोगों ने बताया कि जब इनके नेता बैलगाड़ी में बैठ रहे थे तो बैल भी बिदग गया था, बैल भी इनके विरोध में था ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, जब हमारे नेता बैलगाड़ी में बैठ गए थे तो बैलगाड़ी 120 की स्पीड से दौड़ रही थी ......(व्यवधान)......

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, वह इसलिए कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि बैलगाड़ी और सायकल में आ रहे हैं और हम सायकल में बिल्कुल किनारे में चल रहे थे । माननीय सदस्य सदन में असत्य कथन कह रहे हैं । हम तो सायकल में साईड में चल रहे थे ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन भैया, बैल बिदकता क्यों है, ये बताइए ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, बैल आप लोगों के कारण बिदक रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता तो जनता, बैल और किसान भी खुश नहीं हैं । आपके काम से बैल भी संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा था । इनको 53 साल अवसर मिला, किसानों के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 15 वर्षों से ये विपक्ष में बैठ रहे हैं और आने वाले 10-20 वर्ष तक और बैठेंगे । कुछ विषय पर बार-बार चर्चा में इनकी ओर से आता है । मैं विषय आपके सामने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रखना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने (XX)[5] शब्द को विलोपित कर दिया था, आज इन्होंने नाटक किया है चाहे सायकल से आने का, चाहे बैलगाड़ी से आने का । मैं खाली उनको एक आईना दिखाना चाहता हूं ...

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी तो रमन सिंह जी और बृजमोहन अग्रवाल जी सायकल में विधान सभा आ रहे थे, जब महंगाई और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे । (हंसी)

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, उस समय माननीय रमन सिंह जी और बृजमोहन अग्रवाल जी भी सायकल से आये थे, उस समय भी उन्होंने नाटक किया था क्या । (हंसी) उस समय नाटक था क्या, यह भी बात बता दीजिए ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- वे लोग भी सायकल में चलकर आ रहे हैं, बैलगाड़ी से चलकर आ रहे थे ।

श्री दीपक बैज :- अध्यक्ष महोदय, बैलगाड़ी से और सायकल से आ रहे थे, वह नाटक हो गया, उस समय क्या था, ये बता दीजिए ।

श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\a18\11.40-11.45

श्री मोहन मरकाम :- माननीय शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सायकल में आये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि एक अवसर आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमण्डल के सारे सदस्य और सारे विधायक महंगाई के विरोध में सायकल से विधान सभा आये थे। मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। आज इन्होंने महंगाई के विरोध में जो नाटक किया है और विशेष कर डीजल और पेट्रोल में महंगाई का मामला आया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में यूपीए की सरकार बनी। 2004 में जब यूपीए की

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकार बनी तो पेट्रोल का भाव 40 रुपये 96 पैसा लीटर था और मई, 2014 में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी तो पेट्रोल का भाव 80 रुपये 16 पैसे लीटर था और आज 5 वर्षों बाद पेट्रोल का भाव 88 रुपये 26 पैसे लीटर आज की तारीख में है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय कच्चे तेल की कीमत 135 डॉलर प्रति बैरल थी, आज कच्चे तेल की कीमत कहां पहुंच गयी है, यह तो बता दीजिए? उस रेट के हिसाब से आज कीमत आधी होनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो डीजल का भाव 28 रुपये 65 पैसे लीटर था और 2014 में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो डीजल का भाव था 66 रुपये लीटर और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज डीजल का भाव 77 रुपये लीटर है। मैं आपके माध्यम से इन्हीं से पूछना चाहता हूं।

श्री दीपक बैज :- माननीय शर्मा जी, उस समय कच्चे तेल की कीमत क्या थी, जरा वह भी बता दीजिए?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय कच्चे तेल की कीमत 135 डॉलर प्रति बैरल थी।

अध्यक्ष महोदय :- यह जो चर्चा है, इसमें अनुपूरक पर तो कोई बात नहीं हो रही है। आप लोग अनुपूरक पर बात कीजिए। जो अनुपूरक का विषय नहीं है, उस पर आप बात कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सदस्य असत्य कथन कर रहे हैं।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से बोनस की घोषणा हुई है, कांग्रेस बिदक गये हैं ।

लोक निर्माण मंत्री (श्री राजेश मूणत) :- 48 साल में सम्पन्न किसानों के बारे में थोड़ा सा बाता दीजिए?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको शर्मा जी से यही आपत्ति है कि शर्मा जी सच नहीं कह रहे हैं। गीता पर हाथ रखकर बोलें कि जो आप कह रहे हैं, वह सच है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- यह सदन बहुत चिंतित है और यह जानना चाहता है कि बैल के बिदकने से कोई केजुवल्टी तो नहीं हुई ? मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे उनको देखना पड़ेगा।

श्री अरूण वोरा :- बैल के बिदकने से किसी को कुछ नहीं हुआ है।

श्री दीपक बैज :- माननीय मंत्री जी, आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, दुर्ग-भिलाई में 42 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद मंत्री जी गंभीर नहीं है। माननीय मंत्री जी, पहले आप जनता की चिंता कीजिए। उसके बाद विधायकों की चिंता कीजिए। पहले डेंगू की चिंता कीजिए। उसके बाद आप विधायकों की चिंता कीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, भिलाई में 42 लोगों की मौत हो जाती है, आप उनकी चिंता करिये। आप इतने गंभीर हैं तो भिलाई-दुर्ग में डेंगू से लगातार मौतें हो रही हैं, आप उसकी चिंता कीजिए, डेंगू की चिंता कीजिए, हमारी चिंता बाद में करना। इस सदन में आपको हँसी आती है ? माननीय मंत्री जी, अगर आप इतने गंभीर हैं तो भिलाई-दुर्ग और राजनांदगांव में 42 लोगों की जो मौत हुई है, उसकी चिंता करिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बैल के बिदकने से कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन भिलाई में डेंगू से 42 लोग मर चुके हैं और 4 हजार लोग भर्ती हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप उनकी चिंता करिये।

श्री मोहन मरकाम :- आप उनकी चिंता करिये, आपको इस सदन में हँसी आ रही है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि बैल के बिदकने से कोई घायल नहीं हुआ पर विचार का प्रश्न यह है कि बैल बिदका क्यों ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुपूरक का विषय है, मैं उस अनुपूरक के विषय पर ही अपनी बात कर रहा हूं। जो महंगाई का जिक्र किया, हमारे विपक्ष के साथियों ने जो आज किया, उस परिप्रेक्ष्य में मैंने डीजल के 2013-2014 और 2004 से मैंने तुलना की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं। ...

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जारी श्रीमती सविता

सविता\12-09-2018\a19\11.45-11.50

जारी श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ, वे लिखने-पढ़ने में बहुत होशियार हैं वे पूरे समय लिखते-पढ़ते हैं, जरा गणना कर के देख लें कि यू.पी.ए. की गवर्नमेंट में डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने की दर क्या थी ? और एन.डी.ए. की गवर्नमेंट में डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने की दर क्या है ? तो वे ज्यादा अच्छे ढंग से अपने साथियों को समझा सकेंगे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो आपके दल के लोग वाट्सअप में चला चुके हैं और खूब ट्रोल हो चुके हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने का एक विषय आया, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में वर्ष 2014 में खाद्यान्न पदार्थों के रेट क्या थे ? और आज खाद्यान्न पदार्थों के रेट क्या हैं ? राहर की दाल 200 रूपये किलो बिकती थी और आज खुले बाजार में 55 रूपये किलो में मिल रही है।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 250 रूपये बिक रही थी, आप टमाटर और प्याज के रेट भूल गये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही 250 रूपये पहुँच गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज खुले बाजार में राहर दाल 55 रूपये किलो में मिल रही है। 45 रूपये किलो शक्कर बिकती थी, आज खुले बाजार में 35 रूपये किलो में शक्कर मिल रही है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा आया था कि प्याज के भाव 80 रूपये किलो हो गए थे, आज खुले बाजार में 15 रूपये प्याज के भाव है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी, एक समय ऐसा आया था जब प्याज की वजह से आपकी सरकार गिर गई थी। आप उस दिन को याद करिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा दिन भी आया था जब प्याज के कारण आपकी सरकार गिर गई थी। ये क्यों भूल रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई न कोई नाटक करना पड़ेगा और आज ये नाटक हमारे कांग्रेस के साथी कर रहे हैं, पर मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है अपने राजनीतिक निर्णय बहुत सोच समझकर करती है और उनके राजनीतिक निर्णय के चलते ही आप लोकसभा में 417 से 44 में आ गये और विधान सभा में 67 से 38 पर आ गये। ये हमारे देश और प्रदेश के मतदाताओं की जागरूकता है (मेजों की थपथपाहट) और आने वाले नवम्बर के महीने में ये नाटक का परिणाम जनता आपको देगी। यहां आप जितने हो, शायद आप लोग इससे आधे हो जाओ, आपके नाटक का परिणाम ये होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सिर्फ धान की फसल के लिए कोई काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने किसानों की चारों तरफ उन्नति हो, इसके लिए सबसे पहले मैं सिंचाई सुविधा का जिक्र करना चाहूंगा। डॉ. रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता 13 लाख, 28 हजार हेक्टेयर की थी और वर्तमान में 20 लाख, 88 हजार हेक्टेयर की है। वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में पम्प कनेक्शन 1 लाख के आसपास थे और आज छत्तीसगढ़ में किसानों के सिंचाई पम्प कनेक्शन की संख्या 4 लाख से ऊपर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 लाख, 19 हजार अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को सरकार पूरी तरह से मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही है ताकि किसान उन्नति कर सके। सरकार ने किसानों के हित में 43 लाख सोलर पम्प लगवाए गए हैं जो लागत 3-4 लाख रूपये की आती है वह 7 हजार से 20 हजार रूपये के बीच किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करवाया जा रहा है और बाकी किसानों के लिए विद्युत शुल्क के रियायत देने के लिए किसानों को फ्लैट सिस्टम दिया गया है, एक पम्प है तो आप 100 रूपये प्रति हार्स पॉवर के हिसाब से कनेक्शन ले लें, दूसरे पम्प पर 200 रूपये प्रति हार्स पॉवर के हिसाब से कनेक्शन लें, फिर दो के बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जितने पम्प हों, उसमें 200 रूपये प्रति हार्स पॉवर के हिसाब से पम्प कनेक्शन देने की व्यवस्था सरकार ने की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान जो सर्टीफाईड बीज का उपयोग करता है, किसान जो फर्टीलाईजर का उपयोग करता है इसके उपयोग में जो बढ़ोत्तरी हुई है ये किसानों की उन्नति को प्रदर्शित करता है । छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003-2004 में किसानों ने 6 लाख, 87 हजार मिट्रिक टन उर्वरक का उपयोग किया था और वर्ष 2016-2017 में किसानों ने 13 लाख, 96 हजार मिट्रिक टन उर्वरक का उपयोग किया है, जो 103 प्रतिशत की वृद्धि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों ने परम्परागत खेती से ऊपर उठकर उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन की ओर भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है और उसके चलते जो उद्यानिकी का रकबा है जो वर्ष 2003-2004 में 1 लाख, 64 हजार, 683 हेक्टेयर था ....

......जारी श्री चौधरी

चौधरी\12-09-2018\b10\11.50-11.55

पूर्व जारी.. श्री शिवरतन शर्मा :- उसके चलते जो उद्यानिकी का रकबा है, वर्ष 2003-04 में 1 लाख 64 हजार 683 हेक्टेयर था, वह बढ़कर 8 लाख 30 हजार 799 हेक्टेयर हो गया, लगभग 400 गुना वृद्धि है। वर्ष 2003-04 में उत्पादन 14 लाख 16 हजार 221 मीट्रिक टन था, वह बढ़कर 98 लाख 33 हजार 933 मीट्रिक टन हो गया है। फलों के उत्पादन का रकबा भी बढ़ा है, 36,803 हेक्टेयर से बढ़कर लगभग ढाई लाख हेक्टेयर में फलों की खेती किसान कर रहे हैं। सब्जी की खेती का रकबा भी बढ़ा है। 1 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 4 लाख 63 हजार हेक्टेयर पर सब्जी की खेती किसान कर रहे हैं। किसान लगातार उत्पादन कर रहे हैं। सरकार किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। उसके पश्चात भी जो मंडी प्रांगण में अनाज बिकने आता है उसकी भी मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। 2003 में हमारे छत्तीसगढ़ की मंडियों में जो अनाज बिकने आया, वह 38 लाख 2300 टन था। वर्ष 2016-17 में जो अनाज बिकने आया, वह 99 लाख 38,893 टन था।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मानानीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो दूसरा बड़ा काम किया है, चना के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। दलहन की समस्या रहती थी, दलहन उत्पादन में हमारी सरकार को पुरस्कार मिला, धान उत्पादन में बढोत्तरी के लिए हमको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय शर्मा जी, आजकल चना का चखने में उपयोग हो रहा है। उसका कोई सदुपयोग ही नहीं हो रहा है। आजकल जो गांव-गांव में दारू बिक रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब ऐसा है कि गांव में जो दारू बिक रही है उसको डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने नियंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ में लोग दारू पिएं, ये काम तो आपकी सरकार ने किया। **(XX)**[6] ने एक नियम बनाया कि जो अनुसूचित ब्लाक हैं वहां 5 लीटर शराब बनाने की छूट रहेगी। मोहन मरकाम जी ये आपकी सरकार ने नियम बनाया था।

अध्यक्ष महोदय :- नाम हटा दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर हिम्मत है तो आप अपनी सरकार के प्रस्ताव के विरोध में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत कर दो। सरकार उस पर विचार कर लेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चना का उत्पादन बढ़ा।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ बस्तर में आदिवासियों को देशी दारू बनाने के लिए छूट थी, आप तो गांव-गांव में अंग्रेजी दारू बिकवा रहे हैं। उसके साथ आप चना भी बिकवा रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेताओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, यहां चर्चा में भाग नहीं लेने देना चाह रही है। यह दुर्भाग्यजनक बात है। .. (व्यवधान)..

श्री संतराम नेताम :- यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार..। .. (व्यवधान)..

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

[6] **(XX)[6] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेताओं को रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है।.. (व्यवधान).. बहुत लज्जा की बात है। हमारे नेताओं को सदन में आने नहीं दे रहे हैं।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार तानाशाही है। हमारे विधायकों को रोका गया है। .. (व्यवधान)..

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके ध्यान में इस बात को लाना चाह रहा हूं। वरिष्ठ नेताओं को, हमारे विधायकों को, माननीय भूपेश बघेल जी को, धनेन्द्र साहू जी को, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी को बाधित किया गया है। कौन सा नियम है, हमें बता दिया जाय कि फलाने ही वाहन से प्रवेश किया जा सकता है। यदि पास की बात है तो आप सायकिल का पास दिलवा दीजिए। अगर बैलगाड़ी की बात है तो बैलगाड़ी का पास दिलवा दीजिए। दूसरे वाहन की बात है तो पास दिलवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, उनको आने से बाधित न किया जाये। मेरा आपसे निवेदन है।

श्री दीपक बैज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर ये सरकार हमारे विधायकों को रोकना चाह रही है ताकि जनता की बात को हम लोग यहां न रख सकें। ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर बाधित किया जा रहा है।

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\b11\11.55-11.60

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोगों का नाम यहां पर है। अनुपूरक अनुदान की चर्चा में सब लोग भाग लेंगे। उस समय आप लोगों को जो-जो बात बोलना है, बोल लेंगे। क्योंकि हर बार खड़ा होकर के उसी-उसी बात को बोल रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जब आप लोगों का नंबर आयेगा तो आप लोग विस्तार से बोल लेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि ....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता को बुला लिया जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि उनका नंबर आ रहा है, उनको बुलवा लिया जाये। ......(व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- उनको जानबूझकर रोका जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक हमारे साथी लोग, जो दुपट्टा लगाकर आते थे, उसका कलर कुछ दूसरा रहता था और जो लगाकर आये हैं, उसका कलर दूसरा है।

श्री दीपक बैज् :- यह किसानों का कलर है। आप इसको नहीं समझ पायेंगे। जब आप खेत में जायेंगे तब समझेंगे। ये किसानों के कलर को क्या समझेंगे ? शर्मा जी, यह किसानों का कलर है। आपको समझ में नहीं आयेगा कि यह किसानों का कलर है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, ये किसान-किसान की बात कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे कांग्रेस के साथियों में किसान की परिभाषा में हमारे आदरणीय गुरूमुख सिंह होरा जी और जय सिंह अग्रवाल जी जैसे किसान तो नहीं हैं ? ....(व्यवधान)

श्री गुरूमुख सिंह होरा :- शर्मा जी, आपको जानकारी नहीं होगी कि मेरी कितनी खेती है। मेरी डेढ़ सौ एकड़ जमीन है। ....(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारे माननीय केदार कश्यप जी, किसान हैं या नहीं, यह बता दीजिये ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सिर्फ धान की खेती के विकास के लिए काम नहीं किया है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी किसान हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारी सरकार के कार्यकाल में चना का उत्पादन बढ़ा है, चना का रकबा बढ़ा है। उसके लिए हमारी सरकार ने 1500 रूपये प्रति एकड़क का अनुदान भी दिया है। लगभग 118 करोड़ रूपये का अनुदान चना के उत्पादन के लिए दिया है। माननीय अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में गन्ना का उत्पादन बढ़ा है। लगभग 34 हजार हैक्टेयर में गन्ने का उत्पादन हमारे किसानों ने किया है और गन्ना उत्पादन में भी सरकार ने लगभग 15 करोड़ रूपये का बोनस किसानों को दिया है।

समय

11.59 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए)**

मानननीय सभापति जी, हमारे देश का किसान, हमारे प्रदेश का किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, इसके लिए प्रदेश और केन्द्र की सरकार लगातार काम कर रही है। किसान की खेती कभी ज्यादा पानी से खराब होती है तो कभी अवर्षा के चलते अकाल का सामना करना पड़ता है। डॉ0 रमन सिंह की सरकार ने पहली बार भू-राजस्व संहिता में परिवर्तन करके सूखे को शामिल किया। ....जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\b12\12.00-12.5

जारी....श्री शिवरतन शर्मा .....पहली बार भू-राजस्व संहिता में परिवर्तन करके सूखे को शामिल किया और इस साल 96 तहसीलों को 555 करोड़ रूपये का सूखा राहत प्रदान किया गया है । माननीय सभापति जी, नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू हुई । प्रधानमंत्री फसल बीमा में सिर्फ पिछले वर्ष का आंकड़ा मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, पिछले वर्ष में हमारे यहां के 12 लाख 98 हजार 602 किसानों ने बीमा कराया । 19 लाख 82 हजार 36 हेक्टेअर का बीमा था । किसानों ने जो बीमे का प्रीमियम दिया था, वह राशि थी 128 करोड़ 8 लाख रूपये की । माननीय सभापति जी, वर्ष 2017 में बीमा कंपनियों ने किसानों को जो मुआवजा दिया है, वह राशि है 1293 करोड़ 92 लाख रूपये है । माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के नाम से जब इनकी सरकारें थी......

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति जी, फसल बीमा के रूप में 100 रूपये और 50 रूपये का चेक दे रहे हैं । माननीय सभापति जी, 100 रूपये और 50 रूपये का फसल बीमा दे रहे हैं, यह क्यों भूल रहे हैं ? शर्मा जी आपके नॉलेज में होगा, आपके क्षेत्र में है, रायपुर में है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, जब इनकी सरकारें थी, तो भी फसल बीमा के नाम पर किसानों की राशि सहकारी समितियों में कर्ज लेते समय काट ली जाती थी । कभी भी किसी भी किसानों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि बीमा की शर्तें ऐसी जोड़ी थी कि पूरी तहसील अकालग्रस्त होगी तो किसानों को लाभ मिलेगा । उसके चलते किसान लाभ से वंचित होता था । प्रधानमंत्री फसल बीमा में पंचायत को इकाई माना गया । पंचायत को इकाई मानने के चलते हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख 62 हजार किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला, मुआवजा मिला । मैं अपने जिले की बात करूंगा । मेरे जिले में किसानों ने जो फसल बीमा का प्रीमियम दिया है, कुल 8 करोड़ रूपये का दिया है । किसानों को फसल बीमा से जो मुआवजा मिला है, वह 139 करोड़ रूपये का है । किसानों के हित में नरेन्द्र मोदी जी और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने यह बड़ा काम किया है । हमारे कांग्रेस के साथियों को स्वीकार करना चाहिये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, 13 लाख किसानों ने लैंसो से लोन लिया था । जैसे लोन लेते हैं, काट लेते हैं । मात्र पांच लाख लोगों को दिया गया है, बाकी लोगों को नहीं दिया गया है । बाकी किसान क्या गलती किये थे, बाकी को मुआवजा क्यों नहीं दिये हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- मोहन मरकाम जी जैसा व्यक्ति यह बात करे कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो सिर्फ राजनीति करने आये हैं या पढ़ना लिखना भूल गये हैं । अगर पढ़ना लिखना इनको याद होता, फसल बीमा की क्या शर्तें हैं, कौन सी इकाई है, यह बात नहीं करते । ग्राम पंचायत को इकाई माना गया । जो पंचायत सूखाग्रस्त, अकालग्रस्त घोषित हुई, जिनका थ्रेशोल्ड कम पाया गया, वहां के किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला । माननीय सभापति जी, भाई मोहन मरकाम जी, जब अपना पहला भाषण देने खड़े हुये, उन्होंने भाषण में एक विषय रखा, किसानों की आत्महत्या का । हमारे कांग्रेस के साथी हर सत्र में किसानों की आत्महत्या काम मामला उठाते हैं । मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु हो, वह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये । परन्तु जो ये आत्महत्या की बात करते हैं, वह आत्महत्या क्या खेती में नुकसान के चलते हुई या किसान कर्ज से लदा हुआ था, इसलिए हुई । माननीय सभापति महोदय, ऐसी संख्या नहीं के बराबर रहती है । जब कहीं भी आत्महत्या की घटना होती है, पुलिस मर्ग कायम करती है, मर्ग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कायम करते समय उसमें एक कालम होता है, व्यवसाय । मृतक क्या काम करता था । हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर लगी हुई है, मर्ग कायम करते समय व्यवसाय का कालम आता है, वहां उसका कृषि लिखा जाता है, आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह भी हो सकता है । आत्महत्या का कारण बीमारी भी हो सकती है । आत्महत्या का कारण और कई हो सकते हैं । छत्तीसगढ़ का और हमारे देश का किसान दिल से इतना मजबूत है, खेती के चलते कभी भी वह आत्महत्या नहीं कर सकता । किसानों की आत्महत्या करने की बात करके बार-बार आप किसानों को बदनाम न करे तो ज्यादा अच्छा होगा । माननीय सभापति जी, यह निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ । माननीय सभापति जी, देश की आजादी को 71 साल पूरे हो गये । हम 72 वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं । आप पूरे देश का इतिहास उठाकर देखेंगे, इसमें लगभग 58 साल इनकी सरकार ने राज किया है ।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विधायकों को रोका गया है । आप निर्देशित करें, उन्हें अंदर आने दें । सरकार द्वारा साजिश एवं षडयंत्रपूर्वक रोका गया है । (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, उनको रोक दिया गया है, उनको यहां आने दें । सभापति महोदय, आप आसंदी से निर्देशित करें (व्यवधान) जारी...श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\b13\12.05-12.10

(व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारे वरिष्ठ सदस्यों को सदन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए । हमारे सदस्यों को बाहर रोका गया है । माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है उनको आने दिया जाये । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- श्री मोहन जी, आप बैठिए ।

श्री दीपक बैज :- हमारे वरिष्ठ सदस्यों को बाहर रोक दिया गया है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हम आधे घंटे से आपसे निवेदन कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिए न । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- आखिर उन्हें क्यों रोका गया है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक मिनट आप बैठिए । माननीय नेता जी ने इस बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है और इसके संदर्भ में संज्ञान लिया जा रहा है । आप थोड़ा धैर्य रखिये । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटे से अधिक हो गया है । बाहर बैठे हैं, उनको रोका गया है । (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप तत्काल निर्देशित करें । उनको आने दें ताकि वे भी चर्चा में भाग ले सकें । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- वे भी चर्चा में भाग ले सकें ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- सरकार षड़यंत्रपूर्वक ऐसा कर रही है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आधा-पौन घंटा हो गया है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैंने आपसे निवेदन किया कि कृपया उसके संदर्भ में आसंदी से..।

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटे से अधिक हो गया है ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं । नेता जी के द्वारा आसंदी को अवगत करा दिया गया है अब ऊस पर देखा जा रहा है । आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटे से अधिक हो गया है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटे हो गये हैं हमारे नेता नहीं आ रहे हैं । (व्यवधान) उनको आने दीजिये । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, उन्हें बाहर रोक दिया गया है । आप निर्देशित करें, उनको आने दें । हमारी मांग है कि जानबूझकर उनको रोका गया है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हमारी मांग है कि उनको जानबूझकर रोका गया है । आखिर उन्होंने क्या अपराध कर दिया है ? (व्यवधान) हमारे विधायकों को रोक दिया गया है । हम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक घंटे से निवेदन कर रहे हैं । (व्यवधान) हम किसानों की बात करना चाहते हैं । (व्यवधान) हमारे विधायक साथियों को अंदर आना चाहिए । (व्यवधान)

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, इन लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं ? इन लोग बोनस से डर क्यों रहे हैं ?

सभापति महोदय :- आप बैठिए ।

श्री नवीन मारकण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, इन लोग बोनस से डर क्यों रहे हैं ? इन लोग भय से ऐसा कर रहे हैं ।

अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, सदस्यों की यह चिंता है कि अघोषित रूप से आपातकाल तो नहीं लगा दिया गया है, जो सदस्यों को रोका जा रहा है ।

सभापति महोदय :- श्री अरूण जी बैठिये । उस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराया गया और यह देखा भी गया । चूंकि आप सब सदस्य जानते हैं कि सदन की नियम और प्रक्रियाएं हैं और नियम और प्रक्रियाओं की जानकारी हम सबको होते हुए भी अगर कोई माननीय सदस्य नियम-प्रक्रियाओं के विपरीत यदि एराईज करना चाहता है तो आप समझ सकते हैं कि हम और आप आज से नहीं बल्कि 5-5 वर्षों से माननीय नये सदस्य भी हैं और पुराने सदस्य कई सालों से हैं मगर नियम-प्रक्रियाओं को तोड़कर अगर आना चाहते हैं तो क्या यह उचित है, यह आपके विवेक पर छोड़ता हूं।(व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- साईकिल में आ रहे थे । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- उनको अंदर आने से रोका गया । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिये न ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन विरोधी नारे लगाये गये।)

..........श्री यादव

यादव\12-09-2018\b14\12.15-12.20

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

सभापति महोदय :- आप बैठिए । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए । देखिए यह सदन और सदन की कार्यवाहियां नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से हट कर यदि कोई माननीय सदस्य इस तरह से सदन में या अन्य जगह प्रवेश करना चाहते हैं, नियम प्रक्रियाओं के तहत यहां अंदर आने चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं तो किसी को भी नहीं रोका गया है । इस तरह से बात कहना कि रोका गया है, यह सूचना गलत है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, सायकल पर आने नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथियों को नहीं आने दिया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमने विधिवत आवेदन दिया है । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- यह सरकार किसान विरोधी है । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए)

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है और मेरे ख्याल से हल हो गया है तो कुछ दूर तक वह आ रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमने विधिवत सचिवालय को दिया था कि हम सायकल में आएंगे तो अनुमति क्यों नहीं दी ? हमने विधिवत आवेदन दिया है ।

श्री संतोष उपाध्याय :- मोहन भईया, ते दुल्हा राजा कस दिखत हे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपने नियम प्रक्रियाओं की दो बार व्यवस्था दी, अभी जो प्रतिपक्ष के द्वारा नारेबाजी हो रही है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यदि सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है तो एक बार समझ में भी आता है कि हम असहमत हैं । विधान सभा की नियम प्रक्रिया, विधान सभा की व्यवस्था खिलाफ यदि वह नारेबाजी कर रहे हैं तो इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वह विधान सभा की व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी है या सरकार के खिलाफ नारेबाजी है ?

श्री संतराम नेताम :- हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं । हम सायकल में आ रहे थे (व्यवधान) हम अपनी व्यवस्था से आ रहे थे, हम सायकल से आ रहे थे । (व्यवधान) हम नियम प्रक्रिया से आ रहे थे ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, वहां पर सदस्यों को रोककर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है । विपक्ष किसानों के हित की बात करना चाहता है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस तरह से सदन में जो भी है, जो भी उचित होगा और जो अनुचित होगा, मैं निकाल दूंगा, मगर आप बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने व्यवस्था दी और नियम प्रक्रियाओं का हवाला दिया उसके बाद यदि व्यवस्था पर नारेबाजी कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, यदि वह ऐसा कर रहे हैं तो आज तक के विधान सभा के पन्द्रह साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है । इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी ओर से व्यवस्था आए ।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपना विषय रखते हुए कह रहा था कि आजादी के 71 साल पूर्ण हो गए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा फिर से आग्रह है कि जिस बात को बार बार उठा रहे हैं कि घुसने के लिए नियम प्रक्रिया का हवाला दिया गया, जिसमें नारेबाजी की गई, उसमें वस्तुस्थिति क्या है ? किस बात पर यह नारेबाजी हुई? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- हमने विधिवत आवेदन दिया था । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- माननीय सभापति महोदय, क्या उनको रोका जाएगा ? (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हम लोग विधिवत तरीके से सायकल में आ रहे थे (व्यवधान) हम तो चुप बैठे थे, माननीय मंत्री जी पता नहीं क्यों (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप दोनों सदस्यों से मेरा अनुरोध है, जिस तरह से आक्रोशित होकर बात कर रहे हो, यह सदन की व्यवस्थाएं हैं, आप इस तरह ? माननीय नेता जी ने पूरी बात कही ।

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\b15\.-.5

सभापति महोदय :- आप सदस्यों से अनुरोध है कि जिस तरह से आक्रोशित होकर बात कर रहे हैं, यह सदन की व्यवस्थाएं हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, डीजल और पेट्रोल ऐसे ही बहुत महंगा हो गया है, आग में और न डाला जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, उसके साथ-साथ आज आखिरी दिन है, एक दिन के प्रदर्शन से आपकी हालत नहीं सुधरेगी, जितना हल्ला करवा लीजिए।

सभापति महोदय :- शिवरतन जी, बहुत समय हो गया, समाप्त कीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हो रहा है, सरकार के कार्यों का जवाब नहीं है, तो नाटक करके पेपर की हेडलाईन बने रहें इनका ये काम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा था कि आजादी के 71 वर्ष पूर्ण हो गये हैं और इस 71 वर्ष में देश के स्तर पर बात करें तो इस देश में लगभग 58 साल कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारों ने राज किया। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगभग 53 साल कांग्रेस समर्थित सरकारों ने राज किया। माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस की सरकार के पीरियड में हमारे देश और हमारे प्रदेश का कृषि हमेशा उपेक्षा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और भेदभाव का शिकार हुआ। ये सरकारें केवल उद्योगपतियों के हित में काम करने वाली सरकारें रहीं। किसानों के हित में जब भी कोई बड़ा निर्णय हुआ वह बड़ा निर्णय जब देश में जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकारें बनीं तभी बड़े निर्णय हुए। हमारे प्रदेश के किसानों को अगर सबसे पहले कर्ज मुक्ति का लाभ मिला तो वह वर्ष 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 764 करोड़ रूपये की कर्जमुक्ति पहली बार छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली।

श्री दीपक बैज :- आपके 15 साल में कितना कर्ज माफ किया?

श्री अरूण वोरा:- शर्मा जी, आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं कि 71 हजार करोड़ रूपये का ऋण कांग्रेस पार्टी ने ही माफ किया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हमारा देश गांवों में बसता है और हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। गांवों में निवास करने वाले जो किसान हैं उन किसानों के आने-जाने के लिए रास्ता भी बना तो वह पहली बार 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत पहली बार 1977 में मिट्टी का काम हुआ और बाद में अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना बनाकर उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, यह किसानों के हित में हमारा निर्णय है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया में अगर किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा बदनाम था तो वह भूख से मृत्यु के लिए बदनाम था। छत्तीसगढ़ अगर दूसरी बात में किसी मामले में बदनाम था तो वह नक्सलवाद के लिए बदनाम था और ये दोनों चीजें अगर छत्तीसगढ़ को विरासत में मिली थी तो यह इनके द्वारा विरासत में मिली थीं। सभापति महोदय, इस कलंक से छत्तीसगढ़ मुक्त हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है।

श्री दीपक बैज :- आप बोल रहे हैं कि विरासत में मिला है, आपने 15 साल राज किया है और अभी तक कितना मुक्त किया है?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, ये विरासत में मिला है की बात कर रहे हैं तो अभी आप विरासत में क्या देंगे? अब आप प्रदेश का खाली खजाना देंगे? आप पूरा खजाना खाली करते जा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि सत्य जरा कड़वा होता है और कड़वी चीज सबके बस की नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने विरासत में दी, मैं शर्मा जी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार अरबों रूपये की घोषणा कर रही है तो हमारी जो सरकार आयेगी इसके लिए आप खाली खजाना छोंड़कर जायेंगे क्या?

डॉ. खिलावन साहू :- वोरा जी, ये सपना आप देखते रहना, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, तीन चुनाव से तो आप सरकार आने का सपना देख रहे हैं।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- अरूण जी, अभी उही डहार बईठे हस त का होगे, उही डहार बईठे रह ना।

डॉ. विमल चोपड़ा :- (श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य हरे रंग का कुर्ता पहने हुए हैं) शिव भैय्या, अभी तक आप लाल पहनते थे तब ये भड़कते थे, ये हरा में कब से होने लग गया?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, क्या है आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी है इसलिए मैं किसानों का कलर पहनकर आया हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा था कि भूख और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में कलंकित करता था और इस कलंक से मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी ने किया, इस कलंक से छत्तीसगढ़ मुक्त हो इसके लिए किसी सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया तो वह सरकार डॉ. रमन सिंह जी की सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) पहली बार भोजन का अधिकार कानून अगर किसी सरकार ने बनाया तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बनाया और आज छत्तीसगढ़ की 80 प्रतिशत आबादी को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत चावल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों में दोनों टाईम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चूल्हा जल रहा है और ये हो रहा है तो डॉ. रमन सिंह जी के माध्यम से हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, नक्सलवाद से सरगुजा मुक्त हुआ है और नक्सलवादी घटनाएं नियंत्रित होने लगी हैं और उम्मीद करते हैं कि दो साल में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ देश का सबसे विकसित राज्य होगा यह मानकर चलते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अंतिम लाईन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा..

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\b16\12.20-12.25

जारी......श्री शिवरतन शर्मा :-
और छत्तीसगढ़ देश का सबसे विकसित राज्य हो होगा, यह हम मानकर चलते हैं । सभापति जी, मैं अंतिम लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारी दोनों सरकारों ने इस मातृभूमि के सपूत के रूप में, किसानों के गौरव और सम्मान को वापस लेने के लिए, सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में मैं प्रशंसा करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि किसानों के इस अनुपूरक बजट को आप सर्वसम्मति से पास करें । अगर आप इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हैं तो पूरे देश में यह माना जाएगा कि ये किसान विरोधी हैं । आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजो की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री नवीन मारकंडेय (आरंग) :- माननीय सभापति जी, आज कांग्रेस सायकल के सहारे सदन में आना चाहती है । आज यह देखने को मिल रहा है ।

श्री दीपक बैज :- मारकंडेय जी, आप वह दिन भूल रहे हो जब मुख्यमंत्री जी और बृजमोहन जी सायकल के सहारे आए थे ।

श्री नवीन मारकंडेय :- ऐसी भष्ट सायकल में कांग्रेस बैठना चाहती है ।

डॉ. विमल चोपड़ा :- संतराम जी, आप कौन सी कंपनी की सायकल पर बैठे थे?

श्री मोहन मरकाम :- वो कमीशन वाला सायकल था । (व्यवधान)

श्री दीपक बैज :- आदिवासी एक्सप्रेस कंपनी की सायकल थी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- इनके नेता ने एक बार सायकल की सवारी की थी, उत्तर प्रदेश में। उस सायकल की सवारी का परिणाम यह हुआ कि इनकी संख्या उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पुन्नूलाल जी के बच्चों की संख्या से कम हो गई और उसी गति को आप छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त करने वाले हो ।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांग संख्या 13, 29, 36, 41 और 64 का विरोध करता हूं । अभी जो मांग की गई है दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़, अठ्हत्तर लाख, एक सौ रूपए की । सभापति महोदय, मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि 2013 में जब चुनाव चल रहा था तो उस समय जनता ने यह मांग नहीं की थी कि हमें 2100 रूपए समर्थन मूल्य और 300 रूपए बोनस दीजिए । भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ था । लेकिन आज कि एक भी किसान को 2100 रूपए समर्थन मूल्य नहीं दिया गया । बीच में 300 रूपए बोनस इसलिए दिया गया कि अब चुनाव होने वाला है, हमारी मांग है कि जो 3 साल का बचत बोनस के साथ इस साल जो धान खरीदी होने वाली है, कुल 4 साल को बोनस देने की मांग सरकार से करते हैं । अभी किसानों को चार साल का बोनस दिया जाए ।

सभापति महोदय, इन्होंने कहा था कि एक-एक बीजा धान खरीदेंगे । 18 क्विंटल से घटाकर 15 क्विंटल कर दिया गया, 15 क्विंटल से घटाकर 11 क्विंटल कर दिया गया । जब हम लोगों ने बस्तर में मांग रखी और मंत्रालय में सचिव महोदय के समक्ष अपनी बात रखी तब जाकर हमारे यहां 15 क्विंटल किया गया । हमारे कई किसान लैम्प्स में जाकर रात-रात भर सोए लेकिन उनके धान की तौलाई नहीं हो पा रही थी । सभापति महोदय, मैं मक्का खरीदी के संबंध में भी कहना चाहूंगा और मैंने पिछली बार भी सदन में इस बात को रखा था कि बस्तर में धान के बाद सर्वाधिक उपज मक्के की होती है । मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम एक-एक लैम्प्स में समर्थन मूल्य में खरीदेंगे । लेकिन आज तक लैम्प्स खरीदी नहीं कर पा रहा है हमारे बड़े डोंगर क्षेत्र के किसान मक्के को खेतों में फेंक रहे हैं, बाड़ी में फेंक रहे हैं, मक्का सड़ रहा है । इस प्रकार से हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और सरकार बार-बार दावा करती है, वहां के जिला कलेक्टर ने मंच से कहा था कि हम एक-एक बीजा मकका खरीदेंगे । आखिर क्यों नहीं खरीद रहे हैं ? आज फिर इतने हजार करोड़ की राशि ले रहे हैं । सभापति महोदय, ये किसानों को धोखा दे रहे हैं । सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और खेदजनक बात है कि हमारे किसान जब बुवाई के समय खाद लेने गए तो लैम्प्स के मैनेजर ने कहा ।

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं भा.रा.कां. दल के कुछ अन्य सदस्यों ने सदन में प्रवेश किया)

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, हम सारे विधायकों को जिसमें धनेन्द्र साहू, दलेश्वर जी और सारी महिला विधायकों को रोका गया । एक जगह नहीं, तीन-तीन जगह हम लोगों को रोका गया है । विधान सभा अध्यक्ष आ रहे थे उनको भी वापस करके नहीं आने दिया गया है । यह प्रजातंत्र का दमन है और यदि विधायक, विधान सभा में नहीं आएंगे तो फिर अपनी बात कैसे रखेंगे । सभापति महोदय, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है । कार्यवाही रोकर इस पर विचार किया जाए । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- सरकार, विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- हम लोगों को आने से 10 जगह रोका गया है । (व्यवधान)

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\12-09-2018\b17\12.25-30

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति जी, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार कर रही है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, हम लोगों को आने से 10 जगह रोका गया है । छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, इनको माफ करने वाली नहीं है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति जी, विपक्ष ये जानना चाहती है कि क्या छत्तीसगढ़ में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है ?

श्री मोहन मरकाम :- हम अपनी बात विधान सभा में नहीं करेंगे तो कहां करेंगे ?

(श्री धनेन्द्र साहू के खड़े होने पर)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसा लगा रहा है कि सरकार हमें जानबूझकर रोक रही है, विधायकों को आने से रोका जा रहा है, ये सरकार इस तरह से काम कर रही है ।

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी, आपको ज्ञान है, वरिष्ठ सदस्य खड़े हैं, उसके बाद आप बीच में टोक रहे हैं । आपको बोलना है तो बोलिएगा । आप बैठिए ।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, किसानों का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेंकने के नाम पर आज ये विशेष बैठक बुलाई गई है और हम किसानों को ही सदन के अंदर आने के लिए रोका जा रहा है, हम लोग अपनी बैलगाड़ी से नहीं आएंगे तो क्या हम लोग सी प्लेन लेकर यहां पर आएं ? (शेम-शेम की आवाज) हम लोग अपनी बैलगाड़ी से विधान सभा में आ रहे थे । यदि कोई आपत्तिजनक है तो आप हमारी बैलगाड़ी को मेटर डिक्टेटर से जांच करा लें, लेकिन बैलगाड़ी को अंदर आने से रोका जाए । हम लोग भी 25-30 साल से इस सदन में आ रहे हैं, हमने कहीं पर नहीं पढ़ा कि कौन से वाहन से विधायक आएगा, कौन से वाहन से विधायक को प्रवेश दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा । आजतक हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा और आज एक-एक घंटे तक भरी धूप में हम लोगों को रोका गया । आज तीजा का त्यौहार है, हमारी बहनों को वहां पर धूप में रोका गया, हम किसान यहां पर नहीं आ सकते । इस पवित्र सदन में आने के लिए जनता ने हम लोगों को निर्वाचित करके भेजा है । ये सरकार का पुलिसिया आतंकवाद है कि विधायकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से रोका गया है और इसके लिए ये विशेषाधिकार का हनन हुआ है । मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सारी चर्चा छोड़कर हमारे विशेषाधिकार हनन पर चर्चा कराई जाए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकवादी आ गए । ऐसा रोका जा रहा है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा था ।

सभापति महोदय :- माननीय भूपेश जी, माननीय धनेन्द्र जी, आप लोगों ने इस संदर्भ में सदन का ध्यानाकृष्ट किया है, इस पर व्यवस्था देंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, व्यवस्था तत्काल आनी चाहिए । एस.पी., कलेक्टर, थानेदार, एडिश्नल एस.पी., एस.डी.ओ., एस.डी.एम., एस.डी.ओ.पी. पूरा पुलिस प्रशासन, पूरे रायपुर की पुलिस लगी हुई है और हम लोगों को जगह-जगह रोका गया । हम लोग साढ़े 9 बजे

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

से निकले हैं, लेकिन यहां पहुंचने में 12.30 बज गया, यहां आने में तीन घंटा लगा और हर जगह रोका जा रहा है । विधान सभा में आने से हमको प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है । इसमें तो पहले कार्यवाही हो, फिर आगे की कार्यवाही बढ़े । पूरी कार्यवाही को रोककर इसमें चर्चा होनी चाहिए ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, दुर्भाग्यजनक बात है कि हम अपनी बात इस सदन में नहीं कर सकते ।

श्री भूपेश बघेल :- आखिर सरकार क्या जवाब दे रही है, सरकार क्यों हमको आने से रोक रही है, प्रशासन ने क्यों रोका ? इसका जवाब पहले आना चाहिए ।

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, हम अपनी बात इस पवित्र सदन में नहीं रख सकते, ये दुर्भाग्यजनक बात है क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के किसानों की बातें कहना चाहते हैं, वह सरकार जान-बूझकर हमारे वरिष्ठ सदस्यों को रोका गया है । सभापति जी, आपकी व्यवस्था आनी चाहिए, क्योंकि हमने सचिवालय को विधिवत् सूचना भी दे दी है कि हम इस गाड़ी से, इस वाहन से आएंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, भाई मोहन मरकाम जी जिस विषय को उठा रहे हैं, उस विषय को पहले नेता प्रतिपक्ष उठा चुके हैं और आसंदी से व्यवस्था आ चुकी है । आसंदी की व्यवस्था के बाद बार-बार इस विषय को उठाना क्या आसंदी को चुनौती नहीं है ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, विषय अलग है । इनको रोका गया, वह अलग बात है । आपको रोका गया, वह अलग बात है ।

श्री संतराम नेताम :- विधान सभा में हम अपनी बात नहीं रख सकें, इसलिए रोका गया।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- जब बोल रहे हैं कि विधान सभा जा रहे हैं, उसके बाद रोक दें, ये गलत बात है ।

श्री भूपेश बघेल :- सत्यनारायण शर्मा जी अभी आ रहे हैं, इनको जगह-जगह रोका गया था ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- सभापति महोदय, आपने बिदाई समारोह आयोजित किया, उसके बाद जनता को धोखा देने के लिए आपने विशेष सत्र बुलाया । पांच साल तक आपने क्या किया ? यदि बोनस देना था तो पांच साल तक देना था, उसके बाद विधायक आ रहे हैं, उनको रोक रहे हैं । उसके बाद आने नहीं दे रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, शिवरतन जी को थोड़ा डांट दीजिए, ये ऊंगली करने में माहिर हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति जी, सत्यनारायण जी 6-6 बार के विधायक हैं, वे अभी पहुंच पा रहे हैं, अमरजीत तीन बार के विधायक हैं, उनको अभी आने दिया गया, लगातार बेरीकेटिंग करके रोक रहे हैं । हमारी महिला विधायकों को रोका गया, आज तीज का त्यौहार है, उसको रोका गया । हमने उनको जाने देने के लिए आग्रह किया और महिला विधायक को जाने दीजिए, लेकिन निर्मम पुलिस ने उन्हें आने नहीं दिया, विधान सभा उपाध्यक्ष का वाहन आधे घंटा तक खड़ा रहा, मैंने वहां भी आग्रह किया कि कम से कम विधान सभा उपाध्यक्ष को तो जाने दो, वे तो बैलगाड़ी में नहीं आये थे, लेकिन उनको भी नहीं आने दिया गया तो उनकी गाड़ी वापस चली गई । सभापति महोदय, हम तो आज की कार्यवाही रोककर चर्चा चाहते हैं और शासन की ओर से जवाब चाहते हैं कि इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, बैलगाड़ी में आने वाले लोगों का प्रवेश हो गया है, अब ये तो बता दें कि बैल बिदका क्यों था ?

श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\b18\12.30-12.35

श्री अमरजीत भगत :- शर्मा जी, सावन के अंधे को हरा-हरा दिखता है। जनता बेहाल है, परेशान है, हा-हाकार मचा हुआ है, 4 सौ की रसोई गैस 9 सौ, साढ़े 9 सौ में बिक रही है, पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और विधान सभा का सत्रावसान हो चुका था फिर ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि आपको विधान सभा की फिर से सत्र बुलानी पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप हर चीज को वोट की राजनीति से देख रहे हैं और आप लोग केवल ढोंग करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- 200 की दाल 55 रुपये किलो में बिक रही है, 45 की शक्कर 35 में बिक रही है, 40 का चावल 23 रुपये किलो में बिक रहा है, 30 का आटा 18 रुपये किलो में बिक रहा है, आप इसको क्यों नहीं बोलते?

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, अब केवल दो महीना बचा है, मंत्री तो बनना नहीं है, फिर क्यों दलाली कर रहे हैं?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार शराब बेचने में मस्त है, इधर जनता पस्त है, जनता परेशान है, जनता की किसी को परवाह नहीं है। जनता की कोई फिक्र नहीं करता। हमारी बहनें परेशान हैं, रसोई गैस महंगी हो गयी है, पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेणु जोगी जी को बधाई दूंगा कि इनको किनारे करते-करते ये सारे लोग गुलाबी रंग में रंग गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह किसानों का गमछा है। यह लाल रंग का और किसानों का गमछा है और इनको तो वही दिखाई देगा। यह गमछा किसानों का है, हमारे किसान कांग्रेस का गमछा है और इसको हम पहनकर आये हैं। आपको तो वही दिखेगा क्योंकि आप उन्हीं के भरोसे यहां वैतरणी पार करना चाहते हैं। (शेम शेम की आवाज) इस समय कुछ नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप सबने अपनी बात कह दी है और माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में है। इस पर कार्रवाई की जायेगी। कृपया कार्यवाही होते तक या व्यवस्था देते तक मैं इस सदन के संचालन में आपका सहयोग चाहता हूं। कृपया आप सहयोग करें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है। सारे विधायकों को रोका गया। शासन की ओर से इस पर जवाब आना चाहिए। सरकार हमको क्यों रोकी, यह तो बताएं? यहां हम कोई हमला करने वाले थे या हमारे साथ कोई आतंकवादी आया था ?

माननीय सभापति महोदय, हमको बार-बार रोका गया।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, ये देखिये, पूरी कीचड़ लगी हुई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमको बार-बार रोका गया। हम यहां 11 बजे उपस्थित होते, लेकिन हमको डेढ़-दो घंटे डिटेंट किया गया, रोका गया, जगह-जगह रोगा गया। अभी यहां गृहमंत्री जी बैठे हैं, हमें क्यों रोका गया, यह बताएं? माननीय सभापति महोदय, यह तो बताना पड़ेगा। लगातार बेरीकेटिंग की गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- गृहमंत्री जी क्या बतायेंगे, ये तो रमन सिंह जी की गाय हैं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने कल भी कहा था कि हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं आयेंगे, केवल विधायक आयेंगे और हम सब विधायक बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे। आखिर यहां तक आये, 1 नंबर गेट तक आ गये थे तो हमको बार-बार रोका क्यों गया? इस पर सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले सरकार की ओर से जवाब आए फिर आप कार्यवाही आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय :- बैठिये। देखिये विधान सभा परिसर में प्रवेश का यह विधान सभा सचिवालय और विधानसभा की नियम-प्रक्रियाओं के तहत करना पड़ता है और उसके तहत यहां पर कार्रवाई की गई। मैं समझता हूं कि इसमें विधान सभा सचिवालय के, माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाई गई है, इसके संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं व्यवस्था देंगे, तब तक सदन के संचालन में आप सहयोग करें, यह मेरी आपसे अपेक्षा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, इसी विधान सभा में विधान सभा सत्रावसान की घोषणा की गई थी और सत्रावसान के बाद किस नियम-प्रक्रिया के तहत विधान सभा सत्र पुन: आहूत की गई? इसको बताया जाए। जब यहां से सत्रावसान और विदाई का कार्यक्रम हो चुका था इसके बाद ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि पुन: विधान सभा सत्र आहूत की गई?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एडिश्नल एस.पी., कलेक्टर, एडिश्नल कलेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक पूरे के पूरे हमे रोकने में लगे हुए थे। आखिर वे हमें क्यों रोक रहे थे, पुलिस हमें क्यों रोक रही थी?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय भूपेश जी, आपने संज्ञान में ला दिया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं, कम से कम उनकी तरफ से जवाब तो आना चाहिए ।

समय : **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)**
12.35 बजे श्रीमती सविता

सविता\12-09-2018\b19\12.35-12.40

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले (व्यवधान), फिर सारे सीनियर एम.एल.ए. को रोका गया, (व्यवधान) माननीय अमरजीत भगत को बाद में रोका गया तो हर जगह रोकने की कोशिश लगातार की गई है हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं ये विशेषाधिकार हनन का मामला है और इसमें पहले व्यवस्था दे दें, उसके बाद कार्यवाही को आगे बढ़ाएं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के गेट से 200 मीटर दूर हम लोगों को रोका गया। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं के आंतकवादी आ गये, इस तरह से हम लोगों को पुलिस घेर ली और आपके पास, आपके सदन में नहीं आने दिया जा रहा था। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जो बात हम लोग आपके सामने रखने के लिए आते हैं, उसको भी रोका गया। 2 घण्टे तक मुजरिम की तरह रोका गया, हमें धूप में खड़ा किया गया, ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य श्री अमरजीत भगत जी ने अभी एक विषय का उल्लेख किया कि विधान सभा के सत्रावसान के पश्चात् किस नियम, किस अधिकार से विधान सभा का सत्र बुलाया गया, सत्र आपके द्वारा आहूत किया गया और ये आपके द्वारा आदेशित ये सत्र हो रहा है उसको किस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नियम, किस प्रक्रिया में बुलाया गया, ये कहकर के आसंदी की और एक प्रकार से अध्यक्ष की गरिमा की अवमानना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आसंदी के प्रति ऐसा नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ऐसी कोई...। (व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र आप बुलाते हैं या मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं? ये भी स्पष्ट कर दिया जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सत्र बुलाया, लेकिन इनकी सरकार ने हमें रोका, आपने सत्र बुलाया तब हम लोग आएं, लेकिन इनकी सरकार ने पुलिस का डंडा दिखाकर रोका, दो घण्टे तक हम लोगों को आरोपी, आतंकवादी की तरह धूप में खड़ा किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- बात हो गई, चलिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर हम लोग आएं, लेकिन ये सरकार इस तरह की "दादागिरी" कर रही थी।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी या माननीय विपक्ष के साथियों ने प्रवेश संबंधी जो बात उठायी है। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पक्ष के या सत्यनारायण जी कांग्रेस पक्ष के बहुत सीनियर विधायक हैं और मंत्री भी रहे है और माननीय सत्यनारायण शर्मा जी संसदीय कार्यमंत्री भी रहे हैं। जब भी सत्र नोटिफाईड होता है आपके द्वारा एक व्यवस्था दी जाती है कि किधर से प्रवेश होगा, किधर से आएगी, कितने बजे जाएंगे, कैसे होगा? और यदि उस पर कोई बात होती है तो मैं आज दूसरी बार इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ कि विधान सभा की व्यवस्था या आसंदी की व्यवस्था पर नारेबाजी हो, ये इस सदन में, इस सत्र में पहली बार दिख रहा है, एक बात।

अध्यक्ष महोदय :- आप रूकिए तो आप बैठिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आसंदी के आदेश पर हम लोग आ रहे थे और आपकी सरकार ने हम लोगों को रोका, सवाल इस बात का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आते ही प्रवेश नहीं दिया गया, विधान सभा की व्यवस्था थी आप सत्र के बाद प्रवेश देना, आपके परिपत्र जारी करने बाद कौन से विशेषाधिकार या उन्मुक्तियों का हनन हुआ है ? उसमें हम बहस कर सकते हैं, यदि इसमें आप व्यवस्था देते हैं तो बहस आमंत्रित है, किसी तरह का कोई विशेषाधिकार आपके निर्देश के बाद भंग नहीं हुआ है और यदि इसमें बहस की बात होती है तो बिल्कुल हम उसमें आप व्यवस्था देंगे तो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के विषय पर भूपेश बघेल जी बहस कर लें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही बैलगाड़ी से आने की सूचना दी थी, प्रशासन को भी जानकारी दे दी थी और उसके बाद यहां से 10 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया था, फिर दूसरे बैरेकेटिंग में रोका गया, फिर यहां जीरो प्वाईंट के उस पार हमको रोका गया और लगातार ये कलेक्टर, एस.पी. और पूरा प्रशासन लगा हुआ था तो किसके आदेश से हमको विधान सभा आने से रोका गया ? कार्यवाही से भाग लेने से रोक रहे हैं और इससे बड़ा विशेषाधिकार का हनन और क्या हो सकता है, उन अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। हमको रोका गया, सारे सदस्यों को रोका गया है।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी का आजकल तो ये शौक हो गया है, कभी सजी हुई घोड़ी पर टमटम लेकर ऐसा चलते हैं कभी बैलगाड़ी, कभी रथ पर चलते हैं। अभी विधान सभा आने के लिए बैलगाड़ी कहां तक आएगी और कहां तक नहीं आएगी, इसका तो कोई दिशानिर्देश है नहीं, पहला। सामान्य तौर पर जो आदमी आते हैं और जिसका पास इश्यू होता है वही वाहन अंदर आ सकता है वरना विधायक को अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर ही विधान सभा में आना है उसे विधान सभा के कार्य में बाधित करने के लिए कोई यदि जानबूझकर.....

......जारी श्री चौधरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौधरी\12-09-2018\c10\12.40-12.45

पूर्व जारी श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- उसे विधानसभा के कार्य में बाधित करने के लिए यदि कोई जान-बूझकर, नियतपूर्वक, बदनियती से विधानसभा के कार्य पर भाग लेने से टोकता है, रोकता है, तब विशेषाधिकार की बात होती है। लेकिन यदि आप राजनीतिक नौटंकी करने के लिए ऐसा करते हैं तो प्रशासन का ये काम है। क्या प्रशासन ला एण्ड आर्डर नहीं रखेगी? प्रशासन व्यवस्थाबनाने के लिए मजबूर हो रही है। जान-बूझकर के विधानसभा सत्र की इस गरिमामय जिसके बारे में सबको मालूम है कि ये सत्र विशेष तौर से किसानों के हित के लिए बुलाया गया है। किसानों के खातों में करोड़ों रुपया जाने से रोकने के लिए ये राजनीतिक नाटक किया जा रहा है। ... (व्यवधान)..

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्‌वारा नारे लगाये गये।)

श्री भूपेश बघेल :- हम अपने साधन से आये हैं, विधानसभा में हमको कैसे आना है। ... (व्यवधान)..

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्‌वारा नारे लगाये गये।)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी पूरे सदन के सामने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने तर्क बताये। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक और मंत्री।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूर्व संसदीय कार्य मंत्री।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- हॉ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो बात करेंगे सारे नियम को जानते हुए, समझते हुए करेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पाण्डेय जी ने कहा आपने वाहन से आ सकेंगे। मोड आफ ट्रान्सपोर्ट क्या लिखा है कि चार पहिये वाली वाहन से आयेंगे ? हम बैलगाड़ी में आयेंगे, हम चाहे जिसमें आयेंगे, हम घोड़े पर आयेंगे। आपने मोड ऑफ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ट्रान्सपोर्ट कहां लिखा है कि चार पहिया वाहन में आना है। आपने क्यों रोका ? आपके सरकारी चमचों ने क्यों रोका ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप किसी भी वाहन से आयें, विधानसभा सचिवालय पास जारी करता है, क्या आपने पास बनवाया ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा परिसर में चीफ सेकेटरी ऑफ स्टेट, डी.जी. पुलिस ऑफ स्टेट भी बगैर विधानसभा सचिवालय के द्वारा जारी प्रवेश पत्र के हस्ताक्षर सहित वह प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उस प्रवेशिका के साथ ही होना पड़ता है। ये विधानसभा का परिसर आपके शुद्ध नियंत्रण में चलता है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको पहले इस परिसर की चौहद्दी बता दी जाये। यह जो नियम माननीय विद्वान मंत्री जी ने बताया, हम लोगों को इस परिसार की चौहद्दी बता दी जाये। ये चौहद्दी बता दी जाये, उसके बाद फिर बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बता दिया जाये कि वह चौहद्दी कौन सी है ? स्वयं विद्यान मंत्री जी ने कहा है, आप किसी भी वाहन से आ सकते हैं कोई रोक नहीं है। इनका प्रशासन क्यों रोक रहा है? आपके परिसर की चौहद्दी के बाहर इनका प्रशासन क्यों रोक रहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- विधानसभा में और कोई इशु कांग्रेस के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना दिवालियापन की विधानसभा में प्रवेश कैसे किया जाये, इस पर विपक्ष बहस कर रही है। इसके अतिरिक्त और कोई इशु है ? प्रदेश हित में बात करिये। आप कोई व्ही.आई.पी. नहीं हैं।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आज महाराजा सरगुजा एक दिन के लिए बैलगाड़ी और एक दिन के लिए गमछा लगा लेने से कोई किसान या किसान के प्रतिनिधि नहीं हो जा रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे अनुमति दी जाये। हम अपने घर से किस वाहन से आ रहे हैं, यदि वहां रोका जा रहा है। हम विधानसभा के लिए निकले हैं और रास्ते में आ रहे हैं। हम बैलगाड़ी, सायकिल, पैदल, चारपहिया वाहन, मोटर साइकिल से आयें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश पर विधानसभा में आज तक चर्चा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, उनको बोल लेने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कैसे प्रवेश करे, यदि उसमें हैं तो नोटिस दें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कैसे प्रवेश किया जाये, इस पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को पुलिस ने रोका। आपने विशेषाधिकार हनन का मामला लाया था, एक सब-इंस्पेक्टर ने रोका था। यहीं प्रताड़ित किया गया था। जहां तक बैलगाड़ी से आने की बात है, अटल बिहारी बाजपेयी जी जिनको कल हमने श्रद्धांजली दिया, वह लोकसभा में बैलगाड़ी में गये थे तो फिर यहां क्यों रोका जा रहा है ? लोकसभा में बैलगाड़ी से गये।....(जारी).. श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\c11\01.45-01.50

..........जारी श्री भूपेश बघेल तो फिर यहां क्यों रोका जा रहा है। लोकसभा में बैलगाड़ी से गये। आप वही फोटो चिपकाकर चलते हो। तो फिर यदि हम लोग आ रहे हैं तो फिर हमको क्यों रोका जा रहा है ? इस विधान सभा परिसर से बाहर प्रशासन ने हमको रोका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अटल बिहारी बाजपेयी के नाम के लिए, नकल नहीं अकल चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- आप तो टेबल ठोक रहे थे। कैसे श्रद्धांजलि देते हैं, उसको देखा है। अटल बिहारी बाजपेयी के लिए कितनी श्रद्धा है, पूरे देश ने देखा है। ....(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- किसानों के लिए इस सदन में चर्चा हो रही है, वहां पर ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाईये। माननीय भूपेश बघेल जी सहित सभी सदस्यों की बातें मेरे संज्ञान में ला दी गई है। अगर इस प्रकार से कोई बात हुई है कि किसी सदस्य को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने से रोका जा रहा है तो मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। चूंकि यहां विधानसभा में पूर्व से माननीय सभी विधायकों को किस-किस वाहन से आयेंगे, उसके बारे में पास जारी किया गया है। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई थी कि हम बैलगाड़ी में आयेंगे तो मैंने उनको बुलाकर अनुरोध कर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिया था कि यहां बैलगाड़ी का पास जारी नहीं होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने-अपने वाहनों से जिसका आपको पास जारी किया गया है, उस वाहन से आयें। इस प्रकार की जो बात संज्ञान में लाई गई है, उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं। कम से कम उनके द्वारा बयान आना चाहिए कि हमको रास्ते में क्यों रोका गया।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दिखवा लूंगा, आपको बताया न।

श्री भूपेश बघेल :- निश्चित रूप से विधान सभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष आप जो कहेंगे, वही माना जायेगा। लेकिन हमको रास्ते में रोका गया है। हम राजीव भवन से चले और जीरो पाईंट आते तक कम से कम चार बार रोका गया और हर विधायक को रोका गया और महिला विधायकों से धक्का-मुक्की की गई। (शेम-शेम की आवाज) वाह का क्या मतलब है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- धक्का ?

श्री भूपेश बघेल :- अटल बिहारी बाजपेयी के मौत पर ठहाका लगाने वाले, टेबल पीटने वाले थे, वाह-आह करेंगे, क्या संवेदनशीलता है, पूरा देश जान चुका है। आपके बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है, आपके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। प्रवेश कैसे किया जाए, इस पर आधे घंटे से बहस कर रहे हो। अब उस पर क्या बात करें। मानसिक रूप से दिवालिया, वैचारिक रूप से दिवालिया। प्रवेश कैसे किया जाए,कौन सा विषय है। .....(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाईये।

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश जी, भूपेश जी। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीवास\12-09-2018\c12\01.25-01.30

समय
1.25 बजे **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुये ।)**

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से उस विषय पर जवाब आ जाता ।

अध्यक्ष महोदय :- शासन कुछ बोलना चाहेंगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष के साथियों के साथ किसी मुददे पर विधान सभा आने के विषय को लेकर प्रश्न उठाये गये और अपनी भावनायें व्यक्त की गई । जो भी बात आपके समक्ष लाई गई है, सरकार की प्रशासन की कभी यह मंशा नहीं रही कि हमारे विपक्ष के साथियों को या किसी भी सम्माननीय विधायक को विधान सभा की गतिविधियों में या उनके कर्त्तव्य निर्वहन में, किसी भी तरह की बाधा पहुंचाये जाये या अपमानित किया जाये, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए । फिर भी आज यहां आते वक्त माननीय सदस्यों के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, जिनकी बातें उनकी भावनायें से प्रकट हुई, उनको हम जांच करके दिखवा लेंगे और यदि तथ्य सही पायेंगे तो आपके निर्देश पर हम उचित कार्यवाही भी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम ।

श्री संतराम नेताम (केसकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के भाईयों ने जो किसानों के हित के लिए चिन्ता जाहिर कर रहे थे, किसान जब खाद और बीज के लिए लैम्पस में जाता है तो उनसे यह कहा जाता है कि आप पहले स्टाम्प में लाओ । यह किसान 10 रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के स्टाम्प के लिए नोटरी के पास जाता है तो 120 रूपये उनसे लेते हैं । अध्यक्ष महोदय, आठ दिन तक घूमता है, समय पर उनको बीज नहीं मिल पा रहा है । उनको 500 से 1000 रूपये खर्च हो रहे हैं । इसके पहले भी हमारी जो सरकार थी, उस समय भी खाद और बीज देते थे, उस समय स्टाम्प नहीं लगता था । बेवजह किसानों को परेशान करते हैं । कहते हैं कि हम किसानों के प्रति चिन्ता करते हैं, उनको बोनस देने की बात करते हैं, हम कब मना कर रहे हैं? हम विरोध नहीं करते । अध्यक्ष महोदय, आप पांच साल का बोनस दीजिए । किसान लोग मजबूत हो जाये । उनकी जो बालिकायें हैं, बालक हैं, अच्छे स्कूलों में हायर एजूकेशन प्राप्त करें। हम कभी भी बोनस देने और समर्थन मूल्य के विरोध में नहीं है । लेकिन जो सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं, उसमें 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने की बात हुई, लेकिन आज तक क्यों नहीं दे रहे हैं ? उनको कौन रोका है ? अध्यक्ष महोदय, यह हमारी मांग है कि उनको बोनस भी दें और समर्थन मूल्य 2100 रूपये देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बेरोजगारी की बात करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, अब मोबाइल बांट रहे हैं, मोबाईल न बांटकर अगर रोजगार देते तो हमारे बस्तर के बेरोजगार युवक बोरगाड़ी में काम करने दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते । इतनी महंगाई में हमारे युवा साथी अपने घर का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन लोग बोरगाड़ी में नागालैण्ड, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र में जाते हैं, वहां उनसे इतना काम लेते हैं, कई बार उनको बीमार भी पड़ना पड़ता है और हमारे एक सदराम मरकाम है, बांसकोट का, वह तमिलनाडु के जेल में बंद है । अध्यक्ष महोदय, उसकी जमानत हुई। उनका कहना है कि आपका राशन कार्ड हिन्दी में है, उसको इंग्लिश में करवाओ । आज छै: महीने से उसका इंग्लिश में नहीं हो पा रहा है । इस प्रकार से बेरोजगार पलायन कर रहे हैं। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो ? अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिये, हम इसके पक्ष में है । विकास का ढोल पिट रहे हैं । मेरे विधान सभा में बड़े डोंगर ब्लॉक मुख्यालय 6-6 महीने नहीं आ पाते हैं । अभी बाढ़ आया है, कोई भी नागरिक, कोई भी उस क्षेत्र के लोग ....

जारी....श्रीमती यादव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नीरमणी\12-09-2018\c13\01.30-01.35

जारी.......श्री संतराम नेताम :- अभी वसूली कर रहे हैं तो अभी वसूली करने की क्या प्रक्रिया है ? किसान कहां से लायेगा ? किसान ने तो अपना पूरा पैसा खेत में लगाया है तो हम इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं । हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे क्षेत्र के किसान, हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल हों । इस प्रकार से चूंकि हमारे रसोईया संघ के लोग भी, आखिर यह बजट उनको क्यों नहीं दिया जाता ? 40 रूपये में काम करने को मजबूर हैं । लिपिक संघ के लोग 07 तारीख से हड़ताल पर हैं । इनकी व्यवस्था आखिर कौन करेगा ? यह प्रेरक संघ है, कई दिनों से काम कर रहे हैं, दो-दो हजार रूपये उनको मानदेय देने की बात कही, आज तक 8-8 महीने हो गये हैं तो यह व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए । यह भी किसान घर के बच्चे हैं, हमारी सरकार से यह मांग है कि जो छोटे-छोटे नौकरी करते हैं उनको समय पर समय पर वेतन और मानदेय मिलना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महाविद्यालय की एक बात कहना चाहूंगा । दुख होता है कि मैंने महाविद्यालय विश्रामपुरी में कई बार मांग की, मंत्री जी से मिला, पत्राचार किया, विधानसभा में उठाया । केशकाल में छात्रों की संख्या ज्यादा हो गयी है, वहां पर छात्रों को एडमिशन नहीं मिल रहा है । छात्रों को एडमिशन नहीं मिलने से आज वे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो यह किस प्रकार की व्यवस्था है ? कैसा प्रशासन ? कैसी सरकार ? हमारी मांग है कि हमारे मंत्री जी को हमने पत्र लिखा लेकिन वहां सचिवालय के लोग हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं हैं तो हम जैसे विधायकों का फोन यदि रिसीव नहीं करेंगे, हमारे पत्र पर कोई विचार नहीं करेंगे । हमारी लड़ाई है बेरोजगारों की, हमारी लड़ाई है किसानों की । अभी हम आ रहे थे वहां पर रोक दिये जबकि हम साईकिल में आ रहे थे हमारे माननीय दीपक भाई, हमारे श्री साहू जी तो इस प्रकार की व्यवस्था का हम विरोध करते हैं । हम सरकार में कभी भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं, हमारा धर्म सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने का है लेकिन हम यहां पर जो भी पत्राचार करते हैं, हम सदन में जो भी क्षेत्र की बात रखते हैं तो कम से कम हमारी बात को सुना जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यह चूंकि अनुपूरक बजट है, मुख्य बजट नहीं है इसलिये अनुपूरक बजट जिस चीज के लिये लाया गया है यदि उसी के आसपास रहेंगे तो ठीक रहेगा । श्री अवधेश सिंह चंदेल । थोड़ा समय-सीमा का ध्यान रखेंगे ।

श्री अवधेश सिंह चंदेल (बेमेतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये 2 हजार 433 करोड 78 लाख 100 रूपये का जो बजट है तो मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से हमन पास करन और पास ऐकर सेती करन ताकि आने वाले समय में सरकार जो योजना बनाकर के काम करत हे, आने वाले समय में किसान ला ओकर लाभ हो और किसान मन ला लाभ दिलाना सरकार के फर्ज है, सरकार के दायित्व है । फर्ज और दायित्व ला बहुत ईमानदारी पूर्वक सरकार पूरा करत है, आज जईसे चर्चा होवत है जब से सदन चालू होय हे ता सफारी चलईया साईकिल में आवत है । अगर किसान के अतेक चिंता है अऊ स्वयं यदि डीजल बचाना है ता एक दिन में डीजल नइ बाचय, डीजल बचाना है तो ओकर बर तोला रेगुलर प्रयास करे बर लागही ता डीजल बाचही और सफारी चलईया साईकिल में आवत हे, मर्सिडीज के चलईया हा गाड़ी-बैला में आवत हे । देखो कैसा राजनीतिक प्रपंच है कि प्रदेश में मीडिया और अन्य माध्यम से जनता ला ये बताना चाहत है कि हमन तुंहर हितैषी हन । 50 साल ले अधिक राज करेओ तब तो तुमने हितैषी के कोई रोल ला नई निभाये । अब 50 साल से अधिक राज करने वाला अब कहत है कि साईकिल मा चलबो, सफारी वाले मन-मर्सिडीज वाले मन कहत हैं कि हमन गाड़ी-बैला मा चलबो, ये तुंहर नाटक-नौटंकी ला पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश मीडिया अऊ अन्य माध्यम से देखत है लेकिन सरकार काम बढ़िया करत हे, 14 साल से अधिक होगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप विषय पर आ जाईये ।

श्री अवधेश सिंह चंदेल :- मैं बिल्कुल विषय में हंआें । (हंसी) माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसान मन के आय में कइसे वृद्धि होय । खेती-बाड़ी कैसे आगे चलकर के बढ़िया हो, सरकार क्रमश: 14-15 से लेकर के जेन अनुदान दिस, यांत्रिकीकरण के व्यवस्था करना, कृषि में शिक्षा ला बढ़ावा देना, समय-समय में परीक्षण करना, कभी-कभी जब जरूरत होगे तो प्रशिक्षण लगाना, सिंचाई के क्षमता ला बढ़ाना, कृषि के ....जारी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

............श्री यादव

यादव\12-09-2018\c14\01.10-01.15

...........(जारी श्री अवधेश सिंह चंदेल) :- समय समय में परीक्षण करना, कभी कभी जब जरूरत होगे तो प्रशिक्षण लगाना, सिंचाई के क्षमता ला बढ़ाना, कृषि के ऋण देना, ऋण में माफी देना । ये सब होय के बाद अगर कोई प्रकार के आपदा आ गये तो वो आपदा के समय में किसान ला कइसे व्यवस्था ढंग से ओला लाभ दिलाये जाये । मछली का उत्पादन करना और यदि किसी का पशुपालन की ओर ध्यान हे तो पशुपालन में कइसे सरकार हा ओला मदद करेय ताकि ये सब मिलकर प्रदेश के तरक्की और विकास में सबकी भूमिका बनी रहेय । माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में आज ये जो सत्र लगे हे वो सिर्फ और सिर्फ किसान बर हे और ये सत्र में ये विरोध करथ हे तो मैं नइ समझों कि सदन में एखर मन के विरोध हे । ये हमार यहां 80 प्रतिशत किसान और वो कौन किसान जेन बहुत छोटे किसान हे जो मध्यम किसान हे जेखर लिये ये सरकार योजना बनाकर काम करत हे, ऐखर मन के विरोध करना । आज जेन व्यवस्था हे और ये सारा व्यवस्था में अब किसान वास्तव में जेन ला लाभ मिलना चाहिए, वो किसान ला लाभ मिलत हे । नइ तो खेती भी बड़े आदमी करत रहिन हे । अगर कोई नया सिस्टम आ जाए, खेती किसानी में कोई यंत्र आ जाए, यदि कोई वैज्ञानिक ढंग से मदद करे जाए तो वो शहर के किसान हा अपन अपन खेती में करत रहिस हे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के कोना कोना कोई भी गांव हो, वो गांव के व्यक्ति ला जेन सुविधा हे ओखर लाभ सबला अब मिलन लगेय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप मन ला कहना चाहूं कि अभी दस बारह साल में किसान मन ला चाहे वो किसान समृद्धि योजना हो, चाहे हमारा छोटे छोटे किसान मन ला सरकार के माध्यम से जो लाभ मिलिस ओखर लाभ के कारण आज जेन किसान हे वो कम से कम कर्ज मुक्ति वाला है । पहिली आदमी कर्जा में पैदा लेवेय, कर्जा में पलेय बड़ेह और कर्जा में मर जात रहिस हे, लेकिन अभी कहत रहिस हे, हमार कुछ सदस्य कहत रहिन हे कि कतका कन किसान के कर्जा माफ करेय हो । अरे, हम ला जादा कर्जा लेय की जरूरत ही नइ हे, हम कर्जदार है ही नइ हे, हम व्यापारी के दरवाजा मा बइठे के जरूरत ही नइ हे तो कोन बात के हमार मन के माफी के बात करबो ? कौनो दिन अइसा अवसर और मौका आ गये तो ओखर लिये केंद्र की सरकार और राज्य सरकार हा व्यवस्था बनाकर के रखे हे ताकि ओला फसल क्षति या फसल बीमा के जो लाभ है, ओला जरूर मिलही, लेकिन कतको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदस्य मन ला कहना हे कि ये कर्जा है, मोर हिसाब से आज की डेट में 90 प्रतिशत से अधिक कर्जदार अपन बैंक में चाहे सेवा सहकारी बैंक समिति में जाकर कर्जा ला पटावत हे । मैं आज नइ मानो कि तुम्हर जमाना में भले रहिस, लेकिन आज के जमाने में ये परिवर्तन आ गये हे । यदि तुम्हर बेस अच्छा रख रहित्यो आज आजादी के बाद अनेक साल तक जेन तुम शासन करे हो, राज करे, यदि वही व्यवस्था ला अच्छा बनाकर के रखते । आज ये हाल नइ हे । बदहाली ले उबारे वाला कोई नेता यदि इस देश में, इस धरती में पैदा लीस तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पैदा लीस । नइ तो हमन मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी रहत रहिस हे तो ये कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता ला एक उपहार स्वरूप तुम्हर उम्मीद, अपेक्षा और जेन ढंग से तुम सोचत रहिस हो, हमार पूर्वज सोचत रहिस कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी करिस और छत्तीसगढ़ राज्य की जनता ले ये बात के लिये समर्पित और सौंप दीस कि आगे चलकर हमार जेन पूर्वज मन जो सपना देखे हे ओ सपना ला पूरा करेय ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग, देश के सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर मानते हैं, लेकिन [XX] [7] उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यह बोलना बंद करें, [XX] अवधेश जी, इसको थोड़ा बताओ तब तो होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ अपमानजनक बोला हो तो हटा देना।

श्री अवधेश सिंह चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट में चरचा होत हे, किसान मन ला जो वाजिब हक हे, वो मिले, ये चरचा होवत हे । लेकिन अवरोध पैदा करना एखर मन के स्वभाव में आ गये हे । अध्यक्ष महोदय, सबले जादा अगर हम ले लाभ मिले तो वो कृषि में अनुदान के कारण मिले हे । यदि अनुदान नइ मिलतिस तो...।

श्री भोलाराम साहू :- कहां वाजिब हक मिलथस हे, भाई बता न ओला, 2100 रूपए कहां मिलत हे, के साल के बोनस देय रहिस हे ?

अध्यक्ष महोदय :- इधर, इधर । आपने इधर तो देखा ही नहीं, उधर क्या देख रहे थे ? (हंसी)

[XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित ।

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अवधेश सिंह चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब सदस्य ला मालूम हे और जेन विरोध करथे वो सबले पहिली बोनस ला उठा लेत हे । वो ये इंतजार नइ करेय कि चल हम पहिली किसान मन ला या छोटे किसान मन हे, मझला किसान मन ला दिवा जाये । ये जतका गोठियाने वाला हे सबले पहिली ये मन बोनस प्राप्त करथे और अइसन अगर तुम ला बोनस के विरोध हे ......(जारी) श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\c15\.-.5

जारी.. श्री अवधेश सिंह चंदेल :- सबले पहिली बोनस ये मन प्राप्त करथे और अइसन अगर तूमन ला बोनस के विरोध हे तो एकाध जन वापस करके देखाओ ताकि ये प्रदेश में एक उदाहरण बन सके। लेकिन वो काम ला करना नहीं हे। ऐखरसेति कि जनता ला गुमराह करके ये जिन्दगीभर येमन दल के लिए लड़िन। अगर ये देश के लिए लड़े रतिस, ये गरीब और समाज के लिए लड़े रतिस तो ये 14-15 साल से राईट साईड में नई बैईठतिस, ये लेफ्ट साईड में बईठतिस। लेकिन जिन्दगी में कभी देश के लिए चिन्ता नई करिन, कभी समाज के लिए चिन्ता नई करिन।

श्री दीपक बैज :- चंदेल साहब, दो महिने के बाद उधर बैठेंगे अभी चिन्ता मत करो।

श्री अवधेश सिंह चंदेल :- अभी वो ह बहुत दूर के बात हे और दूर के बात ऐखरसेति हे कि दिल्ली में जेमन ला तूमन बैठारके रखे हो ओखर में अतेक बड़े क्षमता नई हे कि (XX)[8] ला वो ह टक्कर दे सके।

श्री कवासी लखमा :- (XX) का जुमलाबादी खत्म करो भाई।

श्री दीपक बैज :- (XX) हाल गोवा में देख लिए हम लोग, मणिपुर में भी देख लिये, अब कितना जगह देखना है?

अध्यक्ष महोदय :- जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनका निकाल दिया जाए।

(XX)[8] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित

Uncorrected and unedited/Not for Publication September 12, 2018

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को डूबने के लिए मात्र इतना सा (माथे तक इशारा) बचा हुआ है। डूबने के लिए इतना (माथे तक इशारा) ही बचा है चिन्ता मत करो। 2018-19 बता देगा पूरा समाप्त।

श्री अवधेश सिंह चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शैतान लईका अपन नाव खुदे फोड़ डालथे। डूबना ही रथे तो अपने हाथ में खुदे गड़बड़ कर डालथे, त अईसे गड़बड़ी करके आज इहां बईठे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ छोटे किसान ला मिले हे तो जीरो परसेंट ब्याज हे। अभी तीन-चार साल से हमर किसान मन के जेन आर्थिक स्थिति सुधरेहे तो ओमा सबले बड़े अगर कोई लाभकारी बात हे और सबले ज्यादा अगर कोई फायदा मिले हे तो वह जीरो परसेंट ब्याज के कारण वरना किसान कभी सुधर नई पात रहिस। किसान के आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरत रहिस। ओखर औलाद अगर पढ़त रहिस तो ओखर बर साईकिल नहीं खरीद सकत रहिस। लईका अगर पढ़े ल जात रहिस तो चार जोड़ी ड्रेस नहीं बनवा सकत रहिस। ओखर एकाध बेटा-बेटी अगर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में सलेक्सन हो जाए त किसान अपन औलाद ला डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकत रहिस, ये स्थिति हमर छत्तीसगढ़ के किसान मन के रहिस। जेमा परिवर्तन आये हे, और ऐसा परिवर्तन आये हे तो सबले बड़े अगर कोई कारण हे तो मैं आप मन ला कहना चाहत हों कि भारतीय जनता पाटी की सरकार डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसान मन के लिए अनेक योजना संचालित करिस और अनेक योजना बनाईस और सौभाग्य अच्छा हे कि योजना बनाने वाला तो तूमन बहुत रहेव, तुम्हर नेता बहुत योजना बनावय, रायपुर और दिल्ली में बैठकर हमार नेता और हमार दल अगर योजना बनावथे तो वह गांव में जाकर चाहे वह ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से हो, लोक स्वराज अभियान के माध्यम से हो या गांव में गांव के गरीब, किसान के साथ बैंईठकरके, झाड़ के नीचे बैइठकरके, तंबू लगाकर, छाया जहां मिलगे, अगर कोई तरिया के पार मिलगे या कोई आम के पेड़ के छाया मिलगे तो वहां जाकर सरकार अगर चर्चा करथे और वो चर्चा के आधार पर आज अगर सरकार अनेक योजना बनाईस ऐखर कारण आज धरातल में ये सब योजना दिखथे। मैं आपमन से भी आग्रह करहूं काबर कि किसान हित के बात हे, किसान मन के विषय हे ऐखरसेति कहथंव अगर आज के ये विषय में आपके समर्थन नहीं रहिही तो मैं समझथौं कि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के आप विरोध करथव और जेन विरोध करथव आने वाले समय में निश्चित रूप से क्योंकि आपके तो दू आंखी हे यहां ढ़ाई करोड़ जनता

के पांच करोड़ आंखी हे। तुम दू आंख वाले ये चिन्ता मत करो कि हम जेन काम करथन अच्छा करथन लेकिन ढ़ाई करोड़ जनता तूमन के कृत्य ला, तूमन के व्यवहार ला और आज मर्सिडीज में जेन चलैया बैलागाड़ी में आवथे और हमार जतका ये साथीमन हे चाहे बस्तर और सरगुजा वाले मन आपमन टाटा सफारी वाले आज साईकल में आये हो, ये सब जनता देखथे, तुम्हर कृत्य ला देखत हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मोला समय देव ऐखर लिए आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे आग्रह हे कि ये बजट ला सर्वसम्मति से पास करहू, यही मोर आप सबसे विनती हे, आग्रह हे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सत्र है यह कानून के विरूद्ध है क्योंकि डॉ. रमन सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकने वाली है। यह इस देश के कानून को मानने वाली पार्टी नहीं है इसलिए हम लोग हमेशा आरोप लगाते हैं और देश की जनता भी जानती है क्योंकि मैं मध्यप्रदेश में भी एम.एल.ए. था, हम लोग यहां आपके साथ लगातार 20 साल ..

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\c16\01.45-01.50

जारी......श्री कवासी लखमा :-

मैं आपके साथ लगातार 20 सालों से विधान सभा देख रहा हूं और उसके पहले भी हम लोग देख रहे थे । विधान सभा में एक बार विदाई होती है, सदस्यों का फोटो सेशन होता है । फोटो खींचा जाता है । आपके आदेश के अनुसार फोटो सेशन होता है, गले मिला जाता है, आप बधाई देते हैं, नेता प्रतिपक्ष बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी बधाई देते हैं, पत्रकार दीघा के पत्रकारों को बधाई देते हैं । सबको बधाई देने के बाद, अगला चुनाव जीतने के बार विधान सभा में आते हैं । हमने भी यही सोचा था और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी ऐसा ही सोचा था । लेकिन हिंदुस्तान के कानून के विरूद्ध, पूरी दुनिया के कानून के विरूद्ध यह जो विशेष सत्र बुलाया गया है, यह चुनाव का सत्र है । विकास यात्रा में मुख्यमंत्री जी घूमे, सब में पीछे हो गए, काम नहीं कर पाए । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार छत्तीसगढ़ से नहीं चलती है, यह छत्तीसगढ़ की मंशा के अनुरूप नहीं चलती है । यह सरकार नागपुर के आधार पर चलती है । अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग एक बेटी को विदा करते हैं, मेहमान बैलगाड़ी से आते हैं, दामाद घोड़े पर बैठकर आता है, विदा करने के बाद बेटी एक साल तक घर नहीं आती है । उसी प्रकार यहां विधान सभा में विदाई

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होने के बाद, चुनाव जीतेने के बाद आना था लेकिन इन्होंने यह सत्र क्यों बुलाया ? अध्यक्ष महोदय, हम लोग धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपए किए जाने की मांग कर रहे थे । कांग्रेस पार्टी लगातार बोनस की मांग कर रही थी । हम लोग पूरा का पूरा धान खरीदने की बात कर रहे थे, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम अंतिम व्यक्ति के धान की खरीदी करेंगे। लगातार चुनाव जीतने के बाद और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 क्विंटल पर आ गए । कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, किसान, मजदूरों ने गली गली में, सड़क में विरोध किया तो ले-देकर 15 क्विंटल में पहुंच गए । कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में कहा था, स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी ने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग 2000 रूपए क्विंटल में धान खरीदी करेंगे । इन्होंने हमारी नकल करके कहा कि हम 2100 रूपए में खरीदी करेंगे । पांच साल हो गए लेकिन वह 2100 रूपया गायब हो गया । हम 2100 रूपए के लिए चिल्ला चिल्लाकर थक गए लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है । आज जबरदस्ती सत्र बुलाकर कहते हैं कि हम बोनस देने वाले हैं । ये हमारे छत्तीसगढ़ की सीधी-साधी जनता को गुमराह कर रहे हैं । यह सत्र केवल वोट के लिए बुलाया गया है । जब बजट सत्र चल रहा था, जब मानसून सत्र चल रहा था तो हम लोगों ने सत्र की बैठकें बढ़ाने की मांग की थी हमने कहा कि एक महीने बजट सत्र चले, 10 दिन वर्षाकालीन सत्र चले । हमारे नेता ने लिखकर दिया, हमने कहा लेकिन उस समय नहीं माना । अभी ऐसा कौन सा पहाड़ गिरने वाला था । हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि हर साल बोनस दो, किसने रमन सिंह जी को बोनस देने से रोका था ? किसने इस सरकार को बोनस देने से रोका था ? यह बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हम किसानों की तरफ से पूछना चाहते हैं । अभी कहते हैं कि एक नवम्बर से धान खरीदी की जाएगी । हम लोग तो कह रहे थे कि जिस समय धान कटाई हो रही थी उसी समय से धान लेना था लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं । चूंकि यह चुनावी वर्ष है इसलिए 1 तारीख से खरीदी होगी तो खरीदी का पैसा मिलेगा और बोनस का पैसा भी मिलेगा तो 2100 कैसे मिलेगा ? क्या उसके लिए भी एक सत्र लगाया जाएगा । यह [9](xx) का धंधा बंद करे । अध्यक्ष महोदय, हम लोग सोचते थे कि छत्तीसगढ़ के सीधे सादे आदिवासियों को मोबाइल बांटेंगे, हमारे पंचायत के पैसे पर डाका डाल रहे थे । हम कांग्रेस पार्टी

[9] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

अशोधित प्रकाशन के लिए नहीं

के लोगों ने उसका लगातार विरोध किया है । ....जारी

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\12-09-2018\c17\1.50-55

जारी....श्री कवासी लखमा :- पंचायत के पैसे में डांका डाल रहे थे । हम कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार विरोध किये हैं । पंचायती राज के अधिकार का दुरूपयोग हो रहा है। इसलिए उस पैसे को छीन लिए, लेकिन हमारे बस्तर में मोबाईल नहीं बंटा है, सरगुजा में, जशपुर में मोबाइल फट रहा है, जिससे वह मोबाईल जान का खतरा बना हुआ है । 22 सौ करोड़ रूपए का मोबाईल बांटा गया । 22 सौ करोड़ रूपए में इन्द्रावती नदी में बांध बना देते, सबरी नदी में स्टाप डेम बना देते, जिससे सिंचाई की योजना बन जाती । नौजवान पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देते तो उनको फायदा हो जाता, नौकरी तो देना नहीं है, नौजवान पढ़े-लिखे लोग भटक रहे हैं और ये मोबाईल बांट रहे हैं । सब पार्टियां चुनाव में जाती हैं, किसानों के पास जाता है, मतदाताओं के पास, गांव में वोट मांगने जाती है, गांव वाले कहते हैं कि हमारे लिए स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल खोलो, हमारे बच्चों को नौकरी दो, शिक्षा कर्मी बनाओ, पुलिस बनाओ, पटवारी बनाओ, मेरी उम्र 60 साल हो गई, लेकिन गांव का कोई आदमी नहीं बोला था कि चुनाव जीतने के बाद मुझे मोबाईल दो, छत्तीसगढ़ का कोई भी आदमी नहीं बोला था कि हमको जूता बांटो । जनता कुछ और मांगती है, ये सरकार कुछ और देती है । मैं जब भी कभी बोलता हूं तो ये सरकार बोलती है कि लंदन से नहीं खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से । रतनजोत में करोड़ों रूपए खर्च हुए, उसका क्या हुआ । मोबाईल का भी वही हाल है । इस मोबाईल 6 महीने के बाद 299 रूपये का पैसा भराएंगे, 6 महीने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ की जनता मोबाईल रिचार्ज करवाएगी तो उस मोबाईल कम्पनी को 90-100 करोड़ रूपए का लाभ एक महीने में होगा । एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए मोबाईल का धंधा और जहां-जहां मोबाईल फूट रहा है, जान को जोखिम में डाल रहे हैं । अगर सरकार कोई भी आदमी को रोजगार देती है तो गड्डा करने वालों को पैसा नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में किसान बहुत ज्यादा है, लेकिन आधे किसानों को सरकार बोनस देती है । हमारे बस्तर के लोग खासकर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के लोग तेलांगाना में हमारा किसान धान बेचता है क्योंकि वहां नकद पैसा मिलता है । यह सरकार छत्तीसगढ़ को बरबाद करने की कोशिश कर रही है, कभी मोबाईल बांट रही है, कभी तेंदूपत्ता के बोनस का त्यौहार मनाते हैं, कभी लाईट का त्यौहार मनाते हैं । इस प्रकार भटका-भटका के छत्तीसगढ़ के लोगों से असत्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बोलने का काम करती है । हम लोग हमेशा बोलते थे कि जब बजट सत्र चल रहा था । इस बजट सत्र में हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं मालूम, हम लोगों को भी नहीं मालूम था, हमने पेपर में देखा कि दो दिन का बजट सत्र चलेगा । जब हम लोग कल ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दिए हैं, देश की जनता उनको नमन करती है, वे देश के नेता थे, लेकिन उसमें भी राजनीति कर रहे हैं । नया रायपुर को अटल जी का नाम देकर सौगात करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को उनको नाम से सौगात करते हैं, लेकिन उनकी कलश यात्रा में बड़े-बड़े मंत्रियों का हंसना, हाथ उठा-उठाकर ऐसा करना कितना सही है । इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार किये हैं । ऐसे लोगों को तो मंत्रिमण्डल से निकाल देना चाहिए । महापुरूष की कलश यात्रा में हंसना, मजाक करना ये अच्छी बात नहीं है इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इस देश में चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर हों, इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इस देश का कानून बनाया है, ये कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं । इसी से जाहिर होता है कि इस विधान सभा में एक बार बिदा होने के बाद, विधान सभा में एक बार गला मिलने के बाद दोबारा विधान सभा सत्र नहीं होता है, लेकिन एक दिन की बात नहीं, पांच साल की बात नहीं, 15 सालों से डा. रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं, 15 सालों में किसानों की याद क्यों नहीं आयी, किसानों को कहां भूल गए थे, किसानों को क्यों नहीं दिए, आज चुनाव का अवसर आया तो मोबाईल बांटना, धान के बोनस का विशेष सत्र बुलाना.... श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\c18\01.55-01.60

श्री कवासी लखमा :- आज चुनाव को नजदीक आते देखकर ये मोबाइल बांटना, धान का बोनस देने के लिए विशेष सत्र बुलाना इसे छत्तीसगढ़ की जनता भली-भांति समझती है। छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा चुकी है। कभी चावल के नाम पर, कभी दारू के नाम पर तो कभी मोबाइल के नाम पर, लेकिन इस समय रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, नौजवान अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज कर्मचारी रैली कर रहे हैं, उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, वे रेगुलर नहीं हो रहे हैं। चपरासी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन ये सभी परेशान है, आज कौन सा वर्ग अछूता है? पुलिस के लोग, जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनके पास बंदूक होती है, इसलिए वे रैली नहीं कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान में पहली ऐसी सरकार है, जहां की पुलिस के परिवार की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रैली कर रहे हैं। कोई नहीं बचा है। चाहे आदिवासी, किसान, आम जनता की बात हो, मैं आरोप इसलिए लगाता हूं कि आदिवासियों की जमीन को उद्योगपति/करोड़पति को लूटने के लिए दी जा रही है, चुनाव नजदीक आता है तो फिर उनको जमीन वापस कर दी जाती है, यह छत्तीसगढ़ को मजाक बनाकर रख दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार सफल नहीं होने वाली है। चार साल पहले केन्द्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय घरेलू गैस की कीमत चार सौ रुपये थी, अभी दोगुनी हो गयी है। दिल्ली में सात सौ रुपये, रायपुर में आठ सौ रुपये तो सुकमा, बीजापुर में नौ सौ रुपये हो गयी है। आने-जाने, गाड़ी का किराया मिलाकर 12 सौ रुपये खर्च आता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार है, जब वहां पेट्रोल-डीजल के दाम चार रुपये कम हो सकते हैं तो यहां डॉ. रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में कम क्यों नहीं करना चाहिए। क्या इसके लिए भी अलग से सत्र आहूत करना पड़ेगा? पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से आज सब्जियों, चावल, दाल और जरूरत की सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, कभी पेट्रोल-डीजल को लेकर सायकल तो कभी पैदल रैली निकाले वाले इन लोगों के आज मुंह बंद हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 लाख रुपये देने की बात की थी, बड़ी-बड़ी बातें कीं, महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज वे आराम से बैठे हैं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री देवजी भाई पटेल (धरसींवा) :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी सहृदयता के लिए और प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस देश का अन्नदाता, इस प्रदेश का अन्नदाता कैसे खुशहाल रहे, उसके लिए निरंतर चिंता करते हुए डॉ. रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कीर्तिमान स्थापित किये। यहां के किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विशेष सत्र के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले समय में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की चिंता थी । सत्र के बाद नये सत्र में किसानों के लिए धान के बोनस की डॉ. रमन सिंह की सरकार ने सहृदयता के साथ किसानों को लाभ देने की घोषणा की थी, उसे अप्रैल-मई में प्राप्त होता था। मगर पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने किसानों के साथ खड़े होकर यह घोषणा की कि क्यों न सरकार धान खरीदते समय धान के समर्थन मूल्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के साथ उन्हें 3 सौ रुपया बोनस भी सम्मिलित कर के दिया जाएऔर इसके लिए इस विशेष सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर एक अनुपूरक के माध्यम से 24 सौ करोड़ का किसानों के हित के लिए फैसला लिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में बहुत बड़े फैसले लिये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय पटेल साहब, किसानों के लिए तो दे रहे हैं, थोड़ा, पेट्रोल-डीजल का भी बता देना। सरकार इनके दाम कर दे। राजस्थान में कम हुआ है, यहां भी कम कराओ।

श्रीमती सविता

सविता\12-09-2018\c19\02.05-02.10

श्री कवासी लखमा :- माननीय पटेल साहब, किसानों के लिए तो दे रहे हैं, डीजल पेट्रोल का भी थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा रेट कम कर दें। राजस्थान में कम हुआ है यहां भी कराएं, क्या दिक्कत है ?

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, किसानों की उपज को खरीदने के लिए कोई माकूल व्यवस्थाएं नहीं थीं, उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दीर्घकलीन एक कारगर नीति बनाने का निश्चय किया और उसी नीति के तहत 200-250 करोड़ रूपये का बजट कृषि के लिए रहता था, आज उसको बढ़ाकर 4 हजार करोड़ रूपये का बजट करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और कई बार अलग से कृषि बजट यहां लागू करके, केवल किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस देने से ही किसानों की माली हालत नहीं सुधर सकती। इस सरकार ने अनेक ऐसे कारगर उपाए किए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम बिजली के कनेक्शन देने का बड़ा काम किया। राज्य बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी। पूरे प्रदेश में 73 हजार पम्प कनेक्शन थे और इसे बढ़ाते हुए आज वर्ष 2018 में 4 लाख, 69 हजार, कृषि पम्प कनेक्शन दिए गए, उसमें 75 हजार से लेकर किसानों को पम्प कनेक्शन स्थापित करने के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए अनुदान की राशि भी दी गई। अगर आज हम इस प्रदेश के 4 लाख किसानों को कनेक्शन देते हैं और उसको 75 हजार रूपये में खम्बे लगाकर लाईन ले जाना पड़े, राज्य सरकार उसके लिए अनुदान देती है अगर आप एक-एक का अनुमान लगाएं तो करोड़ों रूपये प्रतिवर्ष केवल अनुदान के रूप में कृषि पम्प की स्थापना के लिए देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ किसानों की धान खरीदी की बात करें तो जब वर्ष 2003-2004 में हमने व्यवस्थाएं संभाली और हमारी सरकार आयी। उस समय 550 रूपया समर्थन मूल्य था, अगर उस 550 रूपये के समर्थन मूल्य को बढ़ाते-बढ़ाते आज 1550 रूपये हुआ है। जब देश, केन्द्र में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की ऐसी संवेदनशील, सरकार आयी, उन्होंने ये निश्चय किया कि क्यों न, अगर इस देश के अन्नदाता किसान दु:खी हैं हम किसानों की लागत मूल्य का आंकलन करें और हम किसानों को डेढ़ से दोगुना उसकी लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य करें और उसके लिए ये पहली बार ये तय किया गया । कांग्रेस के जमाने में लगातार चिंता होती थी । वर्ष 2007 में स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट आयी और वर्ष 2007-2008 में आने के बाद इनकी सरकार लगातार वर्ष 2013 तक रही। अगर इन्हें किसानों के हित में काम करना होता या किसानों के हित में निर्णय करना होता तो पूर्ववर्ती केन्द्र की यूपीए सरकार को स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल लागू करना था। मगर उस स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ और न ही किसानों की चिंता के सदंर्भ में, किसानों की लागत मूल्य का निर्धारण स्वामी नाथन कमेटी को करने को दिया गया था, उस संदर्भ में कोई निर्णय लिया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर काम करना प्रारंभ किया और स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये निश्चय किया कि हम कैसे करके वर्ष 2022 तक किसानों को लागत मूल्य का दो गुना लाभ प्राप्त हो और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला प्रयास, किसानों की उपज के लिए करना प्रारंभ किया। हम केन्द्र की हमारी एन.डी.ए. सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट जो 8-8 साल तक केवल कचरे में धूल खाती रही, यदि कांग्रेस को किसानों की चिंता होती तो ये जो रिपोर्टें आती हैं उस पर अमल नहीं करने का किसने कहा था? लेकिन हमारी सरकार ने उसका अक्षरश: पालन किया। आखिर इस प्रकार की नीति अपनाकर, कांग्रेस की सरकार ने केवल 53-55 साल राज करने का किया किया, फिर भी इस देश के किसान बदहाली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्वतंत्रता के

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

70 सालों के बाद भी अगर किसानों की वही स्थिति है तो अगर ये चिंताजनक स्थिति किसी ने बनायी है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और कांग्रेस की सरकार ने कभी किसानों के हित में....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\12-09-2018\d10\02.05-02.10

पूर्व जारी.. श्री देवजी भाई पटेल :- कांग्रेस ने कभी किसानों के हित में चिंता नहीं की, अध्यक्ष महोदय, कई बार कहा जाता था कि कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया जाये। मगर उसमें उद्योग को दर्जा देने की अनेक संगठनों को मान्यतायें दी, कृषि को कभी उद्योग का दर्जा नहीं दिया और न ही कृषि के प्रति कभी चिंता की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने एक साथ 200 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ाया। बहुत विधवा विलाप करते हैं, मुझे बता दें कि यू.पी.ए. सरकार ने कब एक साथ 200 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ाया। पहली बार 200 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए साढ़े 1500-1570 रुपया को बढ़ाकर 1750 और 1770 रुपया करने का निश्चय किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। पहली बार ''भाजपा का कहना साफ- हर किसान का कर्जा माफ के तहत'' 6-7 सौ करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने का निर्णय श्रीमान पटवा जी की सरकार में निर्णय लिया गया। जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और जब-जब ये लोग वैराग्य में जाते हैं, तब-तब इन्हें वैराग्य होता है और किसानों की, इस देश के गरीबों की याद आती है। गरीबी हटाने का नारा देने वाली सरकार ने गरीबों को बहुत गर्त में धकेल दिया। अमीर और अमीर होते गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय बीमा तो काफी लंबे समय से हो रहा था, मगर बीमा में ऐसी विसंगतियां थीं, पहली बार प्रधानमंत्री जी ने उस बीमे की शर्तों को जो पहले ब्लाक स्तर पर होता था, पंचायत स्तर, हल्के स्तर पर गणना करने के साथ-साथ उस किसान का धान बोने से लेकर ब्यारे में आने तक और मिजाई होने तक की क्षतिपूर्ति करने का निश्चय पहली बार शर्तों में लाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि किसानों को ऐसी अनेक आपदाओं की भरपाई करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है जिसके कारण किसानों को अपनी फसल बचाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए फसल-बीमा में अमूल-चूल परिवर्तन किया गया। आज माननीय शिवरतन शर्मा जी ने कहा है यहां पर पहली बार 1100-1200 करोड़ रुपया से ज्यादा

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला। आखिर यह लाभ मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुसंगत फसल बीमा की जो शर्तें बनाई गई थीं, जिसके तहत मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसानों को 6 हजार, साढ़े 7 हजार यूनिट दिया जा रहा है। अगर हम क्षतिपूर्ति की बात करें तो नि:शुल्क बिजली में 1772 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरकार दे रही है। क्यों किसानों को हाथ में नगद दें, उसी को आप गिनोगे? क्या आप कभी आकलन किये हो कि सरकार के द्वारा विभिन्न सब्सिडीयों के माध्यम से, बिजली में विभिन्न प्रकार की सब्सिडीयों, अनुदान के माध्यम साल भर में पूरे प्रदेश में किसानों को कितना लाभ दिया जा रहा है? इसका अभी अनुमान शायद आप लगा भी नहीं सकते, इसलिए कि आपने दिया होता तो शायद इसका अनुमान लगाते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन मूल्य के साथ उनको बोनस दे रही है। मैं तो यह कहना चाहता हूं बोनस के लिए किसान, देश के अन्नदाता क्यों गिडगिडायें? यह किसानों का अधिकार है जो इस पूरे विश्व को अन्न खिला रहा है, दो वक्त का भोजन उपलब्ध करा रहा है। किसान को इतना बेबश करने का अगर किसी का दोष है और कोई ने दुष्पाप किया है तो इनकी सरकारों ने किया है। मैं यह समझता हूं कि प्रदेश में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लगातार किसानों की चिंता की। अभी मैंने बिजली की चर्चा की। अगर हम नहरों के माध्यम से सिंचाई की बात करें, यहां पर मात्र 13 प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था थी, उसको बढ़ाते हुए आज हम 20 प्रतिशत तक ला पाये। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी ने भाटापारा शाखा नहर प्रारंभ करवाई थी और भाटापारा शाखा नहर मेरे क्षेत्र से होते हुए गुजरती है और निपनिया तक लास्ट में समाप्त होती है। उस नहर का निर्माण सन् 1975 से प्रारंभ हुआ और कांग्रेस के जमाने में उसको आगे नहीं बढ़ा पाये। पटवा जी की सरकार आई, उस समय 1990 के बाद भाटापारा शाखा नहर का काम प्रारंभ हुआ। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई ... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\d11\02.10-02.15

..........जारी श्री देवजी भाई पटेल जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, फिर से वह काम बंद हो गया। ये किसानों के प्रति कितनी सहृदयता बरते हैं, यह इससे साबित होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सन 2003 में डॉ0 रमन सिंह की सरकार आई। आज पूरा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

55 किलोमीटर तक सी0सी0 लायनिंग का कार्य हो गया है और आज निपनिया के हजारों किसान उसका लाभ ले रहे हैं। साफ नीयत से काम किया जाये। किसानों को बानेस देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, किसानों के हित में बात की गई। अगर किसानों के हित की चिंता है, किसानों के हक की बात करना चाहते हो तो इतना नाटक करने की आवश्यकता क्या है ? आज आप बैलगाड़ी में आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। यू0पी0ए0 की सरकार के समय से सब्सिडी समाप्त की गई और पेट्रोल-डीजल के रेट में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से बढ़ोत्तरी होती है और रूपये के दल घटते हैं, यह आज नहीं हुआ है, यह उस समय से है। यह दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड आयल के रेट बढ़ रहे हैं उसके कारण ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। आम आदमी के जीवन यापन के लिए जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, उसके रेट को स्थिर करने का काम सरकार ने बखूबी से किया है।

समय :
2.07 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी नहरों के बारे में कहा। आपका क्षेत्र स्वयं उसका उदाहरण है। अगर हम फ्लैट रेट की बात करें, यहां किसानों की बात करें। सौर सुजला के माध्यम से और क्रेडा के माध्यम से किसानों को पम्प कनेक्शन देना है, बिजली क्रेडा के माध्यम से सौर उर्जा के माध्यम से कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका मात्र सात हजार से लेकर 20 हजार रूपये तक वो कर दिया जाए तो तीन लाख, चार लाख लगने वाला खर्चा बच जाता है। नाबार्ड के माध्यम से पांच सौ करोड़ रूपये का लोन अभी तक लिए हैं और उससे 43 हजार किसानों को सौर उर्जा के माध्यम से कनेक्शन दिए जा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, किसानों को यह जो लाभ दिया जा रहा है, उसकी गणना ये नहीं करते हैं कि किसानों को क्या लाभ दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, अगर हमने 4 लाख 73 हजार कनेक्शन दिए हैं तो इसके लिए लाईनों का विस्तार करना पड़ा है। लाईनों का विस्तार करने के लिए, किसानों के हित में लाईन विस्तार किए हैं। उसके लिए सरकार ने खर्च किया है तो यह क्या किसानों के हित में नहीं है ? माननीय सभापति महोदय, लाईन विस्तार के लिए 852 करोड़ रूपये का अनुदान दिए हैं। अभी मैंने सौर सुजला के बारे में बताया। हमने अल्पकालीन ऋण दी है। किसान बेटे के लिए, किसान परिवार के लिए हमेशा यह कहावत चरितार्थ है कि किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मर जाता है। मगर इस दंश को दूर करने के लिए देश की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आजादी के बाद किसी ने प्रयास नहीं किया कि आखिर किसान का बेटा कर्ज में क्यों मरे ? हम किसानों को कैसी सुविधाएं प्रदान करें, उसके लिए कभी प्रयास नहीं किये हैं। आज हम किसानों को साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये से अधिक के अल्पकालीन ऋण दिए हैं। मुझे भी मण्डी का अध्यक्ष होने का सौभाग्य मिला था, मुझे भी किसानों के हित में काम करने का मौका मिला था। आप भी मण्डी के अध्यक्ष रहे हैं। सन् 2001-02 में अकाल की स्थिति के समय में प्रकार पद यात्रा किये थे और पदयात्रा करके किसानों का हाल जानने के लिए जाते हैं। यह कांग्रेस की सरकार गूंगी-बहरी सरकार है, यह चिर निद्रा में सोई रहती है। किसानों की चिंता नहीं करती है। लेकिन जब-जब मुर्दा श्मशान में जाता है तब-तब वैराग्य होता है उसी तरह से उनको वैराग्य हो गया। जिस तरह जल बिल मछली होती है, उसी तरह से आज सत्ता के लिए तड़फते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इनको सत्ता की लालच इतना विवश बना देगी कि ये कुछ भी नाटक करने के लिए तैयार हो गए। ....जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\d12\02.15-02.20

जारी....श्री देवजी भाई पटेल :- यह सत्ता की लालच इनको इतनी बेबस बना देगी कि कुछ भी नाटक करने के लिए तैयार हो गये हैं । सभापति महोदय, अगर हमने जीरो परशेंट ब्याज दर पर ऋण दिया, हम बैंकों से लोन लेते हैं, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, अगर सोसायटियों को उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए अगर पांच-सात सौ करोड़ रूपया का ब्याज और क्षतिपूर्ति का अनुमान देना पड़ता है । इसको आप नहीं गिनते । यह किसानों के हित में है । किसानों की माली हालत कैसे सुधरे, उसके लिए तरह-तरह के उपाय हमें करने पड़ेंगे, अगर हम सरकार में है, हमारी जिम्मेदारी है और इसका निर्वहन हमें बखूबी करना पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय, धान बोनस का मामला आया । अगर हम आज धान बोनस की गणना करें । अगर राजस्व परिपत्र में 6 4 की गणना करें, इसके तहत गांवों में किसानों को, आम आदमी को सुविधायें देनी पड़ती है । माननीय सभापति महोदय, राजस्व परिपत्र में वर्षों से कभी सुधार नहीं हुआ । पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, मुझे याद है कि पिछले पांच-सात साल पहले जब बाढ़ की त्रासदी आई थी, अनेक मकान गिर गये थे, किसानों की क्षति हो गयी थी, ऐसे समय में राजस्व परिपत्र में पहली बार बढ़ोतरी करते हुये किसानों की या आम आदमी की, आम मजदूरी की क्षतिपूर्ति में परिवर्तन करते हुये उस क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई । इनके समय में क्षतिपूर्ति की राशि के लिए 500 रूपये, हजार रूपये लेने के लिए, किसान इतने चक्कर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लगाते थे, उससे ज्यादा खर्च हो जाता था, उसकी चप्पल घिस जाती थी । मगर आज राजस्व परिपत्र में परिवर्तन करके 600 करोड़ से ऊपर का सूखा राहत में भी 98 तहसीलों को सूखा घोषित किया गया । उसमें जो किसानों को लाभ दिया गया, आज सीधे उनके खाते में जमा किया गया, यहां पर किसानों को लेने के लिए लाईन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी । आज अगर धान के बोनस की बात करें, यहां फसल बीमा की बात करें, मैं समझता हूँ कि ऐसे अनेक परिदृश्य हैं, आज किसान अनेक फसल लेता है, धान के साथ चना, चना में भी 118 करोड़ का बोनस लगभग प्रतिवर्ष को जाता है । आज गन्ना के बोनस में लगभग 54 करोड़ का बोनस जाता है । आज हमारी चार-चार गन्ना मिले हैं । जिससे कि किसान अपने फसलों में परिवर्तन करे । किसान अपने फसल चक्र में परिवर्तन करे, किसान कैसे लाभान्वित हो सके, इसके लिये काम किया गया । माननीय सभापति महोदय, अगर हम किसानों के संदर्भ में बात करें......

श्री गिरवर जंघेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी तक 5000 किसानों को 25 करोड़ बोनस नहीं मिला । जो किसान बीज उत्पादक हैं, उनको अभी तक बोनस नहीं मिला है ।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे भी आपकी जमीन बंजर है, आप क्या किसानी करेंगे ।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी, इनके बाद आपको ही बोलना है ।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अनेक वक्ताओं ने कहा है । अभी मोहन मरकाम कह रहे थे कि यह जनता का पैसा है । आपके पास भी जनता का पैसा था, मगर जनता के पैसे का सदुपयोग करके जनता को लाभ दिलाने का काम कभी नहीं किया । यहां पर पेट में दर्द भी है । मगर खाना भी है । हमको लेना भी है । सबसे पहले कांग्रेस के लोग बोनस और सब का लाभ लेने के लिए खड़े होते हैं । आज इन्हीं के पेट में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहां पर खड़े होते हैं । अगर यह सच्चे किसानों के हितैषी होते तो इस सदन में अशासकीय संकल्प लाकर कांग्रेस के लोग जो हैं, बोनस नहीं लेगा । अगर यह किसानों के हित में नहीं है तो कर दे । अगर किसानों के हित में डॉ.रमन सिंह की सरकार जिस सहृदयता के साथ काम कर रही है, माननीय सभापति महोदय, अगर पूरे बोनस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2013 के बाद से लगातार जो बोनस देने की बात कही है, यह घड़ियाली आंसू बहाते हैं, फलाने वर्ष में नहीं दिये । वह वही बात कर सकते हैं जिन्होंने किसानों को कुछ दिया है । जिसने कुछ कभी दिया नहीं, वह याद दिला रहे हैं कि वह फलाने का नहीं दिया । आज किसानों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

को समर्थन मूल्य के खरीदी के साथ-साथ अगर देना चाह रहे हैं । उसमें भी यहां पर नाटकगिरी जिस तरह से दिखाई गई और इसको बाधित करना । माननीय सभापति महोदय, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये किसानों के इतने ही हितैषी होते.........

श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\d13\02.20-02.25

जारी........श्री देवजी भाई पटेल :- मैं तो समझता हूं अगर ये किसानों के इतने ही हितैषी होते तो यह सर्वानुमति से उसी समय पारित करके आधे घंटे में किसानों के हित में होता तो इस सदन में पारित करना चाहिए था ।

श्री अमरजीत भगत :- आप इतने बड़े हितैषी थे तो पहले क्यों नहीं लाये ? अभी आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ।

श्री देवजी भाई पटेल :- हम तो दे रहे रहे थे लेकिन आप लोगों को नाटक करने के अलावा कुछ नहीं सूझता ।

सभापति महोदय :- बैठिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बजट सत्र पूरा निकल गया, 5 साल हो गये लेकिन अभी ध्यान आ रहा है ।

सभापति महोदय :- श्री बृहस्पत जी, बोलने वालों की सूची में आपका भी नाम है, आप अभी बैठिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरा बजट सत्र निकल गया तब नहीं किया और अभी आप किसानों की चिंता कर रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये ।

श्री देवजी भाई पटेल :- किसानों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता जरूर है । यहां किसानों के हित में हो रही चर्चा को आप लोग बाधित करना चाहते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अगर बाधित करना चाहते तो आखिर यहां चर्चा करने के लिये आते ही क्यों ?

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत जी, बैठिये ।

श्री देवजी भाई पटेल :- ये किसानों का अपमान करना चाहते हैं, ये किसानों का सरासर अपमान है । आपने किसानों के साथ जो पाप किया है, उस पाप को आपको भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में, दो महीने में ही इस प्रदेश की ढ़ाई करोड़ जनता आपको जवाब देगी किसानों के हितों के लिये आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप और कितना समय लेंगे ? बोलने वालों की सूची लंबी है ।

श्री देवजी भाई पटेल :- बोलने के लिये बहुत सारा है ।

सभापति महोदय :- 5 मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री देवजी भाई पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यहां अनेक सारी योजनाओं के साथ ब्याज क्षतिपूर्ति और अगर आज तक दिये गये 300 रूपये बोनस के साथ-साथ क्षतिपूर्ति और इसका आंकलन करें तो मैं समझता हूं कि साढ़े 7 हजार करोड़ से ऊपर हमने किसानों को केवल अनुदान के रूप में या बोनस के रूप में हमारी सरकार ने दिया है । मैं समझता हूं कि इस तरह की संवेदनशील सरकार डॉ. रमन सिंह की सरकार के सिवाय और कोई नहीं दे सकते । अनेक सालों तक 53-55 सालों तक सरकार रही लेकिन कभी इन्होंने किसानों के हित में नहीं सोचा । मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास अगर धन है या सरकार अगर दे रही है यह कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन नहीं है, आपका अपना धन है, सबका धन है । आप सब मिलकर, इस सदन में बैठकर हम क्यों नहीं किसानों के हित में एक सर्वांगीण, सर्वानुमति से फैसला लें ? जब-जब किसानों की बात होती है, मैं समझता हूं कि अगर हम किसानों के हितैषी हैं तो सारा सदन एकमतेन होकर हमें इसका पालन करना चाहिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सरकार की अंतिम इच्छा क्या है, उसी को बता रहे हैं कि हमारी यह अंतिम इच्छा है उसको बता रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवजी भाई पटेल :- जनता आपसे पूछेगी कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रदेश की जनता के फैसले पर, न किसी नेता के कहने पर कोई फैसला जनता करती है, न किसी के कहने पर, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और प्रदेश की जनता आगामी समय में भी 15 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हे, गांव-गरीब और किसानों के हितों में काम किया है, आज अगर हम यह कहें, मोबाईल वितरण में भी इनको पेट में दर्द होता है कि स्काई योजना के माध्यम से किसानों के बेटे को या किसानों को या महिलाओं को मोबाईल मत मिले, आगे मत बढ़ें । सरकार की योजनाओं को मत जानें । जोगी जी की सरकार में भी पट्टा का वितरण का काम हुआ, वह पट्टा वितरण ऐसा पट्टा वितरण था जिसका न ओर न छोर न कहीं रिकॉर्ड और आज वे पट्टा लेकर घूम रहे हैं । पहली बार मैं डॉ. रमन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रचलित आबादी का प्रारंभ किया । 4 सालों में राजस्व विभाग ने पहली बार इसका सर्वे किया, अगर प्रचलित आबादी 5 एकड़ है तो 5 एकड़ में कौन-कौन बसा है, कौन-कौन बसा है तो उसकी चौदहसी बनाई गई, चौदहसी बनाने के बाद उसका रकबा नापा गया, पटवारियों को ये काम करने में 4 साल लग गये और उसके एक-एक पूरे प्रदेश के और उसके बाद उसका पट्टा बनाया गया, आज उसका पट्टा राजस्व विभाग में दर्ज है, उसका बटांकन किया गया, बटांकन के साथ पट्टा दिया गया, वह किसानों को ही दिया गया है, उसमें किसान भी है, पट्टा बटांकन के साथ-साथ हजार फीट-बारह सौ फीट में अगर उसका कब्जा है तो 1200 फीट का पट्टा दिया । हम सब जानते हैं कि पहले किसान सरकारी जमीन में बसते थे, वह प्रचलित आबादी थी, उनके पास मालिकाना हक सरकार का नहीं था । पहली बार डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने मालिकाना हक दिया । मुझे सदन में पट्टे के संदर्भ में जानकारी देनी थी कि यह पट्टा चूंकि पूर्व में हमें भी आभास नहीं था कि सरकार अगर किसी को पट्टा देता है तो 25 साल, 30 साल का पट्टा देता है लेकिन आजीवन मालिकाना हक देने का पहला अगर किसी सरकार ने काम किया तो डॉ. रमन सिंह की सरकार ने काम किया है कि मालिकाना हक दिया है । किसान जो अपनी आबादी में रहते थे, पुराने गांवों में अगर उनको संकट के समय में मान लो अपना मकान बेचना पड़ता था तो उस मकान को बेचने में केवल मलमा की रजिस्ट्री होती थी मगर अब जमीन सहित रजिस्ट्री करें मतलब एक-एक किसान को अगर उस गांव में 500 रूपये का मूल्य चल रहा है तो जमीन का रेट चल रहा है तो हजार फीट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का ....जारी

............श्री यादव

यादव\12-09-2018\d14\02.25-02.30

...........(जारी श्री देवजी भाई पटेल) :- जमीन का रेट चल रहा है तो हजार फीट का पट्टा दिया है तो सरकार ने पांच लाख रूपए इस प्रदेश के उस किसान को मुफ्त में दिया है । आज छह लाख से ऊपर किसानों को दिया गया । इससे विरला काम क्या हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह सहृदयता डॉ.रमन सिंह की सरकार में हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती । मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि इस तरह के अड़ंगेबाजी या इस तरह की [XX] [10] से काम नहीं चलेगा । मैं किसानों के हित में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अल्प चर्चा के साथ किसानों को बोनस देने के लिए सरकार, डॉ. रमन सिंह के द्वारा जो यहां पर 2400 करोड़ का अनुपूरक बजट से लाया गया, इसको सर्वानुमति से पारित करें । माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री अमरजीत भगत ।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय, सरकार बनाने के लायक बोलने का है ।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- आप चिंता मत करो । माननीय सभापति महोदय, धान की कीमत के साथ बोनस को जोड़कर किसानों को देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र का जो महत्व है और किस संबंध, तारतम्य में इसको बुलाने की आवश्यकता पड़ी, उसके संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा, कबीर दास जी की एक लाईन है कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा । आपके पास काम करने के लिए पूरा समय था ।

श्री देवजी भाई पटेल :- वह तो आपके लिए था, आपने कभी पानी पिलाया हीं नहीं, प्यासे को पानी नहीं पिलाया । अब उसके लिए चिंता करने से क्या फायदा । अब यह करने स क्या फायदा, जनता माफ नहीं करने वाली ।

श्री बृहस्पत सिंह :- भईया, आप तो पानी के बदले सरकारी दारू पिला रहे हो।

[XX] [10] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- पटेल जी, आप तो समुद्र में रहकर भी प्यासे बैठे हो।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी, आप इधर देखकर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा । (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि इनके पास काम करने के लिए पूरा समय था और उस समय काम करने के बजाए इन्होंने इधर उधर, उल जलूल में समय समाप्त किया, समय जाया किया और आज जब यह धरातल में जा रहे हैं, इनको जमीन खिसकी हुई मालूम पड़ रही है तो आज यह हो गया कि आज जो मांग, कोई किसान, कोई कर्मचारी संगठन जो भी मांग कर रहा है, ये भी ले लो, वो भी ले लो । जब आपके पास कुछ है नहीं तो क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो ? और यदि आपके पास था तो पहले क्यों नहीं दिया ? आपको करने के लिए किसने रोका था ? इस सदन में जो भी निर्णय होते हैं वह तो एक नजीर बनते हैं । आपने इस सत्र के समापन की घोषणा कर दी । आपने सबको विदाई भाषण दे दिया, इसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई कि अचानक, आनन फानन में सत्र बुलाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- यह बताओ कि जो बोनस मिलेगा, उसको आप लोगे या नहीं लोगे, इतना भर बता दो ? आप घोषणा कर दो कि नहीं लूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में घोषणा करता हूं कि जो बोनस मिलेगा, उसको मैं नहीं लूंगा ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- कब तक ?

श्री अमरजीत भगत :- मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिये जैसे लोग गैस के लिये त्याग किये, मैं अपना जो बोनस मिलेगा उसको ......(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\d15\.-.5

जारी.. श्री अमरजीत भगत :- के लिए आप लोग त्याग किए मैं अपना जो बोनस मिलेगा उसको छत्तीसगढ़ की जनता के लिए त्याग करने की घोषणा करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- वाह, वाह। और बाकी किसानों को नहीं लेने दोगे?

श्री अमरजीत भगत :- साहब, आप लोग दिखावा करते हैं, आप मजबूरी में देते हैं, आप जब फंसते हैं तब इस तरह की कार्रवाई करते हैं और हम जब करते हैं तो दिल से करते हैं। हम दिमाग से काम नहीं करते हैं, हम दिल से राजनीति करते हैं, दिल से काम करते हैं, हम किसानों के लिए दिल से लड़ते हैं। हमने शुरू से यह कहा था कि किसानों के लिए आपने जो घोषणा की है उसको पूरा करिये। आपने 2100 रूपये का जो वायदा किया था उसको दीजिए, बोनस का आपने जो वायदा किया था उसको दीजिए। आपने देने के बदले लोगों के ऊपर लाठी बरसाया। आपने किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है। जो किसान पानी मांगते थे उनको आपने लाठी मारा है। जो किसान बोनस मांगते थे उनको आपने जेल के सलाखों के पीछे डाला है। इस प्रदेश में आज तक का इतिहास है कि जितने किसान आत्महत्या की घटनाएं हुईं इसके पहले कभी नहीं हुई थीं। साहब, अगर कोई भी व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाता है तो वह तब उठाता है जब उसको दूर-दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आता है, सरकार उसके साथ खड़ी नहीं दिखती है। सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- अमरजीत जी, वह देखो कालिख लगा है।

श्री अमरजीत भगत :- ये नहीं लगा है, बैलगाड़ी में आया हूं।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- अरे वह रायपुर मेडिकल कालेज में जो कालिख लगा था, उसका बता रहा हूं।

श्री नवीन मारकंडेय :- माननीय सभापति जी, वह क्या है कि कालिख नहीं लगा है, बैल के पीछे खड़े थे तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छटारा करके तो वैसे ही पड़ गया ऐसा बता रहे हैं।

श्री सांवलाराम डाहरे :- किसान के बैल ने छटारा मार दिया।

श्री अमरजीत भगत :- आज इस प्रदेश में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह किसान है। किसान ज्यादा बारिस हुई तो परेशान, बारिस नहीं हुई तो परेशान, अगर अपने उत्पादन को खरीदी केन्द्र में बेचने गया और वह नहीं बिका तो परेशान, उसका जो खरीदने का मापदंड है वह परिवर्तित हो गया तो उसमें परेशान, आप आप रजिस्ट्रेशन कराओ, कल उसका वहां पर पंजीयन कराओ और पंजीयन नहीं कराओगे तो धान नहीं बिकेगा, साहब ऐसा लगता है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि छत्तीसगढ़ में हम लोग पैदा नहीं हुए, कहीं बाहर से आये हैं। जितनी भी नियम-प्रक्रियायें हैं, जितने भी नियम-कानून हैं सब हम लोगों के लिए हैं। लगातार किसानी का क्षेत्रफल घटता जा रहा है चाहे वह उद्योग के कारण हो, चाहे सिंचाई परियोजना के कारण हो, दिनों-दिन किसानी का रकबा घट रहा है। उत्पादन को बेचने जाता है उसका उत्पादन नहीं बिकता है और बिचौलिये के हाथों औन-पौने दाम में बेचने के लिए वह मजबूर रहता है। सभापति महोदय, इस सरकार को 15 साल हो गये। पिछले चुनाव के समय इनके घोषणा पत्र में था किन्तु 4 साल 11 महीने बीत गये, अंतिम समय में आपको ध्यान आया कि इनको बोनस नहीं देंगे तो लोग घेरेंगे? हम कहीं भी धान की कीमत बढ़ाने के खिलाफ नहीं हैं, कहीं भी धान के बोनस देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो सोच है, आपका जो लागू करने का तरीका है उसके खिलाफ हैं। इसको पहले मिलना चाहिए था। किसान कर्ज में डूबा हुआ है, आज किसान की जमीन नीलाम होने की स्थिति में है, बैंक का नोटिस जा रहा है लोग कर्ज में दब रहे हैं और किसी न किसी सेठ, साहूकार के यहां से फिर कर्ज लेकर उसको पटा रहे हैं तो कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा, किसान की माली हालत दिनों दिन खराब हो रही है। आप जितना दे सकते हैं किसानों के लिए दीजिए कहीं भी उसका कोई विरोध नहीं है लेकिन बात यह है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है।

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\d16\02.35-02.40

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- यह बताओ, इसको तुम्हारे पुराने वाले नेताजी ने लिखकर दिया या नए वाले ने ?

श्री अमरजीत भगत :- सरकार स्कूल खोले, सरकार अस्पताल खोले, लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाए, कहीं कोई विरोध नहीं है साहब । लेकिन विरोध तब शुरू होता है जब सरकार स्कूलें बंद करना शुरू कर देती है, शैक्षणिक संस्थाएं बंद करना शुरू कर देती है । आदिवासी अंचलों में 3000 स्कूलें बंद कर दी गईं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे साहब ? आदिवासी अंचलों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कैसे होगा ? उन क्षेत्रों की चिंता कौन करेगा, जहां इस प्रदेश के लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिये गये और सरकार को जो काम नहीं करना चाहिए उसमें खूब मुस्तैदी दिखाती है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नवीन मारकंडेय :- सभापति जी, सरगुजा संभाग में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और महाराज ने सीतापुर को कॉलेज वगैरह दिया या नहीं ?

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय सभापति महोदय, सरकार स्कूल चलाने और खोलने के बजाय शराब दुकान चला रही है । यह सरकार बहुत सैद्धान्तिक बातें करती है । कमला वाहिनी समूह बनाकर शराब बंदी की बात करती है और स्वयं शराब दुकान चलाती है साहब । इनकी कथनी और करनी में अंतर है । इनकी सोच में अंतर है साहब । आज किसान परेशान है । काश, जिस प्रकार का विशेष सत्र आपने आज बुलाया, आदिवासियों के मामले में भी आपने बुलाया होता । जब आपने भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल लाया था । 165 क में परिवर्तन, आदिवासियों की जमीनों को सहमति के आधार पर सरकार ले सकती है, यह विधेयक भी इसी सत्र में आया था और हम लोगों ने बहुत विरोध किया और मना किया कि आप जो विधेयक ला रहे हैं यह आदिवासियों के हित में नहीं है । इसको आप वापस ले लीजिए । लेकिन उस समय भी जो मुस्तैदी आप लोगों ने दिखाई उसके पीछे आपने जो कसीदे पढ़े, आपने पढ़ा वह तो समझ में आया पांडे जी, लेकिन हमारे जो आदिवासी सदस्य थे उनको भी आपने इतना मजबूर कर दिया, इतना बेबस कर दिया कि वे भी उस विधेयक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए । इसी सदन में आदिवासियों के अधिकार को छीनने के लिए कानून पास किया गया । मैं कांग्रेस पक्ष के सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और सदन से लेकर राजभवन तक आप लोगों ने उस विधेयक को रूकवाने के लिए मदद की । जिस प्रकार से सामाजिक रूप से उस विधेयक का विरोध हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जगह-जगह घिरते हुए नज़र आए, तब जाकर उस कानून को वापस लिया गया । उसे भी वापस नहीं लिया गया बल्कि ठंडे बस्ते में डाला गया है, कब आपका मन बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है । जल, जंगल और जमीन जो आदिवासियों का अधिकार है, उससे भी उन्हें बेदखल करने की कोशिश की है । सभापति महोदय, इस राज्य में ही नहीं, जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई चरम पर है, उससे जनता में हाहाकार मचा हुआ है । जिस प्रकार नोटबंदी और जीएसटी से लोगों का हाल बेहाल हुआ है । चाहे वह व्यवसायी हो, किसान हो या बेरोजगार हो सभी के ऊपर विपरीत असर पड़ा है । सभापति महोदय, डीजल पेट्रोल की दर 80 के पार हो गई है.................................जारी

- श्री अग्रवाल --

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अग्रवाल\12-09-2018\d17\2.40-45

जारी....श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, डीजल-पेट्रोल की दर 80 रूपये से पार हो गई है, रसोई गैस जो कांग्रेस के समय 400 रूपए था और 450 रूपए हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य से लेकर केन्द्र तक के नेता जिस प्रकार से तांडव और आन्दोलन किये थे, वह देखने लायक था । आज वह दोगुना बढ़ गया है । 400 रूपये से 900 रूपये पहुंच गया है, आपने लोगों को गैस दिया, उसकी रिफिलिंग नहीं हो रही है । आज जनता किसके पास जाएगी। जी.एस.टी. को इसके दायरे में क्यों नहीं लाते हैं ? बहुत सारा राज्य है, जहां पर पेट्रोल और डीजल पर उन्होंने रिबेट दिया है । आपका राज्य क्यों नहीं देता है ? हमारे सामने जो छोटे-छोटे देश हैं, पाकिस्तान जैसा देश, नेपाल जैसा देश, जहां पेट्रोल और डीजल भारत से सस्ता बिक रहा है, ये हमारे लिए लज्जा की बात है और इसमें सरकार को अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में सड़कों की स्थिति क्या है ? सड़कें 15-15 दिन बंद हो रही हैं, किसी भी प्रदेश का स्टेटस वहां की सड़कों से होता है, जहां की सड़कें अच्छी रहती हैं, उसको विकास के पैमाने में माना जाता है कि यह प्रदेश विकास किया, केवल रायपुर की सड़क बना देने से, केवल नये राजधानी में सड़क बना देने से पूरे प्रदेश में सड़क बन गई है, ऐसी बात नहीं है ।

सभापति महोदय :- अमरजीत जी, आप वरिष्ठ विधायक हैं । एक तो विषय पर बोलें, जो अनुपूरक बजट है और संक्षेप में अपनी बात करें, यह मेरा निवेदन है । आपको बोलते हुए 15 मिनट से ऊपर हो गए हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूं । सड़क भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा ही है, उस सड़क में किसान ही चलते हैं, उस सड़क में यहां के लोग ही चलते हैं, जहां सप्ताह, 15 दिन तक सड़कें बंद हो जाएं । अम्बिकापुर से सीतापुर, अम्बिकापुर से रायगढ़, अम्बिकापुर से जशपुर, अम्बिकापुर से राजधानी रायपुर की सड़क सब तो बंद रहती है । न जहां पर एम्बुलेंस जा पा रही है, न जहां पर बस जा पा रही है, न जहां पर लोग सफर कर पा रहे हैं, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और आप दूसरी तरफ विकास यात्रा निकालते हैं । लोग डेंगू से, मलेरिया से मर रहे हैं, मंत्रियों का जवाब इतना हल्का आ रहा है कि समय पर हॉस्पिटल नहीं है, सरकार क्या कर रही है, आप बैठकर क्या कर रहे हैं । आप केवल सत्ता का मजा ले

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं, आप की जवाबदारी नहीं बनती है क्या ? अगर एक भी जान कहीं पर जाए तो सरकार की नैतिक जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है कि एक भी जान न जाए और जहां पर भी बीमारी फैल रही है, जहां पर भी बाढ़ की स्थिति आ रही है, जहां पर भी सड़क बंद हो रही है, उसमें सरकार को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । इस प्रदेश में केवल वोट की राजनीति हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, वह केवल वोट लेने के लिए हो रहे हैं। सत्रावसान के बाद भी आप सत्र बुला लेते हैं । बस्तर में जो घटना हो रही है, उसके बारे में सत्र बुला लेते, कभी हाथी के चपेट में आकर बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी सत्र बुला लेते, हमको भी अच्छा लगता कि सबके ऊपर सरकार का ध्यान है, सबके प्रति समान रूप से भावना है ।

माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रदेश में कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर प्राकृतिक आपदा हो जाए, इनसे निपटने के लिए सरकार के पास कोई टीम नहीं है, उसके लिए मुस्तैदी नहीं है, उनके पास कोई तैयारी नहीं है । रायपुर में गर्मी के समय आग लग गई थी, लोग जलकर मर गए, बचाने के लिए सरकार के पास कोई कारगर उपाय नहीं था, कहीं पर बाढ़ आ गया तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है । डेंगू से, डायरिया से, मलेरिया से हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं । सरकार केवल ऊल-जलूल काम कर रही है, त्यौहार मना रही है ।.....

श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\d18\02.45-02.50

जारी... श्री अमरजीत भगत :- सरकार केवल त्यौहार मना रही है। अभी तक हम जानते थे कि दीपावली होती है, दशहरा, होली, पोला, हरियाली होती है, लेकिन हर महीने में नया-नया त्यौहार? और त्यौहार भी क्या बिजली तिहार मना रहे हैं? गांव में तो बिजली रहती नहीं साहब। ट्रांसफार्मर खराब हो गया है तो उसको बदलने वाला कोई नहीं और बिजली के बिल में रिकार्ड बढ़ोत्तरी, लोग परेशान हैं।

श्री नवीन मारकण्डेय :- अमरजीत जी, आप बोनस तिहार में गये थे या नहीं गये थे?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अब एक नया ले आया है सेल्फ असेसमेंट। आपको पहले किसने मना किया था? आप सेल्फ असेसमेंट लाये हैं कि सिर्फ सौ रुपये में आपका बिजली का बिल हो जायेगा। साहब, यह कितने दिन तक रहेगा? तीन महीना। केवल चुनाव तक। चुनाव के बाद क्या होगा? फिर बढ़ा हुआ पूरा जोड़कर आप बिजली का बिल भेजेंगे। आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो योजना है, वह साफ होनी चाहिए। आप मोबाइल बांट रहे हैं। मोबाइल बांटने का कहीं कोई विरोध नहीं है, बांटिये, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मोबाइल बांटिये, स्टैण्डर्ड मोबाइल बांटिये। आप ये क्या बांट रहे हैं, जगह-जगह मोबाइल फट रहे हैं? प्रतापपुर में एक जगह मोबाइल विस्फोट कर गया, उससे पूरा घर जल गया। आप लोगों को जिंदा बम बांट रहे हैं। उससे जो नुकसान होगा...

श्री लाभचंद बाफना :- अमरजीत भैया, खाली मोबाइल तिहार नहीं, हम बोनस तिहार भी, चाउर तिहार भी, बिजली तिहार भी और उज्ज्वला योजना तिहार भी मना रहे हैं।

सभापति महोदय :- मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि अनुपूरक मांगों की बजट के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित था और लगभग पौने चार घंटे की चर्चा हो चुकी है और अभी 16 सदस्यों को बोलना है। उन 16 सदस्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी सम्मिलित हैं। जो समय निर्धारित है, उससे लगभग एक घंटे हम ज्यादा बोल चुके हैं। मेरा निवेदन है कि बातों की पुनरावृत्ति ना हो और सारे सदस्य 5 मिनट में अपने विषय को समाप्त करें। अमरजीत जी, आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति जी, बाकी लोग टोका-टाकी कर के मेरा समय ले लेते हैं, उसका क्या है?

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में समाप्त करें। वैसे आपको बोलते हुए 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह बोल रहा था कि ये जो मोबाइल वितरण हो रहा है, वह बहुत ही हल्के किस्म का हो रहा है और इसमें केवल कमिशनखोरी हुई है। जहां पर भी विस्फोट हो रहा है, जान-माल को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मोबाइल कंपनी के ऊपर जवाबदारी निहित होनी चाहिए कि जहां भी नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई वह करे और जहां

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी विस्फोट हो रहा है, 50 लाख रुपया उनको मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए तब तो आपकी यह योजना ठीक है, नहीं तो आपने तो लोगों को जिंदा बम दे दिया। कहीं किसी का हाथ उड़ रहा है तो कहीं किसी का घर उड़ रहा है । उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार उसकी जवाबदारी ले और उसकी भरपाई करने की गारंटी दे तब तो ठीक है साहब। नहीं तो आपने तो जनता के हाथ में जिंदा बम दे दिया, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है। प्रतापपुर में एक जगह विस्फोट हुआ तो पूरा घर जल गया।

गृहमंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रतापपुर का उल्लेख किया है। मैंने पता लगाया है। वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेसियों द्वारा इसे बदनाम करने के लिए यह साजिश की गई है। प्रतापपुर में न कोई बम फटा है, न कोई मोबाइल फटा है।

श्री अमरजीत भगत :- घोषणा कर दीजिए कि जहां भी होगा, हम उसकी भरपाई करेंगे।

श्री रामसेवक पैकरा :- जैसा कि आपने आरोप लगाया, ऐसा कहीं भी नहीं है। आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने साजिश की है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, मोबाइल लेने वाले आपके क्षेत्र के लोग आपको खोज रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आज जिन कर्मचारियों को 7वां वेतन का लाभ मिलना था, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। अभी एक दिन पहले की बात है, कालेज के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को कालेज बंद कर के यहां बुलाया गया था। खाली तुम लोग मांग करो तो हम घोषणा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये क्या चल रहा है? शैक्षणिक संस्थान बंद हो जाएं, कालेज बंद हो जाएं, उनको हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित करना कि तुम लोग मांग करो, हम लोग उस मांग को पूरा करेंगे। देना है तो सीधा दीजिए और जहां-जहां वेतन विसंगति है, उसको दूर करिये। चाहे वह तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हो, चाहे कोई भी कर्मचारी संघ हो, उसको पूरा करिये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्रीमती सविता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सविता\12-09-2018\d19\02.50-02.55

श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे (अहिवारा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी द्वारा वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांग दो हजार, चार सौ तैंतीस करोड़, अठ्हत्तर लाख, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि की मांग की गई है, इस मांग के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब वर्ष 2004-05 में छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी तो उनके पास कई कठिनाईयां थीं, उनको विरासत में कई विकराल समस्याएं जैसे भूख, गरीबी, महंगाई, पलायन और नक्सलवाद मिली थी। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनें तो उनके पास इन समस्याओं का अंबार था, वे सोचते रहे होंगे कि मैं इन कामों की शुरूआत कहां से करूं।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय सांवला राम जी, जो विरासत में समस्याएं मिली हैं उसको आप बढ़ाये हैं या घटाएं हैं ?

सभापति महोदय :- माननीय केशव चन्द्रा जी, इसके बाद आपको ही बोलना है।

श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे :- माननीय सभापति महोदय, हमें विरासत में ये तमाम् समस्याएं मिली थीं और उन समस्याओं के समाधान की शुरूआत मैं कहां से करूं, नि:संदेह हमारे मुख्यमंत्री जी कई-कई रात नहीं सोये होंगे। वे बातें अच्छी तरह याद है कि इस प्रदेश के कई हजार लाखों लोग भूख से पीड़ित थे, डॉ. रमन सिंह जी सबसे प्रथम अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त करते हुए, इस बात की गंभीरता को उनने बड़ी गहराई से लिया कि चाहे प्रदेश में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने प्रदेश की जनता को भूख से मरने नहीं दूंगा और इसीलिए खाद्यान्न जैसी योजना निकाले।

माननीय सभापति महोदय, मैं बार-बार एक बात को कहता हूँ कि विरासत में जितनी हमको ये समस्याएं मिली थीं, उनके संदर्भ में वे बातें मुझको याद आती है कि

"भूख गरीबी और महंगाई, इश्क मुझसे करती थी ।।
एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मरती थी।"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इतनी विकराल समस्या में डॉ. रमन सिंह जी ने इस प्रदेश के 60 लाख लोगों के घरों में 1 रूपये किलो में चावल पहुँचाया। आज मैं डॉ. साहब को और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को अपने प्रदेश के उन किसानों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज किसानों के हित की चिन्ता करते हुए, ये दो दिवसीय विशेष सत्र यहां पर आमंत्रित किया गया है। हमारे पार्टी के साथ-साथ, मैं विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे सत्रों का भरपूर रूप से सहयोग करना चाहिए। जिस सत्र में प्रदेश के उन अन्नदाता किसानों के बारे में चिन्तन किया जा रहा है और ऐसी चिन्तन की अवस्था में बैलगाड़ियों से यहां पर आने का एक नया तरीका, नया आयाम खोजा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कल के समाचार पत्र में ये हेड लाईन होगा कि ''उनके लाल गमझे को देखकर के किसान के बैल बिदगे और किसानों के बैल ने कांग्रेसियों को मारा छटारा''। ये कल का हेड लाईन होगा, जहां पर इस प्रदेश के अन्नदाताओं के बारे में चिन्तन किया जा रहा है उनके हितों के बारे में सोचा जा रहा है, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में एक नये तरीके को निकालना बड़ा हस्यास्पद लगता है। यदि इन तमाम् बातों को आप लोग शुरू में ही समाधान कर लिये होते तो आज भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसानों के बारे में आप लोगों को पर्याप्त सोचने, विचार और चिन्तन के लिए समय मिला।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सांवला जी, आप जितना बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री राजमहंत सांवला राम डाहरे :- माननीय सभापति महोदय, इस देश और प्रदेश की जनता ने आप लोगों को बहुत समय दिया था, अपार समय दिया था, लेकिन समय का जो सदुपयोग, आम जनता के लिए जो सोच होनी चाहिए थी, वह सोच आप लोगों में नहीं आ पायी और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आयी और आज लगातार कहते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है ? एक-एक परिवार 7, 8, 9 योजनाओं से लाभांवित हो रहे हैं, वे किसान ही तो हैं ...

जारी श्री चौधरी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चौधरी\12-09-2018\e10\02.55-02.60

पूर्व जारी.. श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- वह किसान ही तो हैं, जो 1 रुपये किलो में चावल खा रहे हों, चाहे स्मार्टफोन ले रहे हों, स्मार्ट कार्ड बनवा रहे हों, सुरक्षा योजनाओं की तमाम पेन्शन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हों। ये वही किसान हैं जिनको बिना ब्याज के ऋण दिया जा रहा है। तमाम जितनी भी योजनायें हैं चाहे वह लघु-सीमान्त किसान योजना, शाकम्भरी योजना, किसान समृद्धि योजना तक जितनी भी योजनायें मिली हैं इन योजनाओं का लाभ कहीं न कहीं हमारे किसान परिवार को मिल रहा है। आज हम उन किसानों की बेहतरी को देखें, उन किसानों के बारे में सोचें कि उन किसानों की आज से 15 साल पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में कितना बेहतर है। हम इसको सोचते हैं। हमारे विपक्षी साथी भी इस बात को जानते हैं कि आज किसान बहुत बेहतर हैं, बहुत खुशहाल हैं। उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। उनकी तमाम आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। किसानों की आय में वृद्धि हुई है, किसान का जीवन बेहतर हुआ है। इन तमाम बातों को हमारे विपक्ष के साथी भी बखूबी जानते हैं। सभापति महोदय, सवाल यह खड़ा होता है कि वह सच बोल नहीं सकते। आप सच नहीं बोल सकते। आप सच कभी बोल नहीं पायेंगे। आज सच बोलते, आज कांग्रेस पार्टी के इतने लोगों ने भाषण दिया, कोई एक पार्टी के एक व्यक्ति ने कह दिया होता कि विशेष सत्र उन किसानों के हितों के लिए बुलाया गया है, डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। यह बात होनी थी। किसानों के लिए यह बात क्यों नहीं आ रही है? जब किसानों को बोनस देने की बात आई तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग यह नया तरीका खोज लिये। आप लोग भी किसानों के हित की बात करते हैं, हम भी किसानों के हित की बात करते हैं। चलिये, सदन में आप लोग भी बैठे हैं तो सदन में आप लोगों को कहना चाहिए था कि किसानों के हित की बात इस सत्र में की जा रही है इसलिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का एक शब्द नहीं मिला, ऊपर से आप लोगों को जिस विषय पर बोलना था, उस विषय पर नहीं बोल करके सड़क, पानी पर आ गये। इस सरकार ने किसानों के लिए जो लगातार काम किया है, उसको सभी जानते हैं। हमारी सरकार किसानों को एक अन्नदाता के रूप में स्वीकार करती है। एक अन्नदाता मानती है। मुझे छत्तीसगढ़ गीत की एक पंक्ति याद आती है-

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

धन्य-धन्य रे मोर किसान, धन्य-धन्य रे मोर जवान,

तोला तो मैं जानेव संगी, तोला तो मैं मानेव संगी, तैहां धुईयां के भगवान।

हम जिसको भुईयां के भगवान मानते हैं, अन्नदाता मानते हैं, उस अन्नदाता के प्रति चिंतन नहीं करेंगे, ऐसी कोई सरकार नहीं होगी। जिस प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान रहते हों और उन किसानों के बारे में कोई सरकार चिंतन न करे, उनकी बेहतरी के बारे में न सोचे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग सच बोल नहीं सकते। आप लोग सच बोलने के लिए अवतरित हुए ही नहीं हैं। यदि आपने सच कह दिया तो आपका अवतरण भी व्यर्थ होगा। आप लोग केवल सत्तापक्ष के लोगों की, सरकार की किसी न किसी प्रकार की आलोचना करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए आज जो प्रदेश के किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं, विशुद्ध किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी कभी पंच नहीं रहे, कभी पार्षद नहीं रहे, विशुद्ध किसान था और अभी हैं। इन लोगों को मैं कई बार इस सदन में कह चुका था किसानी के बारे में कोई- कोई जानते हैं। हमारे अमरजीत जी बोल रहे थे कि यहां पर चिखला हो गया। सभापति महोदय, चार बार बोले होंगे। किसानी करने जाओगे, बैलगाड़ी में बैठोगे तो चिखला तो होगा तो फिर चिखला से क्यों डर रहे हो? बैलगाड़ी में बैठोगे, किसानी करने जाओगे तो चिखला होगा, पिट्टी होगी।

सभापति महोदय :- सांवलाराम जी संक्षेप में दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापति महोदय, बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूं। हमारी सरकार ने लगातार किसानो की बेहतरी के लिए चाहे किसी भी योजना के तहत हो, किसान समृद्धि योजना के तहत .... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\e11\03.00-03.5

..........जारी श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे किसान समृद्धि योजना के तहत इन 15 वर्षों में 63,409 नलकूप, यह एक ऐतिहासिक चीज है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, नलकूप के उत्खनन के लिए सरकार राशि दे रही है। शाकम्भरी योजना के तहत लघु सीमान्त किसानों को दे रही है। उसके साथ-साथ कृषि से जुड़े हुए पशुधन के लिए, उनके विकास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उसके साथ-साथ किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हम सब लोगों ने विशेष सत्र बुलाया और विशेष सत्र बुलाकर के किसानों के हित की बातें की तो आप लोगों के पेट में दर्द हो गया। आप लोगों को चिंता हो गई। कहीं न कहीं आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है और यह बौखलाहट है। माननीय सभापति महोदय, यह सच बात है, ध्रुव सत्य है, इसमें न्यूटन का तीसरा सिद्धांत भी लागू होता है कि जब दीया बुझने लगता है तो इसी तरह फड़फड़ाता है। आप इन लोगों की फड़फड़ाहट हो देख लीजिये। हमारी सरकार ने लगातार उन किसानों को अनुदान देकर, डबरी बनाकर तालाब बनाकर कार्य किया है। वनोपज के लिए ऐतिहासिक काम बोनस देकर हमारी सरकार ने किया है। वह अपने आप में अद्भुत और अनूठा है। ये तमाम विकास के काम इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है।

सभापति महोदय :- समाप्त करें।

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी समाप्त करता हूं। कई सारी बातें आईं। एक लाईन मैं जो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज उसको अवश्य बोलूंगा। यहां शराब की बातें आईं, शराब पिला रहे हैं। 53 साल तक किसने शराब पिलाया ? 53 साल तक इस प्रदेश के वातावरण को किसने मदहोश किया ? ये 14 साल की बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 53 साल तक आप सब लोगों ने इस प्रदेश के संपूर्ण वातावरण को मदहोश वातावरण कर दिया और इस मदहोश वातावरण में यहां के लोगों को जीने के लिए, जन्म लेने के लिए आप लोगों ने विवश किया। काश, आप लोग उस समय रोक लगा दिए होते तो आज पूरा प्रदेश नशामुक्त प्रदेश होता। लेकिन उस दिशा में हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर आज यहां पर चर्चा चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। कहां की बेरोजगारी की बात ? लाईवलीवुड के माध्यम से पूरे प्रदेश में कम पढ़े-लिखे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको नौकरियां दी जा रही है। उनके काम की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुदान की राशि मांगी गई है, उसको सर्वसम्मति से पास करने के लिए पूरे पक्ष और विपक्ष अपील और निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

.....श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\e12\03.05-03.10

जारी.....श्री सॉवलाराम डाहरे :- तमाम बातों को लेकर आज जो यहां पर चर्चा चल रही है माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, कहां की बेरोजगारी की बात है । लाइवलीहुड के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको नौकरियां दी जा रही है, उनके काम की व्यवस्थायें की जा रही है । माननीय सभापति महोदय, इस तरह मैं आज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो अनुदान की राशि यहां पर मांगी गई है, उनको सर्वसम्मति से मैं पास करने के लिए पूरे पक्ष और विपक्ष से अपील और निवेदन करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ । आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री वृहस्पत सिंह । संक्षिप्त में पांच मिनट में समाप्त करेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार सुनहरे अक्षरों में लिखा जायेगा कि छत्तीसगढ़ की विधान सभा में पांच साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद, सारे लोगों को पुरस्कार दे दिये गये, इनाम दे दिये गये, सत्ता और विपक्ष के साथ मंत्रियों ने गले लगकर रोया कि हमारे पांच साल बीत गये हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, वापस आयेंगे कि नहीं, राज्यपाल महोदय सारे को ससम्मान विदाई कर दिये । इसके बाद तब तक सरकार को बोनस का नाम याद नहीं आया । सुनकर आश्चर्य लगता है । जब हम सारे लोग अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में चले गये, इसके बाद सरकार का एक फरमान जाता है कि विशेष सत्र दो दिन के लिए बुलाया गया है । यह छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । सभापति महोदय, इस सरकार ने वर्ष 2013 में घोषणा की है कि हम 2100 रूपये धान की कीमत किसानों को देंगे । एक-एक दाना धान खरीदेंगे और तीन सौ रूपये बोनस भी देंगे । सभापति महोदय, यह सरकार पांच सालों तक किसानों को धोखा देता रहा, छलावा करता रहा । किसान नारेबाजी करते रहे, आंदोलन करते रहे, लाठियों से पीटा जाता रहा, जेल भेजा जाता रहा, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है । इस सरकार को शर्मसार हो जाना चाहिये था । और तो और इस साल भी सरकार के पांच वर्ष पूरे होने लगे, सरकार ने मार्च में बजट लाया, उसमें भी सरकार को याद नहीं आया । जब वर्षाकालीन सत्र में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अनुपूरक बजट आया, तब भी सरकार को सुध नहीं आई, अभी इनको लगा, हरेक गांव में विकास यात्रा लेकर जब जाने लगे, किसानों ने इनको सीधे गो-बैक बोल दिया । पांच साल तक तुने धोखा दिया है, आज शकल दिखाने आये हो । माननीय सभापति महोदय, ऐसा जवाब दिया गया, तब सरकार को होश आया है, तब इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी भूल हुई है, कोई उपाय लगाओ । तब इन्होंने बोनस लाया है । आपको कौन मना किया था । आप पांच साल तक बोनस क्यों नही दिये ? क्यों 2100 रूपये का समर्थन दिये ? किसने रोका ? किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी । हम लोगों ने तो किसानों के साथ खड़े होकर आपसे निवेदन किया था। दिल्ली तक मांगने गये, दिल्ली में भी आपकी सरकार ने हमारे कांग्रेस विधायकों को, सांसदों को जेल भेज दिया । लेकिन आपने एक नहीं सुना, क्योंकि आपके ऊपर घमण्ड हो गया है कि हमने 15 साल तक राज किया है । इस बात का घमण्ड सर चढ़ कर बोल रहा है । सभापति महोदय, इसलिए यह नौबत आज आई है । सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में मक्के की खरीदी होती है । आपने 1450 रूपये निर्धारण किया लेकिन एक मक्का नहीं खरीदा । आपके सत्ता पक्ष के जो व्यापारी हैं, उनसे खरीदी करके उसे पूरा किया गया । सरगुजा, बस्तर के किसान बिचौलियों के हाथों में बेचने के लिए मजबूर हो गया । लेकिन एक नहीं खरीदा गया, सभापति महोदय । यह बड़ा दुखदायी है । समय आने पर किसान जवाब देगा । सभापति महोदय, किसानों की हम बात करें, कांग्रेस सरकार में पांच एच.पी. तक फ्री था । सभापति महोदय, कोई बिजली बिल नहीं होता था । आपकी सरकार आते ही उस पर बिजली बिल लाद दिया और तो और बिजली बिल चालू कर दिया । बिजली बिल का कनेक्शन जब किसान लेता था, एक लाख पच्चीस हजार तक 4 वोल्ट तक उसको अनुदान मिलता था । वह भी आपने बन्द कर दिया, क्योंकि आपकी सरकार की नीयत खराब थी । सरकार का यह नीयत खराब होना, बहुत आश्चर्य लगता है । जो किसान आपके लिए दाना पैदा करता है, उसके कनेक्शन की व्यवस्था थी, वर्षों तक चला आ रहा था, उसको भी आपने सब्सीडी रोक दिया । छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष के लोगों का सौर उर्जा की फैक्टरी खुल गयी । सरकार में बैठे लोगों का, मंत्रियों का पार्टनरशिप में फैक्टरी खुल गया । उसको बढ़ावा देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, उसको पांच लाख तक सब्सीडी दे रहे हैं । किसान बिजली पम्प कनेक्शन ले रहा है, उसका नुकसान कर रहे हैं । इसलिए कि आपके सरकार के लोगों ने फैक्टरी खोल रखे हैं । उसका मार्केट बनाने के लिए आपने बन्द कर दिया । सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । इसका समय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आने पर जनता जवाब देगी । सभापति महोदय, यह सौर उर्जा का आपने जो चालू किया है, बिजली पम्प हम लेंगे, एक-सवा लाख में आपने बंद कर दिया । यह बहुत गंभीर बाता है । किसान जब ट्रेक्टर लेकर खेती करने जाता है, पेट्रोल पम्प वाला उधारी नही देता है । डीजल उधारी नहीं मिलता । धान बेचकर किसान डीजल भरता है । खुद भरकर जाता है किसान, मुझे मालूम है । सभापति महोदय, 55 रूपया डीजल था, उस समय इसी सदन में डॉ.रमन सिंह जी और बृजमोहन अग्रवाल जी सायकल चलाते हुये आये थे, जब 55 रूपया डीजल था । अभी भी फोटोग्राफ है । सभापति महोदय, आज जब आपकी सरकार आई तो आपने इसको 75 रूपया कर दिया । पेट्रोल 60 रूपया था, साहब । वहां आपने 85 रूपया कर दिया । मिट्टी तेल जो घर-घर में दीपक जलाने का काम आता है, उसे 10 रूपये से बढ़ाकर आपने 30 रूपया कर दिया । यह कैसी खेल चल रहा है । गैस सिलेण्डर 450 रूपया, दिल्ली से लेकर यहां तक आंदोलन करते हैं। आज यह 900 रूपया हो गया है और आप चुप हैं ? आप बड़े वाहवाही लूट रहे हैं । आप यह क्या कर रहे हैं ? बड़ा आश्चर्य लगता है । जो छत्तीसगढ़ का किसान, हिन्दुस्तान का किसान गाढ़ी कमाई करती है, उसमें 46 परशेंट आप टैक्स वसूल रहे हैं । आप किसानों के पाकेट से लूट रहे हैं । आप 46 परशेंट कमीशन खा रहे हैं । मैं मानता हूँ कि अरब देश की खाड़ी से डीजल आता है, हमारे हिन्दुस्तान में पैदा नहीं होता, कमीशन खाने का हक आपको किसने दिया? 46 परशेंट कमीशन खाकर आप इतने महंगे तेल बेच रहे हैं । जनता को लूट रहे हैं । छत्तीसगढ़ की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार इस तरह का कार्य कर रही है....

जारी...श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\e13\03.10-03.15

जारी...........श्री बृहस्पत सिंह :- इतना महंगा तेल बेच रहे हैं और जनता के पॉकेट से लूट रहे हैं, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार यही कर रही है । मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आपको बताउंगा कि इसी पवित्र सदन में जब वर्षाकालीन सत्र आया आपने अनुपूरक बजट के माध्यम से, संचार व्यवस्था सुधारने के लिये 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया इसी पवित्र सदन में मात्र 80 करोड़ । आज आपने मोबाईल खरीदी 22 अरब 70 करोड़ का आप मोबाईल खरीद रहे हो, 22 अरब 70 करोड़ का आपकी सरकार बता रही है । मोबाईल में आप किस तरह का घोटाला कर रहे हैं ? जब हम यह मोबाईल खरीदते हैं तो यह मोबाईल 1000-1200 का आता है, जितने घंटे चाहते हैं बात करते हैं अगर रात में चार्जिंग में लगाकर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम सो जाते हैं और सुबह 8-10 बजे भी उठाते हैं तो कभी मोबाईल फटता नहीं है, कभी गरम नहीं होता और आपका मोबाईल गरम होने के साथ ही, बात करने के साथ ही फट जा रहा है । लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जब हम मार्केट में मोबाईल खरीदते हैं तो उसमें 35 परसेंट सरकार का टैक्स होता है । अगर हम 2000 का मोबाईल खरीदते हैं तो 700 रूपये केवल सरकार का टैक्स होता है मतलब 1300 का मोबाईल आता है । जो मोबाईल सरकार बांट रही है उसकी कीमत मात्र 1300 है, टैक्स फ्री कर दें, अगर टैक्स जोड़कर भी लगाते हैं तो 2000 है लेकिन आप उस मोबाईल को कितने में खरीद रहे हैं 4499, 4299 और आपने पूरा कितना खरीदा 22 अरब 70 करोड़ का अगर 50 परसेंट भी आपने गड़बड़ किया तो सीधा-सीधा 11 अरब 35 करोड़ का आपने घोटाला किया और लोगों का लूटा, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटा यह मोबाईल दिखाकर, यह नकली मोबाईल दिखाकर । अगर गांव का आदमी वृद्धापेंशन लेने जाता है कोई बुजुर्ग जिसको आप वृद्धापेंशन सहायता कहते हैं साढ़े 300 रूपये देते हैं, उसको भी आप खाते में डालते हैं । वह बुजुर्ग डंडा पकड़कर बैंक तक जाता है, पोस्टऑफिस तक जाता है, अगर नरेगा में मजदूरी करता है तो उनकी मजदूरी भी आप बैंक के खाते से पेमेंट करते हैं, अगर तेंदूपत्ता संग्राहक है तो उसका भी खाते से भुगतान करते हैं और उसकी बोनस की राशि भी आप खाते से भुगतान करते हैं और 300-350 रूपये आप नगदी नहीं दे सकते, आप खाते से लेते हैं और 22 अरब का खरीदने के लिये आप उनके खाते में क्यों नहीं डाल देते । उनके खाते खुले हुए हैं, उनके एकाउंट खुले हुए हैं । आधार लिंक है, जिनको देना है, उनके खाते में आप क्यों नहीं डाल देते, वह पसंद का मोबाईल खरीद लेता लेकिन सरकार की सच्चाई तो यह है कि यह 11 अरब 35 करोड़ का घोटाला आपने किया है इसीलिये इस सरकार ने गड़बड़ किया है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए । छत्तीसगढ़ की जनता पहचान चुकी है कि आपने 2000 का मोबाईल 4000 में खरीदकर 50 परसेंट 11 अरब 37 करोड़ का घोटाला किया है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट । सरकार के विरोध में बोलने में थोड़ा कड़वा लगता है, सत्ता पक्ष के लोगों को सुनने में बड़ा खराब लगता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में जो स्कूल चल रहे थे । आपने 3000 स्कूलों को बंद कर दिया, सरगुजा और बस्तर के जो गरीब आदिवासी पढ़ते थे। उन 3000 स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया । आज ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जो शिक्षकविहीन हैं या एक-एक शिक्षक हैं, डेढ़ सौ-दो सौ बच्चे पढ़ते हैं, एक टीचर है तो क्या पढ़ाई होगी, सरकार इन बच्चों का भविष्य खराब कर रही है लेकिन शिक्षक भर्ती करने की इस सरकार की हिम्मत नहीं है । आश्चर्य होता है कि इन स्कूलों में जो शिक्षकविहीन हैं, वहां शिक्षक भर्ती करने के लिये किसने सरकार को रोका है, यह सरकार वहां पर शिक्षक भर्ती करके क्यों नहीं उन आदिवासी बच्चों को देना चाहती है और जब सरकार को समझ में आ गया कि बच्चे पास नहीं हो सकते तो बिना परीक्षा दिये पास होने का आपने नियम बना दिया, बिना परीक्षा दिये स्कूल जाओ और पास कर दो । छत्तीसगढ़ के इन गरीब बच्चों के साथ, वनवासियों के साथ यह सरकार खिलवाड़ करना बंद करे । सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिये, अस्पतालों में लोग तड़प रहे हैं, वहां डॉक्टर नहीं हैं । 15 साल हो गये हैं, आपने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिये, इतने हजार करोड़ का आपने बजट पास कर दिया लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं दे पा रहे हैं । क्या मजबूरी है, 22 अरब का आप मोबाईल बांट सकते हैं तो क्या हम ईलाज के लिये डॉक्टर भी नहीं दे सकते । आप निजी अस्पतालों को करोड़ों रूपये पेमेंट कर रहे हैं, प्राईवेट अस्पतालों में आप सरकारी पैसा पेमेंट कर रहे हैं उनके ईलाज के लिये लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की तन्ख्वाह बढ़ाकर आप डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर सकते, यह बहुत बड़ी गंभीर बात है । ....जारी ....श्री यादव

यादव\12-09-2018\e14\03.15-03.20

...........(जारी श्री बृहस्पत सिंह) :- लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाकर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते ? यह बहुत बड़ी गंभीर बात है । आप थोड़ी सी हिम्मत जुटा लीजिए, सरकार से हमारी गुजारिश है आप बजट लाइए, हम स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आप इस तरह से किसानों के बोनस देने के लिए बजट का करिए, एक दिन नहीं तीन दिन करिए, अनुपूरक में हम सब दस्तखत करने को तैयार हैं, लेकिन एक साल नहीं, जब से बोला है, पांच साल का धान का समर्थन मूल्य और 300 रूपए धान का बोनस की कीमत दीजिए । सौर ऊर्जा में जो दलाली चल रही है, मोबाईल में जो दलाली चल रही है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए । सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने की जो छूट बनाई है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस पर रोक लगनी चाहिए । सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद । सभापति महोदय, सच बात थोड़ी कड़वी लगती है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा । धन्यवाद ।

श्री केशव चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, द्वितीय अनुपूरक अनुमान जो कि 2433 करोड़ रूपए से भी ज्यादा का है । विशेष सत्र के माध्यम से सरकार किसानों की चिंता की बात कर रही है । मैं तो यह कहूंगा कि आपको किसानों की इतनी चिंता है तो पहले ही चिंता कर लेना था । पांच साल पहले भी आपने किसानों को धोखा दिया । आपने किसानों से कहा कि हम धान को 2100 रूपए क्विंटल में लेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे और 300 रूपए बोनस देंगे । आप किसान के शुभचिंतक हैं तो आपने 2100 में धान खरीदा या अपने पांच साल तक 300 रूपए प्रति क्विंटल बोनस दिया ? या फिर आपने किसान के द्वारा उत्पादित किए गए धान को खरीदा ? सभापति महोदय, यह किसान की चिंता नहीं कर रहे हैं, यह अपनी चिंता कर रहे हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बचे । हमने पिछले समय किसान को धोखा देकर इस कुर्सी को प्राप्त किया है, एक बार पुन: किसान को ठगने का काम किया जा रहा है । मैं दावा करता हूं कि यह सरकार की शुभचिंतक है तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस सदन में घोषणा करें कि पिछले चुनाव में जो 2100 रूपए क्विंटल की जो घोषणा की थी, उस 2100 रूपए में हम आपका धान खरीदेंगे । विगत् दो साल का 300 रूपए प्रति क्विंटल का, उस 300 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस देंगे । यदि यह सरकार किसान की शुभचिंतक है तो आज घोषणा करे कि किसान कितना भी धान उत्पादन करेगा, धान के एक एक दाने को समर्थन मूल्य के माध्यम से हम खरीदेंगे । माननीय सभापति महोदय, कोई विधायक इस बात का विरोध नहीं कर रहा है कि आप किसान को बोनस क्यों दे रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक चिंता और पीड़ा है कि किसानों को ठगने का काम क्यों हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, स्वामीनाथन कमेटी की बात होती है, उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है ? किसान की आय दोगुना करने की बात हो रही है । किसान की आमदनी दोगुनी हो रही है या नहीं हो रही है, यह अलग बात है, लेकिन लागत कई गुना जरूर हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जब आपने इस विषय पर बोलने की शुरूआत किए तो आपने कहा कि सरकार ने महंगाई कम कर दी । आपने उदाहरण दिया कि जो दाल 200 रूपए किलो दाल बिकती थी, आज 65 रूप्ए किलो हो गई । 45 रूपए में जो शक्कर बिकती थी, वह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

35 रूपए किलो हो गई । वाह सरकार । आपने किसकी कीमत को कम किया ? जो किसान पैदा करता है, उसको आपने कम किया । यदि आपमें साहस, हिम्मत है तो उन चीजों के दामों को कम करो जो उद्योगपति और व्यापारी लोग पैदा करते हैं । अरहर कौन पैदा करता है, दाल किससे बनती है ? उड़द कौन पैदा करता है, गन्ना कौन पैदा करता है ? यह किसान ही अपने खून को पसीना बनाकर इन चीजों को पैदा करते हैं । आप उनके उत्पाद के दाम घटा रहे हैं । नुकसान किसान को होगा । जो चीज उद्योगपति पैदा कर रहे हैं, उसकी कीमत आसमान को छू रही है । आप लौहे, सीमेंट, कपड़े की कीमत को कम करो, तब किसान को लाभ मिलेगा। आप किसान की कीमत को कम करेंगे तो किसान की आय कहां से दोगुनी होगी?

समय :

3:19 बजे **<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>**

<u>श्रीमती कमला पाटले, लोक सभा सांसद</u>

सभापति महोदय :- श्रीमती कमला पाटले, संसद सदस्य जांजगीर लोक सभा क्षेत्र आज अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं । मैं सदन की ओर से एवं अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\e15\3.20-3.25

समय:

3.20 बजे

<u>वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन (क्रमश :)</u>

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, पिछले समय भी किसानों को बोनस दिया गया। किसान बीज उत्पादित करके बीज निगम को देते हैं लेकिन जो किसान बीज निगम को धान पैदा करके दिये आज ऐसे पांच हजार किसान बोनस के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार की सहानुभूति किसानों के प्रति कहां है? उन किसानों को बोनस की राशि क्यों नहीं मिल रही है? एक साल समाप्त होने जा रहा है, आप नया बोनस देने की बात कर रहे हैं लेकिन पिछला धान जो आपने खरीदा उसका बोनस आज तक किसान को क्यों नहीं मिला? मंडी बोर्ड

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बीज निगम के माध्यम से खरीदे गये धान पर 200 रूपये प्रोत्साहन राशि देती है वह 200 रूपये की प्रोत्साहन राशि आज भी किसानों को नहीं मिला है और ऐसे पांच हजार किसान जिनको 25 करोड़ और 20 करोड़ इस प्रकार कुल 45 करोड़ रूपये आज भी नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, सरकार बोलती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, आज धरातल से लेकर जहां तक जाएं अगर कोई शोषित है, कोई पीड़ित है और कोई अन्याय, अत्याचार का शिकार हो रहा है तो वह किसान है। उनको अपने नक्शे, खसरे को लेने के लिए भी पटवारी को पैसा देना पड़ रहा है। अपने बच्चे के जाति, आमदनी, निवास पत्र के लिए भी उनको पैसा देना पड़ रहा है। आज सरकार कहती है कि उनको सुलभ करने के लिए हम उनके नक्शे, खसरे और तमाम रिकार्ड को ऑनलाईन दर्ज कर दिये हैं। कहां-कहां ऑनलाईन हुआ है? एक खसरा अगर छूटा है तो उस खसरे को भी दर्ज करवाने के लिए किसान आज मंत्रालय तक चक्कर काट रहा है तब भी उसका खसरा ऑनलाईन रिकार्ड में दर्ज नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी बात कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? उससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो किसान प्रभावित होता है और ये सरकार किसान के हित की बड़ी बड़ी बात कर रही है कि हम जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को लोन दे रहे हैं, हम शाकंभरी योजना के माध्यम से किसानों को ये ये लाभ दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये प्रदेश किसका है? ये प्रदेश किसानों का है। अगर किसान ये ठान लें कि ये सरकार अगर इस प्रकार की बात कर रही है, आप किसके पैसे को दे रहे हैं? ये उन्हीं का तो पैसा है। ये जो राशि आप दे रहे हैं ये उन्हीं किसानों की ही तो राशि है। कोई सरकार के पास आसमान से पैसा नहीं आया, किसान से ही आपने टैक्स के माध्यम से लिया, इस प्रदेश के खनिज से आपने उस पैसे को इकट्ठा किया। ये किसान का ही तो पैसा है और अगर उसको आप किसान को दे रहे हैं तो उसमें ऐहसान की क्या बात है? कांग्रेस के साथियों ने कहा कि आप नहीं कर रहे हो। हमारे सम्माननीय सदस्य अमरजीत भैय्या नहीं हैं। बोल रहे थे कि मोबाईल तो बांटना चाहिए लेकिन अच्छी क्वालिटी का बांटना चाहिए। आप 53 साल सरकार में रहे, इस बात को नहीं समझे और 15 साल की सरकार ने इस बात को समझा कि मोबाईल भी बांट लो और मोबाईल के माध्यम से लोगों की सहानुभूति भी ले लो और बीच की जो राशि है उसके माध्यम से चुनाव का खर्च भी निकाल लो। यह है किसानों के प्रति सहानुभूति। और शायद ये बात 53 साल के सरकार में कांग्रेस समझ

अशासकीय प्रकाशन के लिये नहीं

जाती तो हो सकता है कि 15 साल का मौका आपको नहीं मिलता। इस प्रदेश में सरकार किसी की भी बनी हो, इस देश में सरकार किसी की भी बनी हो केवल किसान से वोट के लिए सहानुभूति लगी है किसी ने किसानों की चिन्ता नहीं की है और न किसान के हित में काम किया है। योजना तो अनेकों बनी है। अगर सबसे ज्यादा योजना गिना दें तो किसान के हित में सबसे ज्यादा योजना बनी है लेकिन योजना का लाभ किसको मिल पा रहा है यह कभी धरातल पर जाकर हमारी प्रदेश की सरकार ने और बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी देखने का काम नहीं किया। आज सब्सिडी में हमको जो सामग्री मिल रही है, 75 प्रतिशत सब्सिडी लेकिन 25 प्रतिशत की जो राशि भुगतान कर रहे हैं अगर खुले बाजार में जाएं तो उस 25 प्रतिशत राशि में भी उससे बेहतर सामान हमको आज बाजार में मिल रहा है। ये 75 प्रतिशत राशि कहां जा रही है? किस किसान को इसका लाभ मिल रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि आप केवल वोट की राजनीति मत करें। किसान के प्रति यदि आपकी सहानुभूति है तो आप जो पांच साल पहले घोषणा किए थे, पांच साल पहले आश्वासन देकर जो आज इस सत्ता पर बैठे हैं, पांच साल पहले जिस विश्वास के बदौलत आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाये हैं उन आश्वासनों को पहले पूरा करने का काम करें।

समय:

3.25 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवजीभाई पटेल) पीठासीन हुए।)**

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\e16\03.25-03.30

जारी.........श्री केशव चन्द्रा :- पांच साल पहले आश्वासन देकर आप सत्ता पर बैठे हैं । पांच साल पहले के विश्वास की बदौलत आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है । पहले आप उन आश्वासनों को पूर्ण करने का काम करें । आप 2100 रूपए क्विंटल धान की कीमत दें । 300 बोनस भी दें और आपने पिछले 3 साल का बोनस नहीं दिया है, वह भी किसानों को दें और खुले मंच पर जाकर आप उस अन्नदाता किसान से माफी भी मांगें कि हमने आपको झूठा आश्वासन भी दिया है, झूठी घोषणा की थी, अब पुन: मौका आ गया है तो आपने जो आश्वासन दिये थे, आपने जो घोषणाएं की थीं उनको पूरा करने का काम करें । माननीय सभापति महोदय, यहां पर अनेक चर्चाएं हुईं । केवल अनुदान मांगों पर ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की चर्चा,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं तो यह कहूंगा कि पूरा प्रदेश ही आंदोलनरत् है । ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आपकी सरकार से संतुष्ट हो । सभी असंतुष्ट हैं, सभी के साथ शोषण हो रहा है । सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहूंगा कि आपने स्वयं के संकल्प पत्र में जिन बातों को पांच साल पहले कहा है, फिर एक संकल्प पत्र बनाने का समय आ गया है । इसलिए उन्हें पूरा करने का काम करें । धन्यवाद् ।

श्री दीपक बैज (चित्रकोट) :- माननीय सभापति महोदय, आज सरकार द्वारा 2433 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट लाया गया है । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि दो-चार दिनों से मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि अनुपूरक बजट में 24 सौ करोड़ किसानों के लिए होगा । लेकिन आज जब सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो पता चला कि सिर्फ 1200 करोड़ रूपया ही किसानों के लिए है । यह बहुत कम है । मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार बोनस का वायदा चुनाव के पूर्व करती है, केवल एक साल बोनस देने का वायदा करती है या पूरे पांच साल बोनस देने का वायदा करती है । चुनाव में केवल एक साल समर्थन मूल्य देने का वायदा करती है या पूरे पांच साल समर्थन मूल्य देने का वायदा करती है । इस साल अगर सरकार को घोषणा पत्र तैयार करना है तो स्पष्ट लिखे कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पूरे पांच साल समर्थन मूल्य और पूरे पांच साल बोनस देंगे या अगर हमारी सरकार आएगी तो एक साल समर्थन मूल्य देंगे और एक साल बोनस देंगे । सरकार इस बार घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखे क्योंकि तीन बार इस सरकार को झूठा वायदा करते हो गया ।

श्री केशव चन्द्रा :- दीपक जी, उन्होंने तो पिछली बार भी लिखा था, लिखने से थोड़े ही कुछ होता है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- ये बताओ, अगर हम लिख देंगे तो क्या हमें वोट दोगे?

श्री दीपक बैज :- नहीं मिलेगा । आप गलतफहमी में है मंत्री महोदय, अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के नाम से तीन बार जनता को (xx)[11] बनाया है । चौथी बार छत्तीसगढ़ की जनता और किसान (xx) बनने वाले नहीं हैं । इसलिए हम इस सदन में कहते हैं कि आप 2100 रूपए समर्थन मूल्य दे दें, आप 300 रूपए बोनस दे दें । 2400 रूपए पांचों साल का दे दें

[11] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो हम बिना चर्चा के इसे पास कराने को तैयार हैं । लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ चुनाव के समय केवल एक साल समर्थन मूल्य और बोनस याद आता है ।

श्री नवीन मारकंडेय :- माननीय सभापति महोदय, किसान (xx) नहीं बनने वाले हैं, इन्होंने ऐसा कहा है इसलिए इसको विलोपित करा दें ।

सभापति महोदय :- (विलोपित किए जाने का इशारा)

श्री दीपक बैज :- छत्तीसगढ़ की जनता को आप (xx) बना रहे हैं । घोषणा पत्र और संकल्प पत्र बना बनाकर आप अपना कितना उल्लू सीधा करेंगे । सभापति महोदय, इस सरकार के कार्यकाल में किसानों ने लगातार आत्महत्या की है । आप सोसायटियों में देखिए आपने कितने किसानों को डिफाल्टर कर दिया । आज वे अपना कर्जा भी नहीं पटा पा रहे हैं । आज जीरो परसेंट ब्याज की बात करते हैं खाद और बीज का रेट कितना बढ़ गया ? ये किसानों की चिंता करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं । सभापति महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज जब किसान आत्महत्या करता है तो आप उस किसान को ही गलत ठहराते हैं..........

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\12-09-2018\e17\3.30-35

जारी...श्री दीपक बैज :- किसान को गलत ठहराती है । इस प्रदेश में नोटबंदी के बाद क्या हालत है, नोटबंदी और जीएसटी से सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं । जब केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काला धन के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से नोटबंदी किया तो प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने टमाटर को, सब्जियों को सड़कों पर फेंका है । नोटबंदी और जीएसटी के नाम से आपने छोटे-छोटे किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी है । आज उसी का नतीजा है । जीएसटी की मार सबसे ज्यादा उन छोटे किसानों पर पड़ी है, जहां छोटे-छोटे किसान धान और सब्जी पैदा करते हैं, उनको ज्यादा नुकसान हुआ है । आप ट्रेक्टर का रेट देखिए, दवाई पर जीएसटी लग रहा है, ये सरकार किसानों की चिन्ता नहीं कर रही है । सरकार दावा करती है कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे । वाह रे सरकार, आपने तो पांच साल पूरा नहीं किया और असत्य कहने के लिए पूरा षडयंत्र रच लिया कि हमको 2022 में आने दो, हम आपकी आय दोगुनी करेंगे । आप किसानों की आय कैसे

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दोगुनी करोगे, मैं कहना चाहता हूं । पिछले समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी को शो हो रहा था तो हमारे बस्तर एरिया के कांकेर की एक बहन से पूछा, दिल्ली से टीम आई थी, एक-दो दिन पहले उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई, आज प्रधानमंत्री जी आपको पूछेंगे, आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, आप कहना कि हां, दोगुनी हो गयी, यह ट्रेनिंग दी गई । जब उसको पूरे देश ने देखा और जब टी.व्ही. के एक चैनल ने उनसे जाकर पूछा कि आपकी आय दोगुनी कैसे हुई तो उसको भी पूरे देश ने देखा । उस महिला ने कहा कि मुझे असत्य कहने के लिए ट्रेनिंग दी गई, हमारी कोई आय दोगुनी नहीं हुई है । जब इस असत्य का पर्दाफाश पूरे देश ने देख लिया तो इस सरकार ने उस टी.व्ही. चैनल को धमकाना चालू किया, ये कैसी दोगुनी आय की आप बात करते हैं । इस सरकार में महंगाई तो इतनी बढ़ गई है-बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार । मैं निवेदन करता हूं कि अब कि बार वैसे ही बोलकर, लंबा-लंबा पोस्टर छपवाकर गांव में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि 56 इंच का सीना कितना है, आप जाकर देखिए । पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के रेट से सबसे ज्यादा किसान तकलीफ में है । आज देखिए कि गाय और बैल बहुत के किसानों के घर में कम है, लगभग हर किसान के घर में ट्रेक्टर है, आज ट्रेक्टर डीजल के माध्यम से चलता है, डीजल का रेट बढ़ता है तो किसान का कहीं न कहीं लागत मूल्य में नुकसान हो रहा है । ये सरकार पेट्रोल और डीजल का रेट कम करने में नाकाम हो गई है, इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही है ? राज्य सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, इसको जीएसटी के दायरे में लाए, पेट्रोल 40 रूपए लीटर से नीचे मिलना चालू हो जाएगा । सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम हुई है । आप ढाई हजार करोड़ का मोबाईल बांट रहे हैं, कभी 25 लाख बेरोजगारों को आपने झांककर देखा है, कभी कोई किसान, कोई बेरोजगार ने आपको आवेदन दिया कि हमको मोबाईल चाहिए, आप किसलिए मोबाईल बांट रहे हैं, ताकि चुनाव के लिए फंड की व्यवस्था कर सकें, घोटाला कर सकें, इसलिए आप मोबाईल बांट रहे हैं । आज बी.एड. और डी.एड. किए हुए 1 लाख, 80 हजार लोग हड़ताल कर रहे हैं, 25 लाख बेरोजगार हैं, उनको देने के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन आप ढाई हजार करोड़ का मोबाईल बांट रहे हैं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा लिए, ताकि आप जाकर वोट मांग सके । आपकी ये चाल भी कामयाब नहीं होने वाली है । आप गलत फहमी में मत रहिए । किसानों की बहुत बात करते हैं । मैं अपने क्षेत्र लोहण्डीगुडा की बात मैं कर लूं, उद्योगों के नाम से टाटा स्टील प्लांट में आप लोगों ने 17 सौ

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों की जमीन ली है, 2016 में आपका एम0ओ0यू0 खतम हुआ है, टाटा स्टील प्लांट वापस हो गया, अगर आप किसानों के बड़े शुभ चिन्तक हैं तो आज 17 सौ किसानों की जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं । आज किसानों को खाद, बीज कुछ नहीं मिल पा रहा है, न बैंक में लोन ले पा रहे हैं । किसानों की बड़े-बड़े हित की बात करने वाली उद्योगों के नाम से आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं । अगर आप में हिम्मत है तो उन किसानों की जमीन वापस करिए, जो टाटा स्टील प्लांट, लौहण्डीगुड़ा में गया है...

श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\e18\03.45-03.50

जारी... श्री दीपक बैज :- उद्योगों के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है तो उन किसानों की जमीन वापस करिये, जो टाटा स्टील प्लांट लोहण्डीगुड़ा में गयी है ताकि किसानों को लगे कि यह सरकार किसानों के हित में है। माननीय सभापति महोदय, अभी बस्तर में इस सरकार के खिलाफ लगभग हजारों किसान पैदल यात्रा कर रहे हैं। वहां के किसानों के साथ क्या हुआ है? वहां के किसानों के साथ ट्रेक्टर एजेंसी, फायनेंस कंपनी, बैंक और दलाल मिलकर किसान क्रेडिट के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। इस सरकार से उन्होंने कई बार मांग की, धरना, प्रदर्शन किया, कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार बस्तर से कूच कर चुकी है। आपकी सरकार को हिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाह रहे है अंतिम वक्त पर पूंछ पकड़कर नैया पार कर लें। पूंछ पकड़ना है तो बैल की पूंछ पकड़ों, बैल का पूंछ पकड़ोंगे तो नैया पार कर लोगे। आपने तो भैंस की पूंछ पकड़ ली है। भैंस नैया पार नहीं करायेगी, भैंस वहीं पानी में डूब जाती है। वही स्थिति आपकी है। इसलिए इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई योजना नहीं है। आपके पास सिर्फ दो योजना चल रही है। एक जियो और दूसरा पियो। यही योजना चल रही है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों की ज्यादा चिंता कर रहे हैं, दो महीने में आपको पता चल जायेगा । आप पूरे प्रदेश में सर्वे करा लिये, आरएसएस से सर्वे करवा लिये, पार्टी स्तर पर सर्वे करा लिये, आप 30 सीट के अंदर सिमट रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आप पूंछ पकड़ कर नैया पार करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप किसानों को धोखा देना बंद करें । आपका यह छलावा अब नहीं चलने वाला है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बालने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. विमल चोपड़ा (महासुंद) :- माननीय सभापति महोदय, अनुपूरक बजट पर लगभग 24 सौ कराड़ रुपये की सरकार ने मांग की है और इस पैसे से किसानों को बोनस दिया जाना है। जो बाद में दिया जाता, वह पहले दिया जायेगा। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने किसानों के हित में यह निर्णय लिया। कारण जो भी हो, लेकिन राशि किसानों तक पहुंचने की है और यह 24 सौ रुपये सरकार को देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं 24 सौ करोड़ क्यों, आप 72 सौ करोड़ रुपये लीजिए और जो 2 साल का बचा हुआ बोनस है, वह भी किसानों को मिल जाए तो किसानों के हित में यह ज्यादा अच्छी बात होगी। माननीय सभापति महोदय, सरकार के पास जितना है, अभी जो भी बचा है, वह सब किसानों को दे दिया जाए, देश के अन्नदाता को दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार 24 सौ करोड़ मांग रही है, हम 72 सौ करोड़ देने को तैयार हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि गरियाबंद से कमार लोग पदयात्रा कर के मुख्यमंत्री जी के निवास तक आ गये। सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि कमार प्रोजेक्ट की जो राशि है, वह सरकार ने दे दी है, लेकिन उस राशि को अफसर खर्चा नहीं कर रहे हैं। पैसा आपके पास है, खर्च नहीं हो पा रहा है। अफसरशाही पर नियंत्रण क्यों नहीं है? हमारे महासमुंद में भी मैं चिल्ला-चिल्ला कर, कलेक्टर को बोल-बोलकर थक गया कि कमार प्रोजेक्ट और माडा प्रोजेक्ट का पैसा वहां पड़ा है। एक साल का नहीं, चार-चार, पांच-पांच साल का पैसा पड़ा है और वह कमार वैसी ही जिंदगी बसर कर रहे हैं, जैसे वे पहले करते थे। उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग के लिए, उनके मकान के लिए सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन अफसर उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी कई योजनाओं का पैसा सरकार ने दिया है, लेकिन वह खर्च नहीं हो पा रहा है। इस अफसरशाही पर सरकार जब तक लगाम नहीं लगायेगी, सरकार चाहे जितनी योजनाएं बना ले, सरकार पैसा भेज दे, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, वनाधिकार के पट्टे मिलने चाहिए। हम खेती की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। कमारों को वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला है। 6 महीने से मैं सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा हूं। सिरपुर के कमार, बंशिवनी के कमार और दूसरे स्थानों के जो कमार हैं, वे महीनों से आवेदन लगाए हैंय, सालों से उनका कब्जा है.......

जारी श्रीमती सविता

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सविता\12-09-2018\e19\03.40-03.45

.....जारी डॉ. विमल चोपड़ा :- और दूसरे स्थानों के जो कमार हैं, वे महीनों से आवेदन लगाएं हैं, सालों से उनका कब्जा है, वे पात्र हैं, लेकिन उनको पट्टा नहीं दिया जा रहा है। मनीराम गोड़, जिसके नाम पर सरकार ने हरियाली पुरस्कार की घोषणा की है, वह कई सालों से वनवासी जंगल की जमीन पर काबिज है, लेकिन सरकार ने उसको पट्टा नहीं दिया। जिसके नाम से सागौन का प्लांटेशन होता है वह मनीराम गोड़, जिसके नाम से सरकार ने पुरस्कार घोषित किया है वह जंगल की जमीन पर वर्ष 2000 से पहले से काबिज है, लेकिन आज तक उसको पट्टा नहीं दिया है ये सरकार की कैसी नीति है?

माननीय सभापति महोदय, निराश्रित पेंशन के लिए सरकार के संकल्प पत्र में ये घोषणा है कि हम 250 का 500 रूपये करेंगे और 300 रूपये का 600 रूपये करेंगे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 50 रूपये वृद्धि की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वह निराश्रित जो प्रदेश में 17 लाख की संख्या में है, उनको आप 250, 300 और 350 रूपये निराश्रित पेंशन दे रहे हैं इस महंगाई के जमाने में 300 और 350 रूपये में क्या होने वाला है? आज तक सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सरकार उनके जीवन की तरफ झांकें, उनकी स्थिति को देखे और सरकार को कम से कम उस निराश्रित पेंशन को 1 हजार रूपये करना चाहिए। हम लोगों ने कई बार मांग की है कि उनको पेंशन की राशि घर पहुँचा कर दी जानी चाहिए। आज 40-40 किलोमीटर वे पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उनको बैंक वाले पेंशन नहीं देते हैं बैंक के अधिकारी उनकी उपेक्षा करते हैं,उनको भगा देते हैं वे आंसू बहाते हुए बैंक से बाहर निकलते हैं, क्यों न सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उनको घर में जाकर 300 और 350 रूपये निराश्रित पेंशन की राशि दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने डी.एम.एफ. का फण्ड बनाया, ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर अच्छे काम होंगे, लेकिन ये कलेक्टर की पॉकेज मनी बन गई है। हमारे महासमुंद जिले में हम लोग जिस खेल को जानते नहीं है, कलेक्टर अपने खेलने के लिए वैसे मैदान बना रहे हैं ये स्क्वेस क्या गेम होता है, हम लोग जानते नहीं है, लेकिन कलेक्टर अपने लिए बना रहे हैं। बिलियर्ड बन रहे हैं, बिलियर्ड के हॉल बन रहे हैं कलेक्टर अपने खेलने के लिए बना रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ये कलेक्टरों का पैसा है कि ये जनता का पैसा है ये तय होना चाहिए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए कि इसका दुरूपयोग न हो।

मानननीय सभापति महोदय, आज 108 के जो चालक हैं, वे हड़ताल कर रहे थे उनकी हड़ताल खत्म हुई, सरकार के साथ उनकी वार्ता हुई, लेकिन उसके बाद जब उसको कंपनी ले रही है तो उनसे लिखित ये वायदा करा रही है कि वे कभी हड़ताल नहीं करेंगे, कभी अपनी मांगों के लिए आवाज नहीं उठायेंगे, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए और इस प्रकार से जो आज हो रहा है उस पर कम से कम सरकार का ध्यान जाना चाहिए। पैसा देने में कोई आपत्ति नहीं है, आप पैसा जितना लीजिए, लेकिन उसका सदुपयोग हो, काम अच्छा हो, किसानों, मजदूरों, गांव के लोगों के हित में हो।

मानननीय सभापति महोदय, आज हम लोग जो देखते हैं कि गांव में पैसा नहीं पहुंच रहा है, सरकार का सारा पैसा बड़े-बड़े नगर निगम, नगर पालिकाओं में जा रहा है गॉवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं सड़क, बिजली, पानी नहीं है। आज यदि हम हिसाब लगाएंगे तो शहरी आबादी को 200 रूपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मूलभूत सुविधाओं के लिए मिलता है तो गॉव में 5 रूपये प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से मिलता है ये अंतर क्यों है ? गॉव वाला भी एक वोट देता है, शहर वाला भी एक वोट देता है शहरों में सारा पैसा जा रहा है, गॉवों में नहीं जा रहा है, गांव के लोग आज अभाव में जिन्दगी जी रहे हैं इसलिए वे शहर की तरफ भाग रहे हैं। गांव और शहर में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी ये जो विधान सभा है इसमें 70 लोग जो जीतकर आये हैं, वे गांव के वोट से जीतकर आये हैं, 20 लोग शहर के वोट से जीतकर आये हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत सुविधाओं की जो राशि है, शहरों में 70 प्रतिशत राशि खर्च होती है और गॉवों में सिर्फ 30 प्रतिशत राशि जाती है ये हमारा बजट जो उल्टा चल रहा है इसको सीधा करने की जरूरत है, गॉवों में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, वहां लोग रह सकें, वैसी सुविधा देने की जरूरत है इसलिए गांवों और शहरों के विकास में पैसे का समान विभाजन होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चौधरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौधरी\12-09-2018\f10\03.45-03.50

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, पावस सत्र में जो अंतिम सत्र के रूप में कहा गया था, अधिकारियों को, पत्रकारों को, सचिवालय को सबको धन्यवाद दे दिया गया था, सबने धन्यवाद दिया था। सभापति महोदय, फोटो भी खिंचवा लिये थे और जिनके साथ फोटो खिचवायें तो स्वर्ग सिधार गये, कल हमने श्रद्धांजलि भी दी। ये नई परंपरा की शुरूआत हुई है। जब सत्रावसान हो जाये और चुनाव के लिए जाना है, उस समय आपने ही सप्लीमेन्ट्री बजट में सब कुछ डाल दिया था। आपको मोबाईल बांटना है, धान के लिए भी, सब कुछ कर दिया था। लेकिन ये पहला सत्र ऐसा है जिसमें न प्रश्नकाल है, न ध्यानाकर्षण है। इस प्रकार के सत्र विशेष परिस्थिति में जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाये, कोई राजनीतिक स्थिति खड़ी हो जाये, उस परिस्थिति में इस प्रकार की बैठकों का आयोजन होता है, लेकिन ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। एक कहावत है- '' लगा कलेजा फटने तो लगी पंजीरी बंटने''।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- और भी तो कुछ है।

श्री भूपेश बघेल :- महाराज, वह आप बोल देंगे। सभापति महोदय, अब ये युक्ति बदल गई। ''लगा कलेजा फटने तो लगी पंजीरी बंटने'' अब ये बदल गया है। ''लगा मोबाईल फटने तो लगा बोनस बटने''। मास्टर स्ट्रोक समझे थे, घर-घर में मोबाईल, 55 लाख मोबाईल, सबके हाथ में मोबाईल, टेलीविजन, समाचार पत्रों में खूब विज्ञापन, संचार क्रान्ति हो जायेगी। लेकिन कमीशनखोरी इतनी हावी थी, अमेजान में हम लोगों ने देखा कि माइक्रोमैक्स का 3100 में सिंगल मोबाईल मिलता है। सरकार ने 55 लाख मोबाईल खरीदा तो सस्ता होना था, 2000 रुपये में मिलता, वह 4100 रुपये हो गया और सभापति महोदय, हिसाब करें तो 5 सौ से हजार करोड़ का वारा-न्यारा हो गया। लेकिन ये तो बकरे की जान भी गई और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। सभापति महोदय, स्थिति यह है कि मोबाईल लिये तो आदमी चार्ज करने में डरता है और चार्ज कर लिये तो बात करने में डरता है। मोबाईल गर्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर वह पैसा भी पटाना पड़ता है, 6 महीना का बोले थे, वह 15 दिन, एक महीने नहीं चलता। अब तो मोबाईल फटने भी लगा है।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अच्छा यह बताओ कि गर्म होने के बाद डिस्चार्ज नहीं होगा तो कब होगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- मोबाईल दिन भर में 24 घंटे चलता है, यदि सुबह चार्ज करें तो देर रात तक चलता ही है, लेकिन ये ऐसा मोबाईल है कि 3 घंटे में ही डिस्चार्ज हो रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ''कलेजा लगा फटने तो खैरात लगा बटने।''

श्री भूपेश बघेल :- वह बूमरेंग हो गया, यह मोबाईल, संचार क्रांति बूमरेंग हो गया। उल्टापड़ गया। मास्टर स्ट्रोक, ब्रम्हास्त्र, पता नहीं भाजपा वाले क्या-क्या बोलते हैं। बूमरेंग हो गया, अब उस मोबाईल को कोई रखना नहीं चाहता। एक व्यक्ति का पूरा गाल जल गया। एक चार्जिंग करते हुए फट गया। सभापति महोदय, लैलूंगा में मोबाईल चार्ज कर रहा था, उसको करेन्ट लगा गया, आदमी मर गया। इसके लिए दोषी कौन है ?... (जारी)..

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\f11\03.50-03.55

.......जारी श्री भूपेश बघेल उसके लिए दोषी कौन है ? प्रतापपुर में में घर जल गया। मेरे क्षेत्र से एक लड़का आया था, वह बोला कि मेरी मां को मोबाइल मिला था, मैंने कहा कि दिखा मोबाइल, मैं भी देखूं, वह बोला कि मैं लाया नहीं, क्यों ? बोला कि डर लगता है। पड़ोसी मांग रहा है, मैं उसे दे दूंगा, मैं नहीं रखने वाला हूँ। यह स्थिति मोबाईल की है। 22 सौ करोड़ रूपये बर्बाद कर दिए। आपने 55 लाख मोबाईल बांटने का निर्णय लिया। रायपुर राजधानी में बैठे हैं। 3 लाख परिवार हैं। सारे अधिकारी बैठे हैं, सिर्फ 39 हजार मोबाईल बंट पाया है। यदि आज रायपुर में 3 लाख परिवार में 39 हजार मोबाईल बांट रहे हैं, तो प्रदेश की स्थिति क्या है ? मोबाईल कहां जायेगा ? उसका पैसा कहां है? आप तो भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। कमीशनखोरी में लगे हैं। उसकी टेण्डर की प्रक्रिया का पता नहीं है। उसमें कौन-कौन भाग लिया है, इसका पता नहीं है। कितने लोगों ने टेण्डर भरा उसका पता नहीं है और आप ऐसे मोबाईल ले आये, 12 सौ रूपये का मोबाईल गरम नहीं होता है। दिनभर बैटरी चलती है।

श्री अमरजीत भगत :- इससे तो अच्छा रहता है कि सबको नकदी बांट दिए रहते।

श्री भूपेश बघेल :- कमीशन कैसे मिलता ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- नकदी बांट देते तो लोग अपनी पसंद से ले लेते।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो सत्र बुलाया गया है, यह किसानों के हित के लिए नहीं है, यह तो रमन सरकार ने भय के कारण बुलाया है। सभापति महोदय, आज तीजा है। महिलाएं व्रत रखती हैं। सबके घर में बहन बेटियां आती हैं।

समय
3.52 बजे **(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.)**

लेकिन सरकार तीज-त्यौहार, हिन्दू धर्म के ठेकेदार हैं। लेकिन इनको छत्तीसगढ़ के तीज-त्यौहार की जानकारी नहीं है। सरकार में बैठे हुए अधिकारी लोगों को यह पता नहीं है कि यहां तीजा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है।

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक सभा सांसद

अध्यक्ष महोदय :- आज अध्यक्षीय दीर्घा में लोकसभा सांसद आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- कुछ वर्ष पहले यहां के सदस्य हुआ करते थे, आज सबसे बड़े पंचायत के सदस्य हैं और हमारे सी0डब्ल्यू0सी0 के मेम्बर बने हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तिथि भी कौन सा चुना ? तीजा का। सबके घर में बहु-बेटियां आती हैं। यह छत्तीसगढ़ की परम्परा है। इनके यहां शायद वह परम्परा न हो।

श्री चुन्नीलाल साहू :- तीजा के पहले दिन व्रत रखे थे। महिलाओं के साथ बहुत परेशानी हुई।

श्री अमरजीत भगत :- (xx)[12]

अध्यक्ष महोदय :- हटा दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो वादा किया उसके लिए भी उसके लिए भी यदि इसको बजट में शामिल कर लेते, तब भी हम सहमति देते। आप 21सौ रूपया

---

[12] (xx) अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी। यदि 5 साल के हिसाब से उतना प्रावधान किया होता तो तब हम आपका समर्थन करते।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 2100 रूपया तो हो गया। आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री भूपेश बघेल :- 2100 और 300 कुल 2400 रूपया होता है और यही बोलकर वोट मांगे हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 21 सौ हो गया। 1770 और 300, दो हजार सत्तर रूपये हो गया। उसी का तो आपके पेट में दर्द है कि 21 सौ कर दिया हमारा क्या होगा।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग 21सौ, 24 सौ रूपये में, इतने में ही अटके हैं। आप लोग 03 हजार रूपये कर दीजिये। हम लोगों कोखुशी होगी, हम लोग समर्थन करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- पेट में दर्द होगा, उसका जो खाना खाये। आप तो टिफिन बांट रहे हो, भात भी छिन लिए, 35 किलो की जगह 7 किलो कर दिए। आप खाली टिफिन दे रहे हैं। आप कुकर दे रहे है, लेकिन चावल 7 किलो हो गया है। दाल का पता नहीं है, चना का पता नहीं है, आप प्रेशर कुकर दे रहे हैं। गैस सिलेण्डर का कोई रिफिल नहीं करा रहा है। सारी योजना फेल हो गई। ....जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\f12\03.55-03.60

जारी...श्री भूपेश बघेल .... कोई रिफिलिंग नहीं करा रहा है, सारी योजनायें फेल हो गयी, लगा कलेजा फटने, खैरात लगी है बंटने । यह विशेष सत्र बुलाया ही इसलिए गया है, देख लिया कि इस मोबाईल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है । उल्टा पड़ रहा है, बुमरेंग हो गया है, इस कारण से सत्र बुलाये हैं । आप बोनस देने वाले नहीं थे, वह तो हम लोग आंदोलन किये तो दबाव में आकर आपने बोनस देना शुरू किया । आपके प्रधानमंत्री ने लिख दिया था कि जो प्रदेश बोनस देगा, उस प्रदेश में धान खरीदी नहीं होगी । आपने इसलिए 10 क्विंटल खरीदने का निर्णय लिया था, वह तो हम लोगों ने आंदोलन किया, वह भी 1 दिसम्बर, 1 दिसम्बर को धान खरीदी, हमने कहा 1 महीने धान नहीं खरीदे हैं, 1 दिसम्बर को भी आप धान मत बेचें, किसानों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से आव्हान किया, कोई किसान धान बेचने नहीं आया । शाम को आप एकात्म परिसर में, मंत्रालय में नहीं, एकात्म परिसर में घोषणा करते हैं कि हम 10 की जगह 15 क्विंटल धान खरीदेंगे । वह कांग्रेस के दबाव में आपने फैसला किया था । आपकी इच्छा तो किसानों को देने की नहीं थी। यदि देना होता तो दो साल के बोनस को और जोड़कर देते । आप कहते थे कि एक-एक दाना धान खरीदी, वह अंतर की राशि जोड़ते तो निश्चित रूप से हम समर्थन कर देते । लेकिन आपकी नीयत नहीं है । आप तो डर के मारे, किसान के पास जाना है, यही सदन है अध्यक्ष महोदय, जब 1500 किसानों ने आत्महत्या किया, हम कहते थे कि किसान कर्ज के मारे आत्महत्या किये । आपके सदस्य लोग बोलते थे कि शराब पीकर आत्महत्या कर रहा है । उसको शराबी बना दिये । आज अन्नदाता के पास जाना है, वोट मांगने जाना है, अब आप उसको याद आये । अब वे आपके बरगलाने में नहीं आने वाले हैं । आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं । कहां एक-एक दाना किसानों का धान खरीदी । 2100 रूपये समर्थन मूल्य, 300 रूपये बोनस, बिजली बिल माफ, कुछ नहीं । अब जनता ने ठान लिया है, आप निश्चिन्त रहें । यह किसानों के साथ धोखा तो हुआ ही है, आपने आदिवासियों को पहले छला, एक-एक जरसी गाय देंगे, आज तक नहीं मिल पाया । उसमें बजट रख देते । जब देना था । एक-एक को आपने नौकरी देंगे कहा था, उसको प्रावधानित कर देते । आप आदिवासियों के हित की बात करते हैं, आपने यह सप्लीमेंट्री प्रस्तुत किया है, उसमें कृषि मंत्री जी आपके विभाग से केवल 1200 करोड़ है । जो बचत 1200 करोड़ है, वह ट्रायबल सब प्लॉन का पैसा है, अनुसूचित जाति के विभाग का पैसा है । अनुसूचित जनजाति विभाग का पैसा है । जो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में काम होता है, उसको लाभ मिलता । वह सब पैसा इकटठा करके इसमें दे दें । आपकी जो मानसिकता है, वह आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जनजाति विरोधी है । यह आपने सप्लीमेंट्री बजट में रखा है । 2400 करोड़ का आप इसमें कृषि विभाग में नहीं रखा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय केदार कश्यप जी, आप आदिवासियों का पैसा है, उसको कहां उल-जुलूल चीज में खर्च कर रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- आदिवासी विभाग का पैसा है, उनके मद में खर्च करते, उनके हितों पर खर्च करते......

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अच्छा आप बताओं कि किसानों को बोनस मिलना चाहिये कि नहीं ?

श्री भूपेश बघेल :- बोनस मिलना चाहिये, पूरे 2100 रूपये समर्थन मूल्य के साथ ।

श्री अमरजीत भगत :- पूरे पांच साल का मिलना चाहिये ।

श्री भूपेश बघेल :- हम उसमें समर्थन करते हैं ।

श्री केदार कश्यप :- उसमें ट्रायबल ब्लॉक कितने हैं आपको मालूम है ? 85 ब्लॉक है । यह भी उसमें शामिल है ।

श्री अमरजीत भगत :- हम लोगों को याद नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- उसके स्कूल में दूसरे ढंग से पढ़ाते होंगे । पत्नी की जगह साली को परीक्षा दिलाते हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पत्नी की जगह साली परीक्षा दे दी तो कौन सा तूफान आ गया? क्या कर लिये ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अटल जी को हमने श्रद्धांजलि दी । पूरा देश उसके जाने से दुखी है और उसके प्रति सब के मन में सम्मान है । भारतीय जनता पार्टी के मन में कितना सम्मान है, पूरा देश ने देखा है ? कैसे ठहाका लगा रहे थे? कैसे कलश के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे? कैसे अटटहास लगा रहे थे........

जारी...श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\f13\04.00-04.5

जारी.........श्री भूपेश बघेल :- और उनके प्रति सबके मन में सम्मान है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में कितना सम्मान है उसको पूरे देश ने देखा है । कैसे ठहाका लगा रहे थे वह सबने देखा है, कैसे कलश के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे और कैसे अट्टहास लगा रहे थे उसको सबने देखा है । श्री अटल जी का चौक बने, उनकी मूर्ति लगे इसमें किसी का कोई विरोध नहीं लेकिन उसको भी आप सप्लीमेंट्री में डाल देते । आपने आदेश निकाल दिया, चौदहवें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वित्त आयोग के पैसे से पंचायत विभाग करेगा । एक तो टावर का पैसा लड़-झगड़कर हम लोगों ने वापिस कराया, नहीं तो 600 करोड़ रूपये तो जमा ही करा दिये थे, जिओ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिये, रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिये, 610 करोड़ वापिस कराये और फिर से पंचायत विभाग का आदेश कि आप ग्राम पंचायत के पैसे से सब करें तो दूसरे के पैसे से आप क्यों करेंगे भई आपको बहुत श्रद्धा है तो आप अपने विभाग से खर्च कर लेते, पंचायत विभाग में पैसे की कमी है । अभी इसको सप्लीमेंट्री बजट में जोड़ लेते, आपने क्यों नहीं किया तो यह आपकी सरकार की नीयत ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास यात्रा निकाल रहे हैं । खूब शासकीय धन का दुरूपयोग हो रहा है । हाईकोर्ट में एफिट-डेविट देते हैं कि हम किसी जो शासकीय व्यक्ति नहीं है उसकी हम फोटो नहीं छापेंगे । राष्ट्रीय अध्यक्ष की फ्रंट पेज में फोटो छपी है, अब तो बदल भी गया, अब तो अटल विकास यात्रा लेकिन अटल जी की फोटो ही नहीं है। मध्यप्रदेश में बंद हो गया है, राजस्थान में बंद हो गया है, छत्तीसगढ़ में शासन के धन का दुरूपयोग अपने प्रचार के लिये, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी हो गयी है जो शासकीय धन का दुरूपयोग करके प्रचार कर रही है । बिल्हा में आपने क्या किया । सारे रिकॉर्डिंग अपने पास है, आप अपने प्रत्याशी का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक-तरफ हाईकोर्ट में आप ऐफिट-डेविट देते हैं कि हम इस प्रकार से प्रचार नहीं करेंगे । क्या यही आपकी विकास यात्रा है । विकास यात्रा के माध्यम से आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इसलिये इसको बंद किया जाना चाहिए । पंचायत मंत्री जी, क्या आप पंचायत के बारे में कुछ बोलेंगे कि अभी सप्लीमेंट्री में जोड़ेंगे ।

पंचायत मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- क्या है आखिरी भाषण है जो बोल लो । रहना तो वहीं है, कहां जाना है । टांगा में चढ़ लो, घोड़ा में चढ़ लो, गधा में चढ़ लो, गाड़ी में चढ लो जो करना है कर लो । जिसमें चढ़ना है चढ़ लो, रहना वहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आप भी अंतिम इच्छा पूरी ही कर लो। इस बार अंतिम इच्छा पूरी कर लो ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपका वाहन तय है । उल्लू भी किसी का वाहन है, चूहा भी किसी का वाहन है तभी आपका घोड़ा चल रहा है और बैला चल रहा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा [XX][13] आपको डांटे क्यों यह आप बताईये । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- जब आते हैं तब डांट खाते हैं । जब आये, नया भवन बना है वहां डांट खाये । हम लोग तो घोड़ा चढ़ें, टू चढ़ें, कुछ भी चढ़ें लेकिन दूलत्ती खाने का शौक आपको है ।

अध्यक्ष महोदय :- [XX] का नाम हटा दें ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक बात है श्री बघेल जी, आप नेता प्रतिपक्ष जी से ज्यादा लोकप्रिय हैं यह बात साबित हो गयी । भले ही आप मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रहे हैं, जीतने तक लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष और सत्तू भैया से ज्यादा लोकप्रिय हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन आपके जैसे ठहाके मारने में पीछे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- सर्वे तो आते-जाते रहेंगे मंत्री जी और सर्वे पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए । वह रोज-रोज बदलते रहता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- सर्वे में तो सब टिकट बांट रहे हो, पूरा सर्वे बता रहा है कि आप लोग भाभी जी को टिकट नहीं दे रहे हैं करके । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- इन लोगों को बड़ी चिंता है उसके बिना कैसे लड़ेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- ये दूसरे के घर में तांक-झांक करते हैं । आपको दूसरे के घर की खबर ज्यादा रहती है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है पहला घर मेरा घर, दूसरा घर ऐसा नहीं है । आपका मूल घर तो जोगी जी का ही घर है । जो यहां बैठे हो उसी के कारण बैठे हो, केवल घर बदल लिये हो, आप समझ रहे हैं न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मंत्री जी, आपने जो कुर्ता पहना है वह किस कलर का है ।

---

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जो भी हैं कांग्रेस के लोग हैं । वे किसी व्यक्ति के आदमी नहीं हैं यदि होते तो चल दिये होते । खूब प्रयास कर लिया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा ।

श्री अजय चंद्राकर :- कांग्रेस के नहीं हैं, सब भूपेश बघेल जी के आदिवासी रथ के हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- क्या चीज ।

.................श्री यादव

यादव\12-09-2018\f14\04.05-04.10

श्री भूपेश बघेल :- क्या चीज ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने बोला भूपेश बघेल जी के आदिवासी रथ के हैं, कांग्रेस के नहीं हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, आदिवासी एक्सप्रेस चलाया था ।

श्री अजय चंद्राकर :- ओरीजनल वाला नहीं था, थोड़ी गड़बड़ हो गई ।

श्री भूपेश बघेल :- आप लोगों ने ही नकली, नकली बोलकर दुष्प्रचार कर दिया और आज तक उनकी जाति का पता भी नहीं लगा पाए । 15 साल में एक व्यक्ति की जाति का पता नहीं लगा पाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी ?

श्री अजय चंद्राकर :- बात खुल ही गई तो यह बता दीजिए कि भाभी जी को टिकट मिल रहा है या काट रहे हो ? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- कुल मिलाकर बात यही है कि इनकी हालत खराब है । यह जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं । यह कितना भी प्रयास कर लें, अजय जी बोल रहे थे कि रहना तो यहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह जान गये थे कि अब विधान सभा में पहुंचना मुश्किल है तो यह जो बीच का समय है, इसमें एक सत्र और बुला दें तो कम से कम विधान सभा में बैठने को मिल जाए । इसलिए यह सत्र बुलाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है । जनता जान चुकी है । रमन सिंह जी को भी पहचान चुकी है । भारतीय जनता पार्टी को भी पहचान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चुकी है । आने वाला समय कांग्रेस का है । कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम किसानों के हित की बात करेंगे । इसी सदन में कार्यक्रम बनाएंगे । अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अजय चंद्राकर :- भूपेश जी, इस भाषण के बाद आपको न घोड़े वाले न आपको घोड़ा देंगे, न बैलगाड़ी वाले बैल देंगे, अगली बार आपके लिए काश्मीर से खच्चर मंगाना पड़ेगा । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अजय जी, भूपेश जी घोड़े पर चढ़े थे या घोड़ी पर चढ़े थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक कहावत है - पूंछ उठाकर देखा, सब मादा थे । वह पूंछ उठाकर देखे थे या नहीं देखे थे, वह जाने ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब भूपेश जी की घोड़ा और घोड़ी दोनों में चढ़ने की उम्र निकल गई है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपके पास क्या है जिस पर भूपेश बघेल जी चढ़ जाएं, बताइए ? आपके पास ऐसी कोई चीज है ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही बात कह रहे हैं, अब बेटा जवान हो गया है, घोड़ी चढ़ाएंगे और आपको भी निमंत्रण देंगे, आप भी उस बारात में जाएंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- बिलकुल जाएंगे । आपने भाभी जी के बारे में नहीं बताया कि उनकी टिकट कट रही है या टिकट मिल रही है ?

श्री भूपेश बघेल :- कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, उसकी अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के बाद अंतिम में सी ई सी तक पहुंचेगा, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, अनुमोदन के बाद फिर जारी होता है । यह प्रक्रिया है । कोई एक व्यक्ति से नहीं होता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी पार्टी की परम्परा है कि आखिरी में प्रस्ताव पारित करके एक ही आदमी के लिए छोड़ देते हो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धनेंद्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रावधान किया गया है, इस सरकार का आपने पापों का आंशिक प्रायश्चित है । जो काम पांच साल पहले हो जाना चाहिए था, जैसे ही आप सरकार में बैठे, वैसे ही यह फैसला आपको ले लेना चाहिए था कि हम धान खरीदी के साथ साथ बोनस देंगे । लेकिन सत्र का अवसान भी हो गया और उसके बाद अपने पापों का थोड़ा बहुत, आंशिक प्रायश्चित, यह पूरा प्रायश्चित भी नहीं हो रहा है । अनुपूरक बजट बनाकर जो प्रावधान किया गया है यह एक आंशिक प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप लाया गया है । यदि आपको अपने वादों की थोड़ी बहुत भी चिंता होती तो आप उन तमाम सारी बातों का उल्लेख इस प्रायश्चित स्वरूप जो अनुपूरक बजट है, उसमें आपको कर लेना था। चाहे वह एक एक दाना धान खरीदी करने की बात थी, चाहे पूरे पांच साल तक बोनस देने की बातें थीं । हम लोग तो सोच रहे थे कि आप लोग उसको बजट में सम्मिलित कर लेते जो दो साल का बोनस नहीं मिला है, उसको भी हम लोग यहां पर पारित करने के लिए तैयार होते । बेहतर होता कि जो दो साल का आपने बोनस नहीं दिया है, वह भी दिया होता । आपने 2100 रूपए समर्थन मूल्य और 300 रूपए बोनस प्रति पांच वर्ष देने की बात की थी । एक एक दाना धान खरीदी करने की बात की थी, लेकिन आपने अपने किसी भी वादे का पालन नहीं किया । यह इस सरकार का किसानों के प्रति जो दुर्भावना है, वह अपने आप इनके पांच साल के कार्यकाल में भी पूरी तरह से स्पष्ट हुई है । धान हमारे मेहनत, खून पसीने की कमाई है । छत्तीसगढ़ में हमारे किसान की उपज के कितना मूल्य मिलता है ? आज हम सोना बेचने जाएं तो सोना रायपुर के बाजार में भी वही भाव बिकेगा, एक छोटे कस्बे में भी वही भाव बिकेगा और मुंबई में भी वही भाव बिकेगा । लेकिन हम जो खून पसीने से कमाते है उसके कितने भाव ? आज भी गांव के किराना दुकान में जो हम छोटे खर्चों के लिए बेचते हैं, दस किलो, पन्द्रह किलो जो गरीब लोग बेचते हैं, वह दस रूपए किलो माने एक हजार रूपए क्विंटल में किराना दुकानों में आज भी बिक रहा है । यदि हमारा धान पहले आ गया, सरकारी खरीदी चालू नहीं हुई तो हम कोचिये के पास बेचने जाएं तो उसी खून पसीने की कमाई को 1100, 1200 रूपए क्विंटल में बेचते हैं । फिर जब सरकारी धान खरीदी चालू हुई ....(जारी)

श्री मिश्रा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मिश्रा\12-09-2018\f15\.-.5

जारी.. श्री धनेन्द्र साहू :- में बेचते हैं। फिर जब सरकारी धान खरीदी चालू हुई तो हमारा आधा धान, लगभग आधी उपज जितना हमने पैदा किया उसकी आधी मात्रा मुश्किल से हम समर्थन मूल्य में बेचने जाते हैं तो हमें मिल गया। 5 साल पूरा होते-होते 1500 रूपये और चुनाव नजदीक आ गया तो ये 3 रूपये और, तो हमारी मेहनत की कमाई का एक तो 10 रूपये किलो में बिक रहा है, 12 रूपये किलो में बिक रहा है, 15 रूपये किलो में बिक रहा है और आखिरी साल चुनाव आ गया तो 18 रूपये किलो में बिक रहा है। आपका 2400 रूपये नहीं पहुंचा। आपने जो बोलकर किसानों से लिया कि हम 2100 रूपये और 300 रूपये मिलाकर हम 2400 रूपये में धान खरीदी करेंगे ये आपका कार्यकाल पूरा होते-होते तक भी आप 2000 रूपये तक ले-देकर पहुंच रहे हैं और वह भी कब? आपका 14-15 नवंबर को चुनाव की घोषणा होने वाली है। आपने 1 नवंबर से बोनस सहित धान खरीदी करने की बात कही है। आप इन 15 दिनों में कितना धान खरीदी करेंगे? शायद आपकी 01 प्रतिशत भी आवक नहीं आयेगी और 99 प्रतिशत धान हम लोग अपनी सरकार बनाने के बाद में खरीदेंगे। अपनी सरकार में हम लोग, जो हम लोगों का वायदा रहेगा उसके अनुसार हम लोग खरीदी करेंगे। मात्र आप 1 प्रतिशत धान की खरीदी करेंगे तो उसमें आप पूरी तरह से किसान को एक गुमराह करने का आपका एक बहुत सुंदर गेम प्लान है। इसके पहले हम लोगों ने कई बार मांगा कि आप एक नवंबर से धान खरीदी करिये, बहुत गरीब लोग हैं जो पंजीयन नहीं करा पाते हैं, जिनकी धान अर्ली वेराईटी की है पहले आ जाती है उनको उसका फायदा मिले लेकिन नहीं आपने इन 15 वर्षों तक ये फैसला नहीं किया। ये पता नहीं, जब आप चुनाव में जाने लगे, आपको कहीं से ये डर हुआ कि ये उनके खिलाफ में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि आपने धान खरीदी और बोनस का वायदा पूरा नहीं किया और यही आपकी सरकार बनने के लिए सबसे बड़ी रूकावट है तो आपने अनुपूरक बजट करके ये बात की। इसमें भी पूरी तरह से आपकी नीयत साफ नहीं है। ये पूरी तरह से गुमराह करने वाली बातें हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा ग्रीष्मकालीन धान है उसको आप क्यों नहीं समर्थन मूल्य देते? उस पर आप क्यों नहीं बोनस देते? इसकी तो बात ही नहीं आती। बोनस देना तो दूर की बात है आप समर्थन मूल्य पर भी खरीदी नहीं करते। हर बार 300, 400, 500 रूपये प्रति क्विंटल कम में आज हमारा किसान गर्मी के धान को बेचने को मजबूर होता है। आपने तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक कदम आगे बढ़कर रोक लगा दी। गर्मी के धान को बैन कर दिया, जो किसान गर्मी में धान लगायेगा उसकी मोटरपंप जप्त कर ली जायेगी, उनके बिजली के कनेक्शन काट दिये जायेंगे। जो सारे संसार में नहीं हुआ होगा वह काम भी इस प्रदेश में आपने किया। न तो किसी युग में हुआ है, न तो विश्व में हुआ है कि आपने अनाज की खेती करने पर बैन लगाया हो लेकिन आपने वह भी कर दिखाया है। तो ये पूरी तरह से आपका किसान विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा जिसका कि आप ढ़िढोरा पीटते हैं उसका क्षति आंकलन नहीं, उसका सर्वेक्षण नहीं, सर्वेक्षण में पूरी तरह से पक्षपात है। वास्तविक में जिन किसानों की फसल नुकसानी हुई है उनको आप क्षतिपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं, उनको आप फसल बीमा का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। यह स्थिति आज यहां पर है। आपकी रबी सिंचाई की कोई नीति नहीं है। अभी आज ही बहुत सारे किसानों का फोन आया कि इस साल सारे जलाशयों में पानी है, अभी हमारे धान के उतेरा का समय आ रहा है, सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, सरकार से जवाब आना चाहिए कि हम उतेरा करें कि आप रबी फसल के लिए पानी देंगे लेकिन आपको चिन्ता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी सदन में मौजद हैं घोषणा करें, जल्दी निर्णय लें, एकाध हप्ते के भीतर निर्णय लें कि आप पानी देने वाले हैं या नहीं इसे स्पष्ट करें?

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- धनेन्द्र जी, आप चिन्ता मत करो, इस साल हम किसानों को रबी फसल के लिए पानी देंगे। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सरकार, किसानों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। आपके जैसे नहीं है कि लोगों को घुमाते रहो। अगर हमारे पास पर्याप्त पानी है तो हम पानी देंगे। आप उसकी चिन्ता मत करिये। हम बोनस भी दे रहे हैं, हम पानी भी देंगे, हम फ्लेट रेट में बिजली भी दे रहे हैं, हम जीरो परसेंट ब्याज पर लोन भी दे रहे हैं और हम सोलर पंप भी दे रहे हैं, हम आर.बी.सी. 6(4) भी दे रहे हैं, हमने 1300 करोड़ रूपये बीमे की राशि भी दी है। ये सब हम ही दे रहे हैं, आप थोड़ी दे रहे हैं।

श्री धनेन्द्र साहू :- आपकी सरकार को पहले जगाना पड़ता है। आपको जगाना पड़ता है तब आप जागते हैं, वरना आप सोये रहते। तो आप अभी स्पष्ट घोषणा करिये कि हम रबी फसल को सारे बांधों और जलाशयों से पानी देंगे।...

श्री कुरैशी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कुरैशी\12-09-2018\f16\04.15-04.20

श्री धनेन्द्र साहू :- आप अभी स्पष्ट घोषणा करिये कि हम सारे बांध और जलाशयों से रबी फसल के लिए पानी देंगे । आप किसानों से बोलिए कि उतेरा मत बोवें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- धनेन्द्र भईया, यह सरकार कम से कम जाग तो रही है। 53 साल तो आप लोग जगाने से भी नहीं जागे । इसका भी जवाब दो थोड़ा । अपनी सरकार के पीरियड में किसानों के हित में कोई भी काम किये हो तो बता दो । एकाध काम गिनाओ जो आपने किसानों के लिए किया हो । सारा काम तो भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार में हुआ है ।

श्री धनेन्द्र साहू :- ये सिर्फ किसानों का मुखौटा लगाते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाटो एक छोटा सा प्रश्न है, जब हवाई छिड़काव हुआ तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे ? पहले माफ करने की घोषणा हुई फिर हवाई छिड़काव की वसूली हुई, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे ? माफ करने के बाद दुबारा वसूली हुई थी, यह बताइए । दोनों समय आपके नेता थे ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रणाम करता हूं उस नेता को। ये पंडित श्यामाचरण शुक्ल की बात कर रहे हैं, उन्होंने हवाई छिड़काव करवाया था । यह उनकी सोच थी, आपकी सोच नहीं है । आप तो केवल किसानों का मुखौटा लगाते हो और काम दूसरे का करते हो । आपने किसानों के हक में एक भी काम ईमानदारी से नहीं किया और न ही सोच है । आप इतने एनीकट बना रहे हो एक बूंद सिंचाई नहीं हो रही है । किसी खेत में सिंचाई नहीं हो रही है । पूरे एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए । बारिश में आपने सारे फाटक बंद कर दिये हैं । हमारे खेत के खेत डूबे हुए हैं । बारिश में एनीकट का गेट बंद रखने की क्या जरूरत है, आपने एक भी एनीकट का गेट नहीं खोला जिसके कारण पूरी फसलें बर्बाद हुई हैं । आपको किसानों की चिंता नहीं है । मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यदि यह सरकार अपने को किसान हितैषी बताती है तो तो इसी बजट में प्रावधान करे कि जो 2 साल का बोनस नहीं दिया है उसका उल्लेख भी इसी बजट में करे, हम उसको भी यहां पारित करने को तैयार हैं, धन्यवाद् ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप बचे हो ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अरे बचे नहीं, आप देख रहे हो मैं खड़ा हूं (हंसी)। माननीय अध्यक्ष जी, अभी बृजमोहन जी बोल रहे थे, इनको मालूम होना चाहिए कांग्रेस की सरकार के कार्याकल में गंगरेल का रिजर्व वाटर, प्लेट काटकर किसानों को पानी दिया । अभी आपसे मांग करते रहे और आपने पानी तक नहीं दिया और किसानों के हित की बड़ी बड़ी बात करते हैं । है आपके पास इसका जवाब ? हमनें रिजर्व वाटर का पानी प्लेट काटकर दिया था ।

अध्यक्ष महोदयस, लगभग दो माह पूर्व 16वीं विधान सभा का अंतिम सत्र आपने निरूपित किया था । अध्यक्ष महोदय, आप एक तरह से न्यायमूर्ति के रूप में हम लोगों के साथ रहे हैं । आपको याद होगा 2 जुलाई से 6 जुलाई तक आपने मानसून सत्र आहूत किया । उसमें आपने खुद निरूपित किया कि ये इस चतुर्थ विधान सभा का अंतिम कार्यकाल है । आपने खुद उसे अंतिम कार्यकाल घोषित कर दिया, फिर इस सत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी ? मानसून सत्र में ही सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था, उसमें ही धनराशि बढ़ाकर दे देते तो सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़े । इस देश के इतिहास में कहीं कोई नजीर नहीं है कि दो महीने के बाद फिर सत्र बुला लिया जाए । अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि दो विधान सभा के सत्र में अंतराल कम से कम 6 माह होना चाहिए और आपने 2 महीने के अंतराल में सत्र बुला लिया । आपने उसी समय राशि बढ़ाकर यह प्रावधान क्यों नहीं किया ? किसने रोका था आपको ? उस वक्त आपकी सोच नहीं थी कि किसानों को बोनस दिया जाए । उस समय आपके दिमाग में यह बात नही आई थी कि किसान इससे नाराज होगा और बोनस देना जरूरी है, उस वक्त आप कुछ और सोच रहे थे । आपको प्रावधान करने से किसने रोका था ? आपने उस वक्त प्रावधान क्यों नहीं किया ? क्या कर रहे थे खाद्य मंत्री जी ? आपने सुझाव क्यों नहीं दिया ? मंत्रिपरिषद की मीटिंग में अनुपूरक बजट पेश होता है, आप कहां सो रहे थे ? पाण्डेय जी आप जैसा विद्वान आदमी ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हम जाग गए थे ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अरे क्या खाक जगे हो, पीएलएम । अभी भूपेश जी ने कहा -

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जब कलेजा लगा फटने तो खैरात लगी बटने । इसका मतलब समझते हो। मैं समझा दूंगा ठीक से । [14](xx)

अध्यक्ष महोदय :- इसको हटा देना ।

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\12-09-2018\f17\4.20-25

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार का जो सामूहिक रूप से समय से निर्णय लेना चाहिए था, वह सरकार ने नहीं लिया और दो महीने के बाद फिर सत्र बुलाना पड़ा, इसमें शासन का, जनता की गाढ़ी कमाई अनावश्यक रूप से खर्च की गई ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो उद्गार व्यक्त किये थे, उससे प्रमाणित हो चुका था कि ये चतुर्थ विधान सभा का आखरी सत्र था, दो महीने बाद आप सत्र बुलाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं । अगर आप में जरा सा भी सोच होती, किसानों के प्रति हमदर्दी होती तो उसी वक्त उसी अनुपूरक बजट में बढ़ाकर आप प्रावधान करते और मानना पड़ता । दूसरी बात, मैं बताना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी, 2014 को प्रदेश की जनता के नाम सरगुजा से संदेश दिया था और उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, उसको मैं अक्षरश: आपको पढ़कर सुनाता हूं । घोषणा-पत्र का तीसरा बिन्दु है-300 रूपये प्रति क्विंटल प्रति वर्ष बोनस । हमने किसानों के समृद्धि के विषय को लंबित रखने की बजाय केन्द्र के निर्णय का इंतजार न करते हुए राज्य शासन की ओर से प्रतिवर्ष धान खरीदी पर 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी निर्णय लिया है । अगर आपने निर्णय लिया होता तो आपने उसी वक्त बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, महाराज जी, आप बोनस का विरोध कर रहे हो या सत्र बुलाने का । विरोध किसका है ।

[14] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के दबाव में आकर आपने विशेष सत्र बुलाकर आपने प्रावधान किया है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आप चाहते थे कि विशेष सत्र हो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, विशेष सत्र का तो मैं कह रहा हूं ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- महाराज जी, आप चाहते थे कि विशेष सत्र बुलाकर...

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, विशेष सत्र की जरूरत क्यों पड़ गई, आपने उसी वक्त प्रावधान क्यों नहीं किया ? उसी समय आप प्रावधान करते तो जनता की गाड़ी कमाई का अपव्यय नहीं होता ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- अगर उस समय नहीं किया, अभी कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या ? इतना बस बता दो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के दबाव में आपको सत्र बुलाना पड़ा ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- दबाव में ही सही, किसानों को तो हम ही दे रहे हैं न। किसान को नहीं देना चाहिए ? आप बता दो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, पाण्डेय जी, किसान को देना पड़ेगा, आप कहां जाएंगे । किसान आपको बक्शता नहीं है, किसान आपको बक्शेगा नहीं । किसान को पानी भी देना पड़ेगा, किसान को आपको बिजली भी देनी पड़ेगी और किसान को समर्थन मूल्य और बोनस भी देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, जनता आपको भागने नहीं देगी । आप सोचते हो कि आपका कार्यकाल खतम हो जाए, आप बचकर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा । आपके कार्यकाल में ही रहते हुए सब चीजों का हिसाब भी आपको देना पड़ेगा और बोनस भी देना पड़ेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- रायपुर ग्रामीण में आप खेती करते हो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपने मेरा खेत देखा नहीं है, चलिए मेरे साथ। आप चलिए, मैं दिखाता हूं । माननीय चन्द्राकर जी को मालूम है, बृजमोहन जी को मालूम है । खेती किसानी करो, ऐसे ही नांगर चलाने से काम नहीं चलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 का 63,10,424.83 करोड़ मेट्रिक टन एवं वर्ष 2015 में 59,29,232.49 मेट्रिक टन खरीदे गए, धान का बोनस आपने क्यों नहीं दिया ? आपने 2014, 2015 में धान खरीदा, उसका बोनस आपने नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में आप सायलेंट हैं । उस पर चुपचाप डाका डालना चाहते हैं । आपको कुल मिलाकर सिर्फ 3672 करोड़ रूपये दोनों सालों का बोनस और देना पड़ेगा और दिए बिना बचकर जा नहीं सकते। आपने केवल 24 सौ करोड़ का प्रावधान कर लिया, आपको दो सालों का बोनस देना चाहिए था, वह आपने नहीं दिया और 3672 करोड़ रूपए जनता के, किसानों के पैसे पर आपने डाका डाला है, जो आप देना नहीं चाहते, आपकी नीयत में खोट है इसलिए किसानों का बोनस नहीं देना चाहते और इस अनुपूरक बजट में 3672 करोड़ रूपए जोड़कर किसानों के धान का बोनस, जो कुल मिलाकर 6072 करोड़ है, उतना रूपए आपको ईमानदारी के साथ देना चाहिए । अगर ये रूपये नहीं देते हैं तो ये मानकर चला जाए कि किसानों के धन पर, किसानों की राशि पर आप डाका डाल रहे हैं, देने की नीयत आपकी नहीं है ।

श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\f18\04.25-04.30

जारी... श्री सत्यनारायण शर्मा :- किसानों की राशि पर आप डाका डाल रहे हैं। उसको देने की आपकी नीयत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसान किसको मानते हैं? आपका क्या लक्ष्य है? आप क्या सोच रहे हैं? प्रदेश के 34.70 लाख किसानों को या आपके पंजीकृत 14.51 लाख जो किसान हैं, आप किसको किसान मान रहे हैं? धान बेचने वाले 13.27 लाख किसान हैं, आप तीनों श्रेणी में किसको किसान मानते हैं? आपकी गलत नीतियों के कारण किसान धान बेचने से वंचित रह गया। उसको बोनस कौन देगा? उस किसान की क्या गलती है? आपकी गलत नीतियों के कारण किसान धान नहीं बेच पाया। किसान की क्या गलती है? उसको बोनस मिलना चाहिए। उसको देने की आपकी नीयत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार नकली, घड़ियाली आंसू बहाने के सिवाय कोई काम नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग जिले में डेंगू फैला। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, आप दुर्ग जिले के दौरे पर क्यों नहीं गये? आपको किसने रोका था? इतने लोगों की जानें गयीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- क्या है, अब आप डांटों-वाटो मत। अब डेंगू कंट्रोल हो रहा है, वह आप ही के आशीर्वाद से है। अब आप डांटना-फटकारना बंद कर दो।

अध्यक्ष महोदय :- आप डांट सकते हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- ये देखिये? आप कैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं? जब लोग डेंगू से मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? लोग बेमौत मारे गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना दुर्भाग्य है दुर्ग जिले के डेंगू के मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- वे सबसे ज्यादा सम्मान आप ही का करते हैं। आपके वक्तव्य के समय में वे एक बार भी खड़े नहीं होते हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वे भले आदमी हैं। (हँसी) अध्यक्ष जी, इसके दो कारण हैं। एक तो मेरे भय से खड़े नहीं होते। वे जानते हैं, मेरी आदत हैं, मैं इनकी तार-तार कर दूंगा। (हँसी) वे डर के मारे खड़े नहीं होते। माननीय अध्यक्ष जी, रायपुर जिले में जो डेंगू के मरीज हैं, उनके लिए नि:शुल्क इलाज नहीं है। रायपुर के डेंगू के मरीजों का नि:शुल्क इलाज क्यों नहीं है ? आज दो तरह की नीतियां क्यों चला रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज, हम डेंगू का इलाज सब करवा देंगे, आप डेंगू का विषय ही मत करो, फालतू और फैल जायेगा। एक तो वह अभी कंट्रोल हो रहा है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप क्या फैलाकर आये हैं ? विदेश गये थे, क्या कर के आये हैं ? (xx)[15] लेकर के आये हैं क्या ?

श्री अरूण वोरा :- वैसे भी आप पाण्डेय जी से पूछ लीजिए, उनके क्षेत्र में करीब-करीब 32 लोग मर चुके हैं और दुर्ग में भी शुरुआत हो गयी है। पाण्डेय जी, आप बताइये।

अध्यक्ष महोदय :- (xx) विलोपित कर दें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(xx) [15] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज, मैंने पूछा कौन-कौन जनप्रतिनिधि यहां घूमते हैं, कौन-कौन ? पता किये तो सिर्फ पाण्डेय जी का नाम लिये। मैं आपका नाम लेकर पूछा वोरा जी कहां है तो बोले कि जब वीआईपी आते हैं, उस समय फोटो भर खींचवाते हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे तो पाण्डेय जी अच्छे हैं, जो मीटिंग लेकर अपने जिले के लोगों को नि:शुल्क इलाज कराने की व्यवस्था की और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं ? रायपुर में डेंगू के मरीज हैं और इनका नि:शुल्क इलाज नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? रायपुर के लोगों ने क्या बिगाड़ा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- महाराज, आज आखिरी सत्र है, आपका आज आखिरी भाषण है, जो कह लें, सब स्वीकार है। लेकिन पूरे पांच साल में आदरणीय अरूण वोरा जी उतने राष्ट्रीय स्तर के अनुभव, नजदीक से सब कुछ देखा, लेकिन पांच साल में एक भाषण नहीं दे सके। मुकरी-वुकरी लोग जो साइड हीरो रहते थे, पिक्चर में जो भूमिका निभाते थे, छोटे-मोटे रोल प्ले करते थे, ये मुकरी टाइप बीच में खड़े हो जाते हैं। आप समय लेकर कुछ तो भाषण दे दो।

श्री अरूण वोरा :- आप चिंता मत करिये, 2018 में हम लोग शासन में रहेंगे। हम क्या रहेंगे, वह हमारे आने के बाद ही आप देखेंगे। हम वहां बैठेंगे।

समय
4.28 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)**

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय सभापति जी, रायपुर में डेंगू के मरीज हैं, रायपुर में ज्वाइंडिस से कई मौतें हुईं, दुर्ग जिले में डेंगू से कई मौतें हुई हैं, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहीं दौरा नहीं किया। क्या वजह थी, आप किस चीज में व्यस्त थे ? स्वास्थ्य मंत्री होकर भी आप दौरा नहीं करना चाहते । आपसे तो अच्छे प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी हैं, जो दुर्ग जिले में डेंगू के मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, रायपुर में डेंगू के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। नि:शुल्क इलाज नहीं हो पा रहा है। आप निर्देश दीजिए कि रायपुर में डेंगू के मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जायेगा। आपको आदेश देने से किसने रोका है ? माननीय सभापति जी, इस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी किसी काम के नहीं हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- आपको कैसे मालूम कि वे किसी काम के नहीं हैं? (हँसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- वह तो आसपास, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं। (हँसी) वह बल्क का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है? वहां से शुरू करूं?.....

जारी श्रीमती सविता

सविता\12-09-2018\f19\04.30-04.35

जारी श्री सत्यनारायण शर्मा :- कि नहीं सुना है, वहां से शुरू करूं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा इस प्रदेश की आवश्यकताएं हैं और ये सरकार उसमें विफल रही है, डेंगू बीमारी से लोग रोज-रोज मर रहे हैं और ये सरकार उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करती। मैं इस सरकार की कारगुजारी का पर्दापाश कर रहा था।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को पिछले 2 सालों, वर्ष 2014-2015 का बोनस और समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और ये सरकार को देना पड़ेगा। सरकार ने जो अभी बजट प्रोविजन किया है, ये भी कांग्रेस के दबाव के कारण किया है वरना ये भी नहीं करना चाहते थे। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

डॉ. खिलावन साहू (सक्ती) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग अनुदान दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़, अठ्हत्तर लाख, एक सौ रूपये के बजट का समर्थन करता हूँ और सदन से निवेदन करता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश है। यहां 37 लाख, 76 हजार कृषक हैं और यहां की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि है । हम देखते हैं कि जब वर्ष 2003 में इनकी सरकार थी तो किसानों की क्या स्थिति थी? वे किसान जो दिनभर खेतों में काम करता है, अपना खून पसीना बहाता है जिसको दुनिया अन्नदाता कहती है और इनकी सरकार में उस किसान से 14 प्रतिशत ब्याज लेते थे, इनकी सरकार में 75 प्रतिशत किसान डिफाल्टर होते थे, मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनायीं और आज हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जो किसानों को सोसायटी से जीरो परसेंट ब्याज दर में कृषि कार्य के लिए कर्ज देती है। डॉ. रमन सिंह जी की सरकार में आज छत्तीसगढ़ का एक भी किसान डिफाल्टर नहीं है। जब इनकी सरकार थी तो किसानों द्वारा ऋण लेने पर 14 प्रतिशत ब्याज लगता था, वह कर्ज छूट नहीं पाता था, उसके बेटे के नाम पर कर्ज आ जाता था, वह भी कमाने खाने के लिए जम्मू कश्मीर चला जाता था, वह नाती के नाम पर आ जाता था, लेकिन वह सरकार कर्ज छूट नहीं पाता था, घर में ताला चाबी लग जाता था, अपनी बच्चों को लेकर जम्मू-कश्मीर कमाने खाने चले जाते थे ये स्थिति थी, लेकिन आज माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने उस 14 प्रतिशत ब्याज दर को घटाते-घटाते जीरो परसेंट किया है और ऐसा नहीं है कि किसान सोसायटी से कर्ज नहीं ले रहे हैं वे पहले से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, लेकिन उस कर्ज को छूट भी रहे हैं। आज 90 प्रतिशत से ऊपर किसान जो सोसायटी से कर्ज लेते हैं, उसको आज छूट रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सक्ती में वर्ष 1980 में नहर, हसदेव बांगों परियोजना लेफ्ट ब्रांच केनाल आकर रूकी थी, लेकिन जैसे ही इस देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, वह जानते हुए भी कि यहां कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जांजगीर-चांपा जिले में नहरों का जाल बिछाने का काम किया और आज हमारा जांजगीर-चांपा जिला इस प्रदेश का सबसे एरीगेटेड जिला है वहां 85 प्रतिशत सिंचाई होती है, आज सबसे ज्यादा धान बेचने वाला कोई जिला है तो जांजगीर जिला है। मैं इस सदन के माध्यम से परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ताधारी दल और जांजगीर जिले के किसानों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने नहरों का जाल बिछाया है, जिसका लाभ ये मिला कि पिछले समय माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने जो 211 करोड़ रूपये की सर्वाधिक राशि का बोनस दिया था, वह हमारे जांजगीर चांपा जिले के किसानों को मिला है और इसी तरह से आज जो बजट में 2400 करोड़ रूपये का प्रावधान किये हैं, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कभी बोनस नहीं दिया, लेकिन आज इनको पीड़ा हो रही है कि ये सरकार बोनस क्यों दे रही है? ये बोलते हैं कि सत्र अभी क्यों बुलाया गया? इस विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी ? लेकिन इन्होंने कभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की। किसानों के हित में न तो विशेष सत्र रखा, ये बोनस की बात जरूर करते हैं कि किसानों को बोनस

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

मिलना चाहिए, लेकिन जब सरकार बोनस देती है चाहे 2100 करोड़ रूपये दी है तब भी इन्होंने विरोध किया और आज सरकार 2400 करोड़ रूपये दे रही है तब भी विरोध करते हैं।

मानननीय सभापति महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार मोबाईल बांट रही है जब हम ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल बांटने जाते हैं, वहां के किसान, महिलाएं या जो हमसे मिलते हैं उनके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता देखी जाती है, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये किसान हितैषी सरकार कहलाती है। हमारी सरकार ने कृषि सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किये हैं, बहुत सारे बांधों, नहरों, तालाबों का निर्माण किया है, कृषि के क्षेत्र में शाकम्भरी योजना के बारे में ....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\12-09-2018\g10\04.35-04.40

पूर्व जारी.. डॉ. खिलावन साहू :- कृषि के क्षेत्र में शाकम्भरी योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि 2003-04 में हमारी सरकार बनी और 2005-06 में हमारी सरकार ने शाकम्भरी योजना निकाली। उस योजना के माध्यम से डीजल पंप, सबमर्शिबल पंप या अन्य कूप हैं इनको 50 परसेन्ट या 75 परसेन्ट छूट दे करके किसानों की आय को दोगुनी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी केन्द्र की नरेन्द्र मोदी जी सरकार का लक्ष्य है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करेंगे। इस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जब इनकी सरकार थी तो यह छत्तीसगढ़ अमीर धरती के गरीब लोग बोलते थे, निश्चित रूप से यह छत्तीसगढ़ की धरती अमीर है। जहां भगवान राम की माँ ने जन्म लिया, जहां पर भगवान राम की मां के अलावा ऋंगी, अगस्त्य, मतंग, कंक ऋषि जैसे महात्मा इस धरती पर जन्म लिये। लेकिन इसको गरीब किसने बनाया, जिन्होनें इस देश में 55-60 साल शासन दिया।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय आप विषय पर आईये न। आप इधर-उधर भटक रहे हैं।

डॉ. खिलावन साहू :- मैं विषय पर ही आ रहा हूं। मैं उसी बात को बोल रहा हूं वह छत्तीसगढ़ जो आपके समय मे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन अंतर केवल 14 साल का है। इन 14 सालों में आज हिन्दुस्तान के 5 विकासशील राज्यों के साथ गणना होती है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की होती है। वह छत्तीसगढ़ जो कभी धान का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कटोरा कहलाता था, लेकिन आपकी सरकार में हम लोग बगल वाले के घर के पास बाढ़ी मांगने जाते थे। आपकी सरकार में ये छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, लेकिन आपने छत्तीसगढ़ को लूटा था। आज इन 14 सालों के अंदर में हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में..।

श्री अमरजीत भगत :- धान का कटोरा खाली हो गया है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

डॉ. खिलावन साहू :- यह धान का कटोरा है। रमन सरकार में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा है। इनकी सरकार में किसान जो अन्न उत्पादन करता है, उसके पास घर में खाने के लिए दाने नहीं होते थे। जैसे ही 2003 में भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह जी सरकार बनी, डॉ. रमन सिंह जी ने कहा कि अगर इस प्रदेश में कोई भूखा सोता है तो मैं चैन की नींद सो नहीं पाता। अगर भूखा मरता है उसका सारा कलंक मुझ पर लगता है। इसलिए उनहोंने एक नियम निकाला, 35 किलो चावल प्रति परिवार देना शुरू किया। लेकिन विरोध किसने किया ? उसके बाद आज हमारी सरकार 1 रुपये किलो चावल दे रही है। यह हिन्दुस्तान, देश और दुनिया की पहली सरकार है जो 60 लाख परिवार को एक रुपये किलो चाव उपलब्ध कराती है। वह छत्तीसगढ़ है, 55 साल इन लोगों ने शासन किया, आज हमारी सरकार को इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन करते हुए 14 साल पूरा हो गया है। आज हिन्दुस्तान के 5 विकासशील राज्यों के साथ केवल तुलना ही नहीं होती है बल्कि आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो मेरा छत्तीसगढ राज्य है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला, मनरेगा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला, बाक्साईट का शत-प्रतिशत उत्पादन करने वाला, टिन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, हमारी बेटियों, बहनों को सायकिल प्रदान करने वाले वाला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य है। कालेज जाने वाले हमारे विद्यार्थियों को विशेषकरके हमारी बहनें, बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। मुफ्त मोबाईल बांटने वाली इस देश ही नहीं इस दुनिया की पहली डॉ. रमन सिंह जी की सरकार है जो अपने यहां रहने वाली माताओं, बहनों को जिनकी आधी आबादी है जिनका प्रदेश के विकास में योगदान है, 50 लाख लोगों को सरकार मोबाईल बांट रही है।

श्री अमरजीत भगत :- पूरे देश में शराब बेचने वाली सरकार केवल छत्तीसगढ सरकार है।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त कीजिये।

डॉ. खिलावन साहू :- माननीय सभापति महोदय, शराब की बात करते हैं। शराब की नीतियॉ किसने बनाई थी ? इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा भय का आंतक था। मैं इस प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने नियम निकाला कि 3 हजार से नीचे की जनसंख्या के जितने भी गांव में शराब भट्टी खुली हैं, हम उन सबको बंद करेंगे। आप शराब की बात करते हैं, अमरजीत जी 3 हजार से नीचे की जनसंख्या के किसी भी गांव में कहीं भी शराबभट्टी नहीं है। यहां पर हमारी आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल जी बैठे हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पीड़ा को समझा। जो बाहर के लोग यहां पर आतंक मचाते थे, आज कोई भी बाहरी आदमी उस शराब दुकान में काम नहीं करता है। गांव का बेटा, भाई उसमें काम करता है, लेकिन इनको पीड़ा होती है। आज इनकी दुकान नहीं चल रही है। सारे ठेकेदार इनके लोग होते थे, लेकिन आज सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- क्या भाषण में बोलना है यह तो देख लीजिए ?

डॉ. खिलावन साहू :- मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं तो कृषि पर ही बात कर रहा था।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- किसकी दुकान चल रही है, क्या बताना पड़ेगा ?

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\g11\04.40-04.45

डॉ0 खिलावन साहू :- आदरणीय सभापति महोदय, आज अनुपूरक बजट के विषय में चर्चा हो रही है। आज हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं अपने जांजगीर-चाम्पा जिले की बात करूंगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिये।

डॉ0 खिलावन साहू :- माननीय सभापति महोदय, 55 साल इनकी सरकार रही। आज जांजगीर-चाम्पा जिला इस प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला भी है और धान उत्पादन करने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाला जिला है। लेकिन 55 साल में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं खुला, यह अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने से और कांग्रेस की सरकार रहने से। आदरणीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 (श्रीमती) रेणु जोगी (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक बजट वर्ष 2018-2019 के विरोध या कहिये उसके पक्ष में ही बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। क्योंकि दो मत नहीं है कि पूरा विपक्ष इसमें एकजुट है कि किसानों को जो बोनस की राशि दी जा रही है, तो हम सब चाहते हैं कि किसानों के साथ जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय किया था, उसे पूरा किया जाये। साथ ही आसंदी से या मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शेष वर्षों का भी बोनस उनको दिया जाए।

क्योंकि 24 सौ करोड़ रूपये का बजट इसमें प्रस्तुत है उसमें 12 सौ करोड़ किसानों के लिए है और 12 सौ करोड़ रूपये की राशि अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए है। चूंकि मेरे विधानसभा का क्षेत्र यहां इस समुदाय के लोग ज्यादा निवास करते हैं तो मैं उनके हित की बात कहूंगी कि हमारी जो केन्द्र सरकार है, उसने लघु वनपजों के दाम 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है। हम पेपरों के माध्यम से पेट्रोल-डीजल के दाम के बारे में पढ़ते हैं, दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। परन्तु जो प्रमुख फसलें मेरे इलाके और बस्तर और सरगुजा अन्य इलाके में होती हैं, उसके दाम 10 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक कम कर दिए हैं। 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देती है और उसमें 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। तो यह सब कहने का मेरा यह अर्थ है कि जब 12 सौ करोड़ रूपये आपने उसके लिए प्रावधान किया है तो इन लघु वनोपजों का दाम इस महंगाई के जमाने बढ़ाया जाये। मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगी कि कुसमी लाख, कई लोग तो शहरी इलाके से आते हैं, ये नाम भी नहीं सुना होगा। कुसमी लाख का कीमत 320 रूपया प्रति किलो था, वह 55 प्रतिशत कम होकर के 150 रूपये हो गया है। रंगीनी लाख जो 230 रूपये प्रति किलो था, वह कम होकर सौ रूपये प्रति किलो हो गया है, अर्थात 56 प्रतिशत कम हो गया है। इसी तरह इमली जो बस्तर में बहुतायत में होता है और हमारे इलाके में 22 रूपये प्रति किलो था, वह कम होकर 18 रूपये प्रति किलो हो गया है। महुआ जो सब जगह होता है ....जारी श्री श्रीवास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीवास\12-09-2018\g12\04.45-04.50

जारी...डॉ. श्रीमती रेणू जोगी .....22 रूपये प्रति किलो था, वह कम करे 18 रूपये प्रति किलो हो गयी है । महुआ जो सब जगह होता है, 22 रूपया उसका समर्थन मूल्य, कम करके 20 रूपया किलो किया गया है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- महुआ 40 रूपया हो गया है ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- देखिये, यह सरकारी रेट है । बाजार की बात नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- आप नहीं समझ रहे हैं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- समर्थन मूल्य जो केन्द्र सरकार तय करती है, माननीय मोदी जी ने तय किया है, मैं उसकी बात कर रही हूॅं जायसवाल जी ।

श्री अमरजीत भगत :- इस बार पहली बार हुआ है कि केन्द्र सरकार ने वन उत्पाद का जो दर है, उसको घटाया है ।

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी :- करंज बीज है, जो 20 रूपये प्रति किलो था, वह कम होकर 18 रूपया हो गया है । ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, अंत में हर्रा 11 रूपये प्रति किलो था, वह कम होकर 8 रूपये कर दिया गया है । 27 प्रतिशत की इसमें भी गिरावट आई है । यानी कहीं कुछ बढ़ा नहीं है, चिरौजी का बता दूं, आप सब महानुभाव उसका उपयोग करते हैं, पकवान वगैरह बनाने में, खाने में । उसमें भी 60 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है । बाजार मूल्य 1000 रूपये से ऊपर है । यह सरकारी समर्थन मूल्यों में जो कटौती है, उसकी ओर मैं माननीय सदन का और आसंदी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि राशि का प्रावधान इस वर्ग के लिए हुआ है, ट्रायवल और अनुसूचित जाति के लिए हुआ है ।

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, ट्राईफेड ने जो दर तय किया है, उसके ऊपर राज्य सरकार ने फेडरेशन के माध्यम से बोनस के रूप में अतिरिक्त राशि दिया है । जैसे इमली है, उसमें हमने चार रूपये अतिरिक्त राशि, चिरौंजी है, उसमें 60 रूपये अतिरिक्त राशि दिये हैं । तमाम जो वनोपज है, उसमें राशि राज्य सरकार ने बढ़ाई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कराया है कि जब 12 हजार करोड़ की राशि इस बजट में है तो करीब 32 प्रतिशत आदिवासी भाई और लगभग 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग पूरे प्रदेश में निवास करते हैं, उनके हित में भी यह फैसला किया जाना चाहिये । अभी आप जानकारी दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वह भी पर्याप्त नहीं है । इमली का आपने चार रूपये प्रति किलो बढ़ाया है । इस पर पुनर्विचार करके उनको लाभ दिया जाये । अंत में महिला उत्पीड़न भी सबसे अधिक बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में हो रही है । उस पर भी यदि नियंत्रण कर सकें तो यह अच्छा होगा । अंतिम बात जो कहना चाहती हूँ कि लगता है कि यह सब बजट पारित करने का यह आखिरी दांव या ब्रम्हास्त्र माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, वोटों की फसल काटने के लिए हो रहा है, चूंकि मैं अंत में विदाई समारोह में नहीं थी, मैं सभी सदस्यों को शुभकामनायें देना चाहती हूँ कि अगले सत्र में हम लोग यहां पुन: मिलेंगे । जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है । टाटा, फिर मिलेंगे । धन्यवाद । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान के सन्दर्भ में मैं बात रखने के लिए और असहमति व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, 2433 करोड़ 78 लाख ......

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी जो आपका व्यक्तित्व है, आज आप स्वांग नहीं करते तो आपका आखिरी भाषण शानदार होता । आप ओरिजनल आदमी हैं । ओरिजनल ठाकुर हैं । ओरिजनल राजा-महाराजा हैं । कहां आप स्वांग-फांग में आ जाते हो । बिल्कुल ओरिजनालिटी है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मर्सिडिस से सायकल और बैलगाड़ी में अवधेश जी को बुलवा दिया गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप ओरिजनल रहेंगे तो 27 परशेंट से उपर चल देंगे । लोकप्रियता में उससे ज्यादा हो जायेंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक लगता है कि उसी बात को लेकर नहीं है । भूपेश भाई का 21 प्रतिशत, टी.एस.सिंहदेव का 11 प्रतिशत, यह शुद्ध रूप से भारतीय

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष का प्रतिशत, यह मुख्यमंत्री जी के प्रतिशत का इतना नजदीक पहुंच गया है, हमने मोबाईल बम भी बांटा, हमने प्रेशर कुकर भी बांटा, हमने टिफिन भी बांटा, हमने न जाने क्या-क्या किया, क्या-क्या वायदे किये, बावजूद उसके इतना अंतर सिकुड़ते हुये दिख रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पांच मांग संख्याओं में 2433.78 करोड़ राशि के अनुपूरक की मांग की गयी है । यह धान के समर्थन मूल्य के लिए है । धान के बोनस के लिए है । 33.78 करोड़ रूपये चुनाव इत्यादि प्रबंधन के लिए है । यह सदन के अनुपूरक की कार्यवाही को लेकर जो बात उठी है, विरोध किस बात का है । विरोध इस बात का है कि पिछले 50 सालों से कांग्रेस के सोने की बात हो रही थी, न जाने कांग्रेस कितने सालों से सोती रही, यह तो दो महीने पहले सोने का उदाहरण प्रस्तुत हुआ । अध्यक्ष महोदय, दो महीने पहले हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जिसने कहा था कि हमने वर्ष 2018 के धान का 300 रूपये बोनस देंगे, वह किन खयालों में थी, किस निद्रा में थी कि वह 300 रूपये बोनस की बात उस प्रथम अनुपूरक में........

जारी....श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\g13\04.50-04.55

जारी.........श्री टी.एस. सिंहदेव :- कि 2 महीने पहले हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जिसने कहा था कि हम वर्ष 2018 के धान का 300 रूपया बोनस देंगे, वह किन ख्यालों में थी? किस निद्रा में थी कि वह 300 रूपये बोनस की बात उस प्रथम अनुपूरक में सम्मिलित नहीं कर सकी ? आपको चुनाव कराना है और चुनाव कराने के लिये मतदाता के जागरूकता के लिये आपको 2 महीने बाद पता चलता है । वह बिदाई समारोह था चुनाव के लिये और अब राशि का प्रावधान कर रहे हैं 10 करोड़ 55 लाख रूपया का जागरूकता करने के लिये मतदाताओं का, उसके लिये आप अनुपूरक बुला लें इस बात का विरोध है । साथ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिये यात्रा भत्ता । आप यात्रा भत्ता मांग रहे हैं 4 करोड़ 3 लाख रूपये का क्या आपको जानकारी नहीं थी कि चुनाव कराने में यात्रा भत्ता लग सकता है, क्या यही हमारे 15 साल का अनुभव है ? और तीसरा 33 करोड़ 78 लाख का हिस्सा आगामी विधानसभा चुनाव में वी.वी.पी.ए.टी. मशीनों के उपयोग करने वाले व्यवस्था के लिये, यह क्या नया वी.वी.पी.ए.टी. मशीन की बात आयी, यह लागू हो चुकी थी । पिछले अनुपूरक के पहले सबको मालूम था कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यह लागू होने वाला है तो कुल-मिलाकर आपने इस सबको जो बुलाया है, सारी परंपराओं को तोड़ा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं दो विषय पर आपसे जानकारी चाहूंगा कि आपके भाषण का शायद पीसीसी अध्यक्ष ने बहिष्कार कर दिया है और दूसरा गुलाबी रंग से इतनी जल्दी आपने पीछा कैसे छुड़ा लिया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यह लाल है, गुलाबी भी नहीं है, लाल है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- दिख गुलाबी रहा है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, परीक्षण करा लिया जाये कि लाल है कि गुलाबी है । (हंसी) आंख टेस्ट कराना हो, मैं टेस्ट करा दूं या कोई और टेस्ट करा दे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लाल का बॉर्डर है बाकी गुलाबी है ।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- हम लोग अभी टीवी में आपकी फोटो देख रहे थे तो वह गुलाबी दिख रहा था तो लोगों को गुलाबी ही दिख रहा है भले आपने लाल पहना है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता किस विषय की थी इस अव्यावहारिक अनुपूरक की ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) :- नेता जी आप यह बताईए कि जब आप प्रवेश किये गमछा डालकर किसान के वेश में और किसान के बारे में जब आप बोलने के लिये खड़े हुए हो तो आप उसको उतार दिये हो ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप सबको खुश करने का प्रयास कर रहा हूं । आप लोगों की चिंताएं जितनी जागृत होंगी, हर चिंता का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा । आगे एक और कमेंट करियेगा फिर कपड़े नहीं उतारूंगा । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता प्रतिपक्ष जी, हमारी चिंता यह है कि हमारी भाभी जी को लगातार आपके विधायक दल के द्‌वारा प्रताड़ित किया जा रहा है । पहले नेता, उपनेता के पद से हटाया गया फिर बैठकों में नहीं बुलाया गया फिर कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया । यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महिला उत्पीड़न आपके विधायक दल के द्वारा कब बंद होगा आप यह बता दीजिये । आप जैसे शालीन व्यक्ति के रहते यह सब हो रहा है तो यह उचित नहीं लगता ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग विषय में आईये न, इधर-ऊधर क्यों चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- वे विषय में जाना ही नहीं चाहते ।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग दूसरे के घरों में बहुत तांक-झांक करते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज तीजा है इसलिये महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक के संदर्भ में हमारी आपत्ति है । एक इस संदर्भ की भी है कि क्या छत्तीसगढ़ के शासक को इस बात का इल्म नहीं था कि आज तीजा का त्यौहार है, तीजा के त्यौहार की अपने छुट्टी भी नहीं घोषित की जो कि एक शासकीय छुट्टी के रूप में यह घोषित हो जाना चाहिए था। आज भी अगर आप इसकी घोषणा कर दें तो कुछ आपने जो गड़बड़ की है उसकी शायद आगे के लिये पूर्ति हो जाये । भविष्य के लिये छत्तीसगढ़ में तीजा का त्यौहार वह तो घोषणा पत्र में आयेगा और अगली कांग्रेस की सरकार तो तीजा की छुट्टी देगी ही किंतु आप उसकी पूर्ति उसके पूर्व करना चाहो तो अभी भी अपनी गलती को सुधार करने के लिये कि आज तीजा के दिन आपने बुलाया तो चलो हम भूल तो गये थे जैसे हम बहुत सारी चीजें भूल जाते रहे लेकिन चलो आज आपने याद दिलाया तो वही सही । हमको बोनस देना है 2 साल का याद नहीं आया, हमको 2100 प्लस 300-400 रूपये की राशि 2400 रूपये की राशि किसानों को देनी थी याद नहीं आया, दो महीने पहले हमको याद नहीं आया कि हमने जिस बात को कहा था उसका प्रावधान कर दें अनुपूरक में और आज आपने एक और अनावश्यक अनुपूरक के माध्यम से एक बात को जिसको आप प्रस्तुत करने का कह चुके थे, शेष उसके 2400 करोड़ के तीन खर्चे और.............जारी

...............श्री यादव

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

यादव\12-09-2018\g14\04.55-05.00

............(जारी श्री टी.एस.सिंहदेव) :- जिसको आप प्रस्तुत करने का कह चुके थे, शेष उसके 2400 करोड़ के तीन खर्चे और, वह चुनाव के संदर्भ में आपको वह भी याद नहीं आया। 2433.78 करोड़ का अनुपूरक बजट है। क्या ऐसे परम्पराओं को तोड़कर, ऐसे सत्र को इस काम के लिये बुलाया जाना था ? आपको अपनी ही बात का विश्वास नहीं था या आपको इस बात का विश्वास नहीं था कि छत्तीसगढ़ का किसान नहीं मानेगा क्योंकि आप पहले भी बोल चुके हो कि हम इतना इतना बोनस देंगे, इतना इतना समर्थन मूल्य देंगे और नहीं दिया था तो भले ही आपने सदन में कहा था कि 2018 का बोनस भी मिलेगा, लेकिन वह नहीं मानता तो चलो फिर से इन परम्पराओं को तोड़कर बुलाओ, आपत्तियां इस बावत् हैं।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की बात हो रही थी। महिलाओं के प्रति हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनकी संवेदनशील कैबिनेट और संवेदनशील सरकार की सोच किस तरीके से परिलक्षित हो रही है। सी ए जी की रिपोर्ट में जो आज प्रस्तुत हुई है, महिलाओं के संबंध में क्या कहा गया है। आपने विशेष योजनाओं के तहत प्रावधान किया था, विशेष योजनाओं के तहत महिला केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 25 योजनाओं के लिए 1455.87 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया था। महिलाओं की तीज के त्यौहार की छुट्टी आपके ध्यान में रही, उनके त्यौहार की व्यवस्थाएं आपके ध्यान में नहीं रहीं और क्यों रहती ? क्योंकि आपके मन में क्या है, काम करना, कहना और करने में अंतर क्या है ? क्या आपने महिलाओं के लिये उस राशि में से खर्च कितना किया ? प्रावधानित राशि 1455 करोड़ में से आपने केवल 883.38 करोड़ रूपए खर्च किए।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- अध्यक्ष जी, मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर यह है कि चर्चा अनुपूरक पर हो रही है और सी ए जी की रिपोर्ट का उल्लेख किया जा रहा है। सी ए जी की रिपोर्ट, जो अपने यहां पर परम्परा है वह थ्रू पी ए सी में जाती है, पी ए सी के द्वारा उसका परीक्षण होने के पश्चात् सदन में आती है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, रिफरेंस के लिये कह सकते हैं। रिफरेंस के लिए बराबर कह सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- आप स्वयं चेयरमेन हैं तो आप तो उसकी जांच करके, उस पर जो कुछ भी कार्यवाही करके सरकार को निर्देश देने का, सरकार को कठघरे में खड़ा करने का काम उस कमेटी के द्वारा कर सकते हैं । दूसरी बात, महिलाओं की चिंता करने की बात बोल रहे हैं, कल ही मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में चाईल्ड केयर लीव 730 दिन की छुट्टी की घोषणा की है । (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश सरकार में जितनी महिला कर्मचारी हैं, उनके चाईल्ड केयर लीव के लिये 730 दिन की छुट्टी मिलेगी । यह अपने आप में बड़ी बात है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल के बाद यह घोषणा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- शायद यह जानकारी उनकी टेबल तक पहुंच गई होगी कि उन्होंने किस प्रकार का चिंतन किया और उन्होंने किस प्रकार का क्रियांवयन किया । महिलाओं की 25 चिन्हांकित योजनाओं के संदर्भ में तो हो सकता है कि कहीं एक और जुमला चल गया हो।

श्री अमरजीत भगत :- अभी प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी ने जो कहा कि 730 दिन की छुट्टी का एलान किया । 365 दिन तो साल में होते हैं तो कहां से 730 दिन की छुट्टी देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप चाईल्ड केयर समझे नहीं क्या ? बच्चों के लिये है 730 दिन ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बच्चे को बड़ा करते तक ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने फिर नया ठगने वाला कर दिया । (हंसी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\g15\.-.5

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, फिर आपने स्वांग रच लिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। उन्होंने याद दिला दिया। आप बोलिए तो उतार देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुलाबी रंग लगा आप रखोगे ही। भाभीजी बता दीजिएगा कि गुलाबी रंग हो गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- भाभीजी के कहने पर तो आप जोगी कुर्ता पहनकर आ गये।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये कहीं न कहीं दिख जायेंगे। (श्री नवीन मारकंडेय जी देवजी की सीट पर बैठे हैं एवं गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुए हैं एवं उसके ऊपर जैकेट पहने हैं।) वह देखिए देवजी भाई की जगह बैठे हैं क्या रंग है। ढ़ाकने की कोशिश की है लेकिन प्योर गुलाबी है। आपका तो भगवा टाईप गुलाबी है उधर प्योर गुलाबी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, रंगों के चक्कर में न पड़ें, आप आगे बोलिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये अनुपूरक की बात है और वित्त के संदर्भ की बात है तो ये पुस्तक उठाई है तो इसके कुछ पन्नों को जिन्हें चिन्हांकित किया है उन्हें पलट लेता हूं। 2015-16 की जो रिपोर्ट इसमें आई है समेजित राजस्व व्यय ये जीएसडीपी के संदर्भ में घटा था। जो आपका अनुमान था गैर ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रही ये आपकी आर्थिक स्थिति है। राजस्व प्राप्तियां 53685 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में जहां बढ़ीं वहां बजट अनुमान आपने रखा था 61427 उसकी तुलना में आप 53685 करोड़ ही प्राप्त कर सके। राजस्व व्यय बजट अनुमान 56390 करोड़ के विरूद्ध में 48165 करोड़ रूपये आप खर्च कर पाये। आप कैसे छत्तीसगढ़ का पोषण कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, किसके जेब से पैसा निकला और छत्तीसगढ़ का विकास हुआ ये मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे पायेंगे। जब आपके बजट के व्यय की तुलना के आंकड़े इस प्रकार के आ रहे हैं तो किस प्रकार का विकास छत्तीसगढ का हुआ और क्यों विकास की चिड़िया को खोजना पड़ रहा है और जो विकास की चिड़िया दाना चरकर चली गई वह वास्तव में छत्तीसगढ़ के हित का वह दाना था जो इन आंकड़ों से परिलक्षित हो रहा है। पूंजीगत व्यय ये 13004 करोड़ रूपये आपने बजट में अनुमानित किया था और आपने खर्च किया 9471 करोड़। ये कुछ-कुछ बातों को मैं जल्दी-जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से दो हमारे वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग आज उनके पास ये विभाग हैं ये आंकड़े एक साल पहले के हैं आपने जिस तरह से 145 परियोजनाओं को चलाया उसमें अनुमानित लागत जो आपकी इन योजनाओं का था 2623.21 करोड़ से बढ़कर क्योंकि आपकी सरकार ने आपके प्रबंधन की कमी के कारण इसको ठीक ढंग से नहीं चलाया, कैसे छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है ये आंकड़े बतायेंगे। उसकी लागत 5059.03 करोड़ रूपये हो गई। वही योजनाएं, वही योजनाएं, ये कोई नया विकास नहीं हो रहा है। हम लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाकर नई-नई घोषणा करके आते हैं, पता नहीं बजट के बाहर कैसी घोषणा हो सकती है, बजट के प्रावधानों के बाहर कैसे पत्थर लग जाते हैं लेकिन वह जो पत्थर हैं, जो अनुमान लगाया जाता है कि कोई नया काम मंजूर हो गया वह होते हैं पुराने काम और पुराने कामों के लिए आपने जो राशि का प्रावधान रखा था वह खर्च आपके काम करने की और काम कराने की कमी के चलते कहां तक पहुंच जाता है इसको देख लीजिए। आपने पी.डब्ल्यू.डी. और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट लिखे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- इस बार इस सत्र में पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री एकदम चुपचाप बैठे हैं। बहुत निराश और हताश हैं क्या बात है?

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी चिन्ता करो।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, आगे मैंने जिस बात को पहले भी कई बार रखा, ये छत्तीसगढ़ का विकास कैसा हो रहा है, बजट क्या है और वास्तविकता क्या है, ये सी.ए.जी. की रिपोर्ट पुन: हमको याद दिलाती है। वित्तीय वर्ष के अंत तक कुल 19745 करोड़ रूपये अनुदान और विनियोग का जो 24.62 प्रतिशत होता है ये खर्च नहीं हुए। आपने ये अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, क्या ये कागज के टुकड़े हैं? हम हर साल जो बजट प्रस्तुत करते हैं ये केवल अखबारों में छापने के लिए हैं? ये घोषणाएं और इनकी सच्चाई इनके संदर्भ में मैंने ये कुछ जानकारियां आपके समक्ष, सदन के समक्ष रखीं। जो पैसा हम लेते हैं, हम कर्ज जो लेते हैं 75 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य की पूंजी निर्माण, विकास की गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका। ..

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\g16\05.15-05.20

जारी......श्री टी.एस.सिंहदेव :- एवं इसका उपयोग राज्य की पूंजी निर्माण विकास की गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका । अध्यक्ष महोदय, हम लोन ले रहे हैं लोन पटाने के लिए या लोन ले रहे हैं काम करने के लिए ? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए ? जब विकास की चिड़िया की बात होती है तो वास्तविकता में उसके पीछे सच्चाई क्या है, उसकी कुछ सच्चाईयों की झलक इन आंकड़ों के माध्यम से सामने आती है और अन्य राज्यों की तुलना में ऋण की निधि उपयोग नहीं करने में छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से बहुत आगे है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय, करों के संबंध में भी कानून में परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन की बात आज सदन में रखी गई है । बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती अगर भारत बंद के बाद उसके समर्थन करने में भी मन लगता कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, वित्तमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस बात की घोषणा कर देते कि डीजल और पेट्रोल में लगे हुए वैट की दरों से जो अत्यधिक कमाई छत्तीसगढ़ राज्य को हो रही है, उस हद तक अनैतिक रूप से जो राशि हम बिना जनता को बताए, हम लेते चले जा रहे हैं, हमने उसमें कटौती की घोषणा की । आज वह सदन में आता और आज उसकी घोषणा होती । इस सत्र को जो हम कह रहे हैं कि अव्यवहारिक है, चलिए उसमें भाग लेने में अच्छा लगता । क्योंकि ये सारी बातें तो पहले हो चुकी हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें हो क्या रहा है ? जितना डीजल और पेट्रोल को बनाने में खर्च नहीं है, उसकी जो कीमत नहीं है, आज अगर पेट्रोल 84 रूपए में बिक रहा है, तो पेट्रोल को बनाकर पम्प तक पहुंचाने की कीमत शायद 39 रूपए होगी । अर्थात् 45 रूपए, उसकी लागत से ज्यादा राशि टैक्सों के माध्यम से ली जा रही है । तीन प्रकार से इसकी राशि में बढ़ोतरी हो रही है । केन्द्र का एक्साइज़ कर, वह इस सदन की कार्यवाही के दायरे के बाहर है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- नेताजी, 84 रूपया कहां है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपको दिखाते हैं, कई जगह है और मैंने उदाहरण के लिए कहा है। मुम्बई में 88 रूपए भी है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- छत्तीसगढ़ में तो अभी 79, 80 चल रहा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अंबिकापुर में 82, 83 रूपए है आप टैक्स घटा दोगे तो उसके पेट्रोल की कीमत भी कम आएगी ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- नेता जी एक बात और है, आप लोग बार-बार विकास की चिड़िया, विकास की चिड़िया कहते हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- भूपेश भाई की अनुपस्थिति में उनकी बात को रख रहा था ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- आप लोग विकास की चिड़िया बार-बार ढूंढ रहे हो । जहां तक मैं समझता हूं विकास तो मेस्कुलिन जेंडर है, यह तो पुल्लिंग है तो उसमें चिड़िया कहां से आ गई ? चिड़िया तो स्त्रिलिंग है ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- चिड़िया में दोनों लिंग नहीं है क्या ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- नहीं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपकी चिड़िया में होगा, हमारी चिड़िया में दोनों लिंग है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- उसके साथ और कुछ लगा लो, चल जाएगा ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- चिड़ा कह लो, चिड़िया कह लो सब चल जाएगा ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय :- विकास पुल्लिंग है उसमें स्त्रिलिंग क्यों ढूंढ रहे हो ? इसीलिए आप लोगों को विकास मिल नहीं मिल रहा है । ढंढ रहे हो चिड़िया और चिड़िया तो है नहीं । विकास पुल्लिंग है तो मिलेगा कहां से ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगली उनकी जो विकास यात्रा निकलेगी वह बिलासपुर से कटघोरा होते हुए अंबिकापुर जाए और चिरमिरी न जाएं, चोटेया मोड़ से डाढगांव होते हुए अंबिकापुर जाएंगे और अंबिकापुर से फिर जशपुर जाएंगे, अंबिकापुर के रिंग रोड का एक पूरा चक्कर लगाकर तो उन्हें जरूर विकास की स्थिति दिख जाएगी । हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उतनी नहीं दिख पाती है । लेकिन वहां जाएंगे तो जरूर सही स्थिति दिख जाएगी कि विकास की वास्तविक स्थिति क्या है, खैर । अध्यक्ष महोदय, बात डीजल पेट्रोल पर वैट में कमी की आ रही थी । आपके पास कमी की पूरी गुंजाईश थी लेकिन आपने एक तरह का लोभ किया कि पैसा ले लो, पैसा ले लो । जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, कच्चे तेल के दाम को छोड़िये, शिवरतन जी ने उदाहरण दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने एक ग्राफिक निकाला है, वाट्सअप इत्यादि में वह वायरल भी हुआ है कि इतने प्रतिशत पहले बढ़े थे, इतने प्रतिशत घट गए । उस बाबत् उनकी आलोचना भी हुई, किस बात को लेकर । जब उन्होंने कहा कि उस समय 80 रूपए का भाव था और अभी 88 हो भी गया तो हमारी बढ़ोतरी तो केवल 7-8 रूपए की हुई । ....

-- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\12-09-2018\g17\5.10-15

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जारी...श्री टी. एस. सिंहदेव :- 7-8 रूपये की हुई । हालांकि केवल टैक्स में 12 बार बढ़ोत्तरी करके आपके एनडीए की सरकार ने 9 रूपये ज्यादा पेट्रोल में और 15 रूपये से ज्यादा डीजल में केवल एक्साईज़ से नागरिकों से पैसे ले लिए । 12 बार बढ़ोत्तरी करके, शायद एक बार कटौती हुई हो, 12 बार बढ़ोत्तरी करके । उस समय कच्चे तेल का दाम 107 डालर था और आज 73 डालर प्रति बैरल है तो उस 88 रूपये का अगर आप आंकलन कर लोगे, घटा दो, उसको 107 से भाग दे दो और 73 से गुणा कर दो तो क्या रेट आएगा, उस समय का रेट आज के रेट की तुलना में 54 या 55 रूपए आएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने मेरा जिक्र किया । कांग्रेस का आन्दोलन है, वह महंगाई के खिलाफ है । इनका तर्क ये था कि डीजल और पेट्रोल महंगा होने से महंगाई बढ़ी है और मैंने आंकड़े दिए हैं कि डीजल और पेट्रोल से किसी भी खाद्य पदार्थ की कोई महंगाई नहीं बढ़ी है । आज खाद्य पदार्थों की महंगाई कम हुई है और मैंने दाल, गेहूं, आटा, शक्कर, सब पर आपके रेट की तुलना की है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि साथी एक बार स्टडी कर लें । होलसेल प्राईज़ इंडेक्स 5 प्रतिशत पर है, जो उस समय की तुलना में बढ़ा हुआ है, आप पता कर लीजिए । रिटेल प्राईज़ इंडेक्स में कहीं फर्क हो सकता है, कमीबेशी हो सकती है, बढ़ता-चढ़ता रहता है, होलसेल प्राईस इंडैक्स क्या है, उस समय क्या था, आज क्या है, आप पता कर लीजिए । मैं सदन में कह रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन शर्मा जी कौन सी किताब पढ़ लेते हैं और यहां बोल देते हैं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- जो किताब दी जाती है, वही पढ़ते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज दाल 55 और 60 रूपये किलो में खुले बाजार में बिक रही है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है । आप बाजार जाकर देख लो, आज शक्कर 35 रूपये किलो में बिक रही है, जाकर खुले मार्केट से खरीद लो । इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- आप पड़ोसी देश में जाकर देख लो, भूटान और नेपाल आपसे सस्ता तेल दे रहा है । क्यों आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो ? बताओ । कहां-कहां की किताब पढ़कर आते हो ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के पास पूरा अवसर है...

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट । अमरजीत जी, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो परम्परा बार-बार खड़े होने की नहीं है । मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे बार-बार खड़े नहीं हों ।

आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाती है, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यही बात सभापति जी को बताइए ।

श्री अमरजीत भगत :- वे बार-बार खड़े होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप गिनती करिए, इधर जितने लोग खड़े हो रहे हैं, उससे ज्यादा इधर खड़े हो रहे हैं । (हंसी)

श्री टी. एस. सिंहदेव :- इधर खास अवसर पर खड़े होते हैं । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरे 45 मिनट में भाषण में नेता प्रतिपक्ष जी का 21 बार खड़े होने का रिकार्ड है, आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महंगाई की जो बात आती है, मुझे शायद अर्थव्यवस्था का उतना ज्ञान नहीं भी है और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी है, अगर आप डीजल के ऊपर 16 रूपये एक्साईज़ ड्यूटी लगाकर डीजल का भाव बढ़ाते हो और डीजल से समान का आदान-प्रदान होता है तो दाम अगर घटेंगे तो वाह-वाह । ऐसी अर्थव्यवस्था की तो फिर देश और दुनिया में मिसाल ही नहीं है कि आपका परिवहन का जो आधार है डीजल, पेट्रोल को हम मान लेते हैं कि निजी उपयोग की एक वस्तु हो सकती है, लेकिन डीजल किसान से लेकर, उसके पम्प से लेकर और ट्रकों के संचालन से लेकर और ट्रेनों के संचालन से लेकर

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिसमें उस वस्तु का उपयोग होता है, अगर पेट्रोल पर एनडीए की सरकार ने टैक्स में 9 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है तो डीजल पर 16 रूपये की बढ़ोत्तरी की है और ये आपके पास अवसर था । क्योंकि जब आप वैट लगाते हो तो उस राशि के ऊपर लगाते हो, डीलर कमीशन जोड़कर आप शायद वैट लगाते हो तो जब आपको बढ़े हुए दरों पर वैल्यू एडेड टैक्स लगाने का मौका मिलता है तो राशि आपको बराबर फिर भी मिलेगी । आपके बजट के अनुमान के मुताबिक आपको राशि फिर भी मिलेगी, अगर आप वैट के दर को कम करते हो, अध्यक्ष महोदय, ये आप सबसे अच्छा समझेंगे और लोग भी कुछ लोग समझना चाहेंगे तो जरूर समझ जाएंगे, ये बहुत सरल गणित है कि जब रकम जिस पर आपको टैक्स लगाना है और लगातार अनैतिक तरीके से बढ़ रहा है तो आप कम से कम अनैतिक लाभ उसका लेने में चिंतन करें और वैट पर आप कटौती करके घोषणा करें, ताकि लाभ मिले और मुझे साथ में ये भी उम्मीद थी कि बहुत साल से बहुत सारे संगठन, शासकीय संगठन, बजट में एक बात हुई, भूपेश जी ने उस बात का उल्लेख किया कि बजट में आपने प्रावधान किया....

श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\g18\05.15-05.20

जारी.. श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, एक बात हुई, बजट में ही, भूपेश जी ने ही उस बात का उल्लेख किया कि बजट में आपने प्रावधान किया अनुपूरक में 12 सौ करोड़ रुपये कृषि मद से और एस.टी. उपयोजना से आपने 912 करोड़ का और एस.सी. उपयोजना से आपने 288 करोड़ का प्रावधान किया । ये उपयोजना में यह राशि क्यों दी जाती है? क्या कारण है कि चिन्हांकित कर के आप एस.टी. और एस.सी. उपयोजनाओं के लिए राशि देते हैं? क्या उसका कारण यह नहीं है कि इस क्षेत्र में रहने वाले और इस समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति और रिहायसी स्थिति में सुधार करने के लिए हमको सामान्य बजट से जो राशि देनी है, उससे अतिरिक्त राशि देने की आवश्यकता है इसलिए हमको यह अतिरिक्त राशि देनी है। लेकिन यहां क्या होता चला आ रहा है? और यह कांग्रेस की अगली सरकार जरूर इसको नियंत्रित और परिवर्तित करेगी क्योंकि प्रतिशत भी अगर आप देखिये, अभी आपने क्या किया, 12 सौ करोड़ रुपया कृषि मद में और 12 सौ करोड़ रुपया एस.टी.,एस.सी. मद में, आबादी कितनी है ? 43 प्रतिशत आबादी पर आपने 50 प्रतिशत पैसा बोनस का उनके विकास की राशि से कटौती कर के

अप्राधिकृत प्रकाशन के लिये नहीं

इसमें आपने डायवर्ट कर लिया। वह उनके विकास के राशि का होना चाहिए था। वह उनके विशेष प्रयोजन के उपयोग के लिए होना चाहिए था। अगर वह भी किसान है और वह भी किसान है तो यह स्टेट के बजट से सब किसान एक जैसे, बिना जात-पात के, भेदभाव के, बिना वर्ग भेद के भेदभाव के स्टेट के बजट से किसानों को बोनस की राशि की व्यवस्था होनी चाहिए थी और जो व्यवस्था हुई भी है, वह प्रतिशत आबादी की प्रतिशतता के अनुपात के भी विपरीत हुई है और यही कारण है कि जब तक सरकारें बराबर की राशियां प्रतिशत के हिसाब से इतना परसेंट उनको दिया, इतना परसेंट उनको दिया, आप स्थिति का जो अंतर है, उसको कभी पूरा नहीं कर सकते और अध्यक्ष महोदय, तब ऐसी स्थितियां आती हैं कि ऐसे मैग्जिन में 52 पन्नों का उल्लेख आता है कि छत्तीसगढ में आदिवासियों की स्थिति क्या है। 52 पन्नों में पत्थलगढ़ी से लेकर बाकी सारी बातों का विश्लेषण होता है, बजट के प्रावधान की आपत्ति इस पत्रिका के 52 पन्नों की बातों से मेल खाती है और ये हमारी आपत्ति का एक और कारण है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं जिस बात को कह रहा था, बजट में अनुपूरक के रूप में भी अभी शराब दुकानों की बात आ रही थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था बन गयी। आपने अपने यहां के जिन बच्चों को रखा है, उनके साथ हो क्या रहा है? आप कह रहे हैं कि हमने उनको काम दे दिया, उनको जेल हो रहा है। वह कहीं बोतल ट्रांसपोर्टेशन में टूटी या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनके पैसों की कटौती के साथ उनको जेल हो रहा है। यह बंट रहा है सरकार की दुकानों से शराब और उसकी व्यवस्था के पीछे जो सच्चाई है वह यह है।

आबकारी मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- नेता जी, एकाध उदाहरण दे दो कि जिसको जेल हुई है, वह गलत तरीके से हुई है। कानून सम्मत जो नियम है, उसके तहत कार्रवाई हुई है। जो बोतल ट्रांसपोर्ट में टूट गई है, उसके लिए जेल नहीं हुई है। जो गलत काम किया है, उसके लिए जेल हुई है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जितना शार्टेज आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो शार्टेज आयेगा, वह जस्टीफाई कहां से करेंगे। वह शार्टेज का कारण कुछ भी हो, मार कौन खा रहा है? वह सात से नौ हजार रुपये...।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय नेता जी, आप अलग से आयेंगे, मैं पूरा समझा दूंगा। शार्टेज वाला कोई विषय नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊं, आकर और समझ लूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- जो भी बात करना चाहते हैं, उनको आप अलग से बुलाते हैं, क्या बात है ? (हँसी)

श्री अमर अग्रवाल :- अगर उसके लिए यहां बहस का समय निर्धारित होगा तो यहीं समझा दूंगा। मैं तो सदन का समय बचाने के लिए बोल रहा हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, चाहे रायपुर के लड़के रहे हों, चाहे अंबिकापुर के लड़के रहे हों, सैकड़ों की संख्या में वे लोग आये हैं और उन लोगों ने कहा है कि बाबा हमको बचाइये। हम लोगों को न तो हमारा पांच-छह महीने का वेतन मिल रहा है और यह सीआरपीसी के तहत नोटिस आ गयी है, जेल का मेरा आशय बंद हुए या नहीं, लेकिन नोटिस आकर पड़ी हुई है। मैं आपको भेज दूंगा। माननीय अमर जी को यदि जानकारी नहीं होगी तो मैं उनको भेज दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वे बहुत अंदर की जानकारी रखने वाले हैं तो उनको जानकारी न हो, यह नहीं हो सकता।

श्री अमर अग्रवाल :- आप वह अडानी वाली बात को भूल नहीं पा रहे हैं। वह जानकारी मेरी नहीं है।....

जारी श्रीमती सविता

सविता\12-09-2018\g19\05.20-05.25

श्री अमर अग्रवाल :- वह अडानी वाली बात को आप भूल नहीं पा रहे हो, वह मेरी जानकारी नहीं है माननीय ने किस-किस से लिखवाया था, उसकी जानकारी है। मैं उस बात को थोड़ी बोल रहा हूँ, वह तो माननीय ने किसी से आपकी शिकायत करायी थी, मैं थोड़ी करवाया था।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक में छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतन भोगी, पंचायत सहायक, किसान मित्र, शासकीय औपचारिक विद्यामितान, छत्तीसगढ़ राज्य बाल श्रमिक, छत्तीसगढ़ रसोईयां संघ, छत्तीसगढ़ मितानिन, नर्स संघ, आंगनबाड़ी सहायिका, लोक स्वास्थ्य, शासकीय अधिकारी असंगठित श्रमिक, अंशकालीन सफाई कर्मचारी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, फेहरिस्त लम्बी है तेन्दू पत्ता संघ की तरफ से समर्थन, परिवहन संघ, सहायक छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ, पटवारी संघ, यहां आपको ध्यान देना है जो आपको डिलिवरी कर रहा है या आपके प्रोजेक्ट्स की राशियां क्यों बढ़ रही है, ये आप टाईम पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो ? ये आप स्वास्थ्य के सेक्टर की ऑउट सोर्सिंग करने पर क्यों मजबूर हो गए हो, स्थितियां क्या हैं ? स्थितियां ये हैं अभी तो बहुत लम्बी लाईन है छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ, रोजगार सहायक संघ, कोई कह देगा कि मेरा नाम नहीं लिया। कोटवार संघ, शिक्षक संघ, प्रदेश मछुआरा संघ, प्रगतिशील किसान संघ, पुलिस परिवार, सरकारी कर्मचारी संघ, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय, यांत्रिकी संघ, शिक्षक पंचायत, नगरीय निकाय ये सब की राशियां और लोग क्या टिप्प्णी कर रहे हैं कि ये हमारे लिए पैसा नहीं है वो मोबाईवा के लिए पैसा है जो गरम हो रहा है और कहीं-कहीं फूट रहा है, टिफिन के लिए पैसा है हमारे लिए पैसा नहीं है आप जो उस दिशा में कर रहे हो, बहुत सोच समझकर और ठीक ही कर रहे होगे। आज का ये सत्र बुलाया तो आपने हम लोगों को बैलगाड़ी और सायकल का भी अनुभव करने का मौका दिया और शायद ये ट्रेन्डिंग भी हो गया होगा, नेशनल ट्रेडिंग भी हो गया होगा तो जो आप कर रहे हैं, उससे हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं हम लोग उन्हीं बातों को लेकर बार-बार सामने बातों को रखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र इसमें कोई बात होती है कि वहां के लिए हम ये कर रहे हैं हमने हर ब्लॉक में ट्रायबल हॉस्टल खोल दिया, हर जगह हमने ये कॉलेज खोल दिया, हर जिले में हमने कृषि विद्‌यालय खोल दिया, ये बातें होती और आप कहते नहीं कि चुनाव के पहले नंबर कमाने के लिए हम ये कर रहे हैं चलिए आप अनुपूरक में हिस्सा लीजिए तो बात आती, कोई नई बात नहीं। एक नई बात नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार सी.ए.जी. कहती है, मैंने एक साल की रिपोर्ट पढ़ी, मैं कई बार सदन में तीन सालों की रिपोर्टों का उल्लेख कर चुका हूँ, बार-बार सी.ए.जी. का ये कहना है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ कि यदि उनने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना चाहिए कि बजट बनाने के पहले ये सावधानियां बरतनी चाहिए यानी 15 साल का अनुभव हमारे काम नहीं आ रहा है और हम उस अनुपूरक के लिए बार-बार बुलाये जाते हैं और सौभाग्य बनाये जाते हैं जिसके लिए सी.ए.जी. कहती है कि कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बजट के प्रावधानों को जब आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो ये और अनुपूरक लाद कर, और क्या कर रहे हैं ? ये अनुपूरक पास कराकर, आप किस हद तक छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नागरिकों को गुमराह करना चाह रहे हो और ये कारण है कि आदिवासी समाज उद्वेलित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समाज में बेहद नाखुशी, किसानों में नाखुशी, महिलाओं में नाखुशी, बच्चों में नाखुशी, उनकी सुरक्षा बच्चों से लेकर महिलाओं के संदर्भ में नाखुशी, अधिकारिक संघों में नाखुशी, मैं कितने गिनाऊं, मैं जहां जा रहा हूँ हर जगह वह बात आ रही है। मीडिया के साथी कहते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा के अलग कानून बनाईये, वकील, डाक्टर्स कहते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा के नये कानून बनाईये, इतना असुरक्षित छत्तीसगढ़ हो गया है कुछ भाई कह रहे थे भय और भ्रष्टाचार, पता नहीं, भय और डर क्या कह रहे थे, 15 सालों के शासनकाल की ये आज की स्थिति है कि आपका जो टॉप वर्ग है, संविधान का चौथा स्तम्भ माने जाने वाला मीडिया, डाक्टर्स कहते हैं कि हमको सुरक्षा दीजिए। टॉप इंटेलेक्चुअल्स जो डॉक्टर बनते हैं हमको सुरक्षा दीजिए, वकील जो पूरे समाज की व्यवस्था का संचालन करते हैं वे कहते हैं कि हमको सुरक्षा के लिए कानून चाहिए, ये छत्तीसगढ़ है और इस अनुपूरक के माध्यम से जो अनावश्यक समय जाया किया गया, जो प्रावधान किसानों के हित में और ज्यादा पिछले अनुपूरक में किये जा सकते थे, उसके लिए ये अनुपूरक बुलाकर सारी परम्पराओं को किनारे कर, एक नया आपने रास्ता इस नाते की हम चाहते तो हम बुला सकते हैं, आप तो जो चाहो कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कल के दिन गोली मार देंगे, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी कर सकते हैं ....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\12-09-2018\h10\05.25-05.30

पूर्व जारी... श्री टी.एस.सिंहदेव :- ऐसा थोडी है कि कुछ भी कर सकते हैं, कोई तो व्यवस्थायें होंगी। कुछ-न-कुछ तो आप करोगे, सब चीज को मानकर चलोगे, लेकर चलोगे। मैं झीरम घाटी से गोली की याद दिला रहा हूं।

कृषि मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- नेता जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप क्यों डर रहे हैं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं नहीं डरता। मैं डरता होता तो यहां नहीं होता, बिले में घुसा रहता। झीरम घाटी के बाद यहां खड़े हैं और मैंने झीरम घाटी की याद दिला दी कि वह झीरम घाटी की गोली की बात थी, चुनाव के पहले का समय है। जो भी हम चाहें कर लें, निकल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जायेंगे। ऐसा प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए और हमारा विरोध इस बाबत् है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय नेता जी, आपने कहा कि पत्रकार सुरक्षा मांग रहे हैं, आपकी जब सरकार थी तो पत्रकारों को सुरक्षा कैसे दी जाती थी, उसका उदाहरण बताता हूं। श्री राजनारायण मिश्रा एक वरिष्ठ पत्रकार थे और उनको लाक-अप में डाल दिया गया और जब मामला विधानसभा में उठा तो गृह मंत्री का जवाब था कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने उत्तेजित थे, उनके साथ कोई घटना घटित न हो जाये इसलिए उनको लाक-अप में रखा गया। ये विधानसभा में जवाब दिया गया था। (शेम-शेम की आवाज) यह सुरक्षा आपकी सरकार पत्रकारों को देती थी। ये ऑन-रिकार्ड विधानसभा में है, गृहमंत्री का जवाब है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आप लोगों के पास पीछे जाने के अलावा कुछ नहीं है, आज की बात नहीं करते हैं, वह ये जो 15 साल बीते उसके पहले की बात कर रहे हैं। अब तो 70 साल भुला गया, अब वह 70 साल भी 50 साल में समा गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोग तो आपकी सरकार के कारनामे याद दिलाते हैं। आपकी सरकारों ने क्या किया, वह याद दिलाना पड़ता है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- क्या याद दिलायें ? आपको याद दिलायें कि इस सरकार ने क्या किया और कांग्रेस की सरकार ने 50 साल क्या किया, आधा घंटा दीजिये, और गिना देता हूं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आज की घटना देखिये। घटना आज घटित हुई है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार रूपेश गुप्ता को पुलिस वालों ने उठा करके फेंक दिया।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक में हिस्सा लेने वाले सभी सम्माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा। श्री मोहन मरकाम जी, शिवरतन शर्मा जी, संतराम नेताम जी, अवधेश सिंह चंदेल जी, कवासी लखमा जी, देवजी भाई पटेल जी, अमरजीत भगत जी, राजमहंत सांवलाराम डाहरे जी, बृहस्पत सिंह जी, केशव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चन्द्रा जी, दीपक बैज जी, डॉ. विमल चोपड़ा जी, भूपेश बघेल जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, डॉ. खिलावन साहू जी, डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी और नेता प्रतिपक्ष टी.एस.सिंहदेव साहब ने अपने विचार रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको और विधानसभा की पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने ये विशेष सत्र आहूत करने के लिए हम सबको अवसर दिया, आपको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट) पूरे छत्तीसगढ़ के किसान, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आपकी इस पहल को देख रही है। क्या विधानसभा सिर्फ एक वजह से, एक कारण से, किसानों के हित में लिये गये एक निर्णय की वजह से दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? यानि हमारी प्राथमिकता क्रम में पहले नंबर पर किसान है, इस विधानसभा की गरिमा और ऊंचाई बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। आम आदमी जो विधानसभा को जानता नहीं, मगर उसको ये बात तो समझ में आ गई है कि 2400 करोड़ का बोनस मिलना है, इसी दरवाजे से मिलना है, इसी से रास्ता खुलता है। अध्यक्ष महोदय, ये अपने आप में आप एक ऐतिहासिक अवसर है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। ये अवसर भी तीज-त्यौहार का निश्चित रूप है, घर में बहुत खर्चा होता है। पोला, तीजा, गणेश चतुर्थी हमारे लोक पर्व हैं जिसमें जाति, धर्म की सीमा को तोड़कर सब इस उत्सव में भाग लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हरितालिका है। हमारी बहनें, मातायें कठिन और निर्जला उपवास करती हैं। प्राचीन कथा भी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए 12 वर्ष का निराहार तप किया था, इसलिए आज का दिन असंभव को संभव करने का दिन कहा जाता है। जो असंभव था उसको संभव करने का दिन है। ये किसी को कल्पना नहीं थी कि ये हो सकता है। क्योंकि सत्र हो गये, दो महीने निकल गये, आपने विदाई दे दिया, हम सब भावुक हो गये, कई लोगों के आंसू निकल गये, अध्यक्ष महोदय, आज फिर आंसू निकल रहे हैं, कराह निकल रही है। अंदर की पीड़ा और व्यथा ऐसा फूट रहा है जैसे मोबाईल के लिए बोलते हैं कि दीवाली में फूटता है। अध्यक्ष महोदय, ये दर्द झलकता है। आह और वाह के बीच में जो फर्क होता है... (जारी)...

श्री अरविन्द

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अरविंद\12-09-2018\h11\05.30-05.35

............जारी डॉ0 रमन सिंह :- आह और वाह के बीच में जो फर्क होता है, आज वह दिख रहा है कि सत्र बला कहां से आ गया ? यह हरतालिका में यही संभव है। विधानसभा के समापन की औपचारिकता पूरी होने के बाद जब सब विधान सभा चुनाव की तैयारी में जुट गए थे, इस वातावरण में सत्र का आयोजन निश्चित रूप से जनहित और विशेष परिस्थिति , ये दो विषय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें विशेष सत्र आयोजन करने की बात है। इस विधान सभा में एक बार नहीं, कई बार ये मौके आये। हम सबको याद है जो इस विधान सभा के सदस्य है कि कैसे पहली बार नक्सल पर चर्चा करने के लिए, दूसरी बार जी0एस0टी0 के समर्थन के लिए, तीसरी बार इसी विधान सभा में 22 सितम्बर को सूखा राहत और धान के बोनस क विषयों पर चर्चा हुई है, विशेष सत्र का आयोजन हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्र तकनीकी तौर पर जब नये निर्वाचित सदस्य जब शपथ लेते हैं, तब यह चौथे विधानसभा का अवसान होगा। इस बीच आपका विशेषाधिकार और पांचवी विधान सभा के गठन के पहले किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात, जो परिपाटी नई बनती है, नई परम्परा बनती है। उच्चतम न्यायालय का भी उदाहरण है कि रात को 12 बजे दरवाजा खोलकर सुनवाई का काम किया था। यह उच्चतम परम्परा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया, जब ऐसे त्वरित क्रियान्वयन के लिए, नई सोच आगे बढ़ती है। तो यह विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और आपने बुलाया, उसके लिए पूरे सदन की ओर से मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको इस मानसिकता से उठना पड़ेगा कि कोई आपातकाल में, इमरजेंसी में ही सत्र बुलाया जा सकता है। लोकहत में इस मानसिकता में बदलाव जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज इस द्वितीय अनुपूरक 2,434 करोड़ रूपये, जिसमें वर्ष 2018-2019 के मुख्य बजट का कुल प्रावधान 87,463 करोड़ रूपये, प्रथम और द्वितीय अनुपूरक को मिलाकर के 94,775 करोड़ रूपये का बजट का आकार बढ़ा है। द्वितीय अनुपूरक का कुल व्यय 2,434 करोड़ रूपये, जिसमें धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना हेतु 2,400 करोड़ रूपये, आगामी विधानसभा चुनाव 2018 हेतु 33 करोड़ 78 लाख रूपये, राजस्व व्यय कुल 2,434 करोड़ रूपये है। अध्यक्ष महोदय, अब यह प्रश्न उठ रहा था कि हमने कर्ज लेकर सरकार को बोझ में डाल दिया। सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की वित्तीय स्थिति बिलकुल बिखर गई है और सरकार कर्ज ले-लेकर सब काम कर रही है। चूंकि भाषण में लंबा-चौड़ा, बहुत सी बात आई, मैं उसका जवाब उसी से शुरू करता हूँ। जब 2003-04 में हमको सरकार में मौका मिला तब राजस्व घाटा 441 करोड़ रूपये का था। आज वर्ष 2017-18 में महालेखाकार के आकड़े के अनुसार 3,417 करोड़ रूपये का राजस्व आधिक्य आज की तारीख में है। (मेजों की थपथपाहट) कहां 441 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा और वर्ष 2017-18 के महालेखाकार ने कहा कि 3,417 करोड़ रूपये का राजस्व आधिक्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आर0बी0आई0 क्या कहता है कि हमारी वित्तीय प्रबंधन के लिए। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में 13 वर्ष राजस्व आधिक्य रहा है। राजा साहब चिंता कर रहे थे। हम इस राजस्व आधिक्य की बात कर रहे हैं। 2017-18 के कुछ आकड़ें हैं और कुछ जानकारियां हैं, जो इस आधार पर है कि हमने कैसे वित्तीय प्रबंधन किए हैं। वर्ष 2017-18 में देश का टैक्स और जी0डी0पी0 का अनुपात 12 प्रतिशत था जबकि छत्तीसगढ़ का टैक्स और जी0एस0डी0पी0 का अनुपात 19 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक ने 18 के प्रतिवेदन में राज्य का कुल ऋण भार, अब मैं ऋण पर आ रहा हूँ, जिसके बारे में सभी सदस्यों ने कुछ न कुछ बोला। वर्ष 2018 के प्रतिवेदन के अनुसार, आर0बी0आई0 के अनुसार कुल ऋण भार सकल घरेलू उत्पाद का 17.4 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का 17.4 प्रतिशत है और अन्य राज्यों का एवरेज 24.3 प्रतिशत है। पूरे देश में न्यूनतम ऋण भार वाले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक कह रहा है 2018 के आकड़े के आधार पर कह रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़े ....जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\h12\05.35-05.40

जारी...डॉ.रमन सिंह :- एक साथ आप बोल देना, तीनों आप सुन लीजिए । ब्याज भुगतान राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का मात्रा 1.1 प्रतिशत सभी राज्यों का, देश के राज्यों का एवरेज मिला दिया जाये, 1.7 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में न्यूनतम ऋण ब्याज भुगतान में देश में पहले नंबर पर है । न्यूनतम है । अध्यक्ष महोदय, तीसरा कुल बजट के विकास कार्यो के व्यय में हम देश में पहले नंबर पर हैं । सामाजिक क्षेत्र के व्यय में हम पहले स्थान पर हैं, कुल बजट में से कमिटेड व्यय न्यूनतम होने पर प्रथम हैं, ऋण दायित्व और ब्याज भुगतान में तीन वर्षों से हम न्यूनतम स्थान पर हैं । अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े बताते हैं, छत्तीसगढ़ में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विकासमूलक कार्य, सामाजिक क्षेत्र में काम, दोनों काम में देश में सबसे बेहतर काम करने के बाद जो 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये । 14 वें फायनेंस कमीशन कहता है कि ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । राज्य का लोक ऋण जी.एस.डी.पी. के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, दो कंडीशन है, एक तो ब्याज भुगतान, कुल राजस्व प्राप्ति का 10 प्रतिशत, राज्य का लोक ऋण, जी.एस.डी.पी. के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । छत्तीसगढ़ इन दोनों वित्तीय माप में अधिकतम निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारा ब्याज भुगतान पांच प्रतिशत है और जी.एस.डी.पी. के कुल राजस्व प्राप्ति का 18 प्रतिशत है, इसलिए राज्य को विशेष छूट मिली है । हम बेहतर वित्तीय प्रबंधन की वजह से 1500 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक ऋण लेने की पात्रता छत्तीसगढ़ को है । स्पेशल कैटैगरी स्टेट में 1500 करोड़ के कर्ज लेने की पात्रता इसलिए है, ब्याज का भुगतान और लोक ऋण में अनुशासन बनाकर रखा है । डिसीप्लीन को मेंटेन किया है, इसके लिए विशेष छूट मिली है । अध्यक्ष महोदय, जब हमने राज्य के संसाधन का आकलन किया, आकलन करने के बाद लगा कि हमारी क्षमता है, अतिरिक्त ऋण लेने की क्षमता या अनुमति हमको मिली हुई है, उस आधार पर अध्यक्ष महोदय, हमने किसानों के बोनस का भुगतान और समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने साहस किया है, धान खरीदी के साथ बोनस एक साथ दे दिया जाये । यह निर्णय भी हमने इसीलिए लिया है । वित्तीय प्रबंधन बेहतर होने की वजह से । अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी और बोनस मुझे लगता है कि इस निर्णय का कम से कम पक्ष विपक्ष को भूलकर विपक्ष वाले इस बात के लिए, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, 12 लाख, 13 लाख किसानों का है । अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इसमें खुलकर सब तरह से रहेगा कि यह सर्वसम्मति से इसमें निर्णय लिया गया है । हम इसका समर्थन करते हैं । इसमें भी राजनीति है । इसमें भी किन्तु परन्तु लगाने का है । एक तरफ तो बोनस देना होगा, देना होगा, नारे लगाते हैं, बोनस जल्दी दे दिया तो चेहरा में मुस्कान भी नहीं आ रहा है । दुखी हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के हित का इतना बड़ा निर्णय और इसमें असहमति तथा हाथ खींच लेने वाली बात ही नहीं है । समर्थन मूल्य का जो हिसाब-किताब है, यह प्रक्रिया शुरू हो गयी है । हम 1 नवम्बर से धान खरीदी शुरू कर रहे हैं । जिस दिन से धान खरीदी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन से धान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खरीदी के साथ 300 रूपये का बोनस साथ जुड़ जायेगा । अब धान की कीमत 1550 या 1570, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि 200 रूपया समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1750 कर दिया । 1750 की देश में पहली बार इतनी बडी वृद्धि हुई है, उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 1700 के उस सिलिंग में ले आया है । 1750 में फिर 300 मिला दें तो 2050 और 2070 रूपये के डायरेक्ट उसके खाते में सारे पैसे जायेंगे । कहीं बीच की दिक्कत ही नहीं है । यह वृद्धि, भुगतान का फैसला, सीधे उनके खाते में जाने का काम करेंगे । दो प्रकार के धान है, कामन ग्रेड का और ए ग्रेड का धान । 1750 और 1770 रूपये के हिसाब से इस खरीदी की व्यवस्था होगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी-बड़ी बात हो रही थी, कांग्रेस के शासनकाल के तीन साल के आंकड़े यदि देख लें, उसका एवरेज निकाल लें, मैं उस आंकड़े को एवरेज में बोलता हूँ, हमने कांग्रेस से चार गुना अधिक धान खरीदा और ....

जारी...श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\h13\05.40-05.45

जारी............डॉ. रमन सिंह :- और उसका एवरेज निकाल लें । मैं उस आंकड़े को एवरेज में बोलता हूं । हमने कांग्रेस से 4 गुना अधिक धान खरीदा और 9 गुना अधिक भुगतान किया । मैं इसके आंकड़े बताना चाहूंगा कि कैसे हमने धान भुगतान पर और इनसे ज्यादा धान खरीदी की उसका हिसाब मैं देना चाहता हूं । 15 साल का हिसाब यदि हम देखेंगे तो कांग्रेस ने औसतन 15 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में 3 साल में मात्र 39.61 लाख धान समर्थन मूल्य में खरीदा, 3 साल का इनको अवसर मिला । आज यह 15 क्विंटल-15 क्विंटल चिल्लाते हैं, 5 क्विंटल धान खरीदी होती थी और क्या हालत खराब किये थे किसानों की केवल और केवल 39.61 लाख धान समर्थन मूल्य में खरीदा था । किसानों को 2159 करोड़ का भुगतान हुआ था । हमारी सरकार ने 15 साल में 7 करोड़ 53 लाख धान खरीदी की, 95 हजार 136 करोड़ का भुगतान किया है जिसमें 9715 करोड़ का बोनस औसत निकालें तो कांग्रेस ने औसतन एक साल में 13 लाख 20 हजार 33 मीट्रिक टन धान खरीदी की और हमने ये 15 साल की अवधि की बात बता रहा हूं । इन्होंने 13 लाख खरीदा और हमने हर साल 50 लाख 20,000 मीट्रिक टन धान खरीदा । (मेजों की थपथपाहट) ये किसानों के दर्द और पीड़ा की बात करते हैं । हम 13 लाख-14 लाख धान खरीद नहीं पाये, हमने एवरेज 15 सालों में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की, सीधा गणित है लगभग 4 गुना ज्यादा हमने खरीदी की है और औसतन प्रतिवर्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमने जो भुगतान किया है, टोटल यदि राशि करें तो 9 गुना ज्यादा भुगतान हुआ है । औसतन प्रतिवर्ष 720 करोड़ का भुगतान और हमने 6343 करोड़ का भुगतान किया है । गांव-गरीब और किसान यह हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को आगे बढ़ाकर हमने काम किया । नीयत और नीति साफ हो तो कहीं पैसे की कमी की जरूरत नहीं पड़ती। हमने स्पष्ट नीति भी बनायी और सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करने का काम किया, स्पष्ट नीति में हमने किसानों को पंजीयन कराया, पंजीयन कराने के बाद ऑनलाईन बैंक में भुगतान की प्रक्रिया की और सीधे उनके खाते में पैसे डालने का काम किया । हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास इतना शानदार प्रोक्योरमेंट का सिस्टम पूरे देश के अंदर बना हुआ है । देश के अंदर अकेला छत्तीसगढ़ राज्य है जो पेडीप्रोक्योर ही नहीं करता, सीधे उनके खाते में जमा करके यह सारी राशि ट्रांसफर करने वाला हिंदुस्तान का अकेला राज्य है, जो पूरे सिस्टम को करता है । (मेजों की थपथपाहट) इस पूरी व्यवस्था में हमको 5 महीने की अवधि लगती है, जब धान खरीदी करते हैं, भारतीय खाद्य निगम को मीलिंग कराते हैं फिर एफ.सी.आई. को देते हैं, अलग-अलग राज्यों को भेजने का काम हम करते हैं । आज वह सारी प्रक्रिया बताने की जरूरत नहीं है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जब किसानों के हित की बात करते हैं तो यह वर्ष 2003-04 में जो कृषि क्षेत्र में बजट 834 करोड़ था अब बढ़कर यही बजट जो 834 करोड़ था, 4000 करोड़ यानी कृषि क्षेत्र का हमारा 21 गुना बजट बढा है । खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2003-04 में 65 लाख मीट्रिक टन था बढ़कर 103 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन बढ़ा है । प्रमाणित बीज 73 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज दिया जाता था वर्ष 2003-04 में, 73 हजार से बढ़कर 10 लाख क्विंटल 21 गुना की वृद्धि हुई है यह ग्रोथ है । जो आपको दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने किया । पम्प 75-76 हजार थे, 5 लाख की संख्या में पम्प हो गये इसमें किसानों के लिये हमने सब्सिडी दी । 4 लाख 69 हजार किसानों को 1725 अकेला बोनस का वितरण 2100, 2200, 2300, 2400 करोड़ इस साल 2400 करोड़ हो जायेगा । अकेले किसान को केवल बोनस का लाभ नहीं मिलता, किसान को लाभ मिलता है जब जीरो इंटरेस्ट रेट में 3600 करोड़ का कर्ज देते हैं तो उसका लाभ किसानों को मिलता है, बिना ब्याज के कर्ज लेते है, दूसरा लाभ मिलता है जो 1775 करोड़ हर साल किसानों को इतनी राशि बिजली में जो उनको हम छूट देते हैं ।..............जारी

...........श्री यादव

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यादव\12-09-2018\h14\05.45-05.50

............(जारी डॉ.रमन सिंह) :- दूसरा लाभ मिलता है, 1775 करोड़ हर साल किसानों को इतनी राशि बिजली में हम उनको छूट देते हैं, 6000 यूनिट और 7500 यूनिट, अनुसूचित जाति, जनजाति को नि:शुल्क बिजली देते हैं तो करीब करीब 1752 करोड़ किसानों पर बिजली के माध्यम से खर्च करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) अनुसूचित जाति, जनजाति को नि:शुल्क बिजली देते हैं । इसके साथ ही साथ हमने अलग अलग योजनाओं से किसानों को पंप लगाने के लिए छूट देते हैं जैसे एक नई योजना सौर सुजला योजना लागू की । तीन वर्षों में 91000 सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा । 1300 करोड़ सीधा किसानों को मिलता है । उन्हें पांच हजार से बीस हजार रूपए ही देना पड़ता है । अभी तक 50000 के विरूद्ध 43000 सोलर पंप स्थापित हो गए हैं जिसमें बिजली का बिल नहीं लगता, सीधे सोलर के माध्यम से यह पंप चलता है । किसानों के लिए अलग अलग योजनाओ में सरल करने का काम किया । गौपालन में एक प्रतिशत ब्याज दर में उनको ऋण देने का काम, रूपे के सी सी कार्ड 10 लाख से ज्यादा किसानों को यह के सी सी कार्ड दिया । 43 लाख किसानों के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की । अलग अलग क्षेत्रों में कृषि सेवा यंत्र, गन्ना पर बोनस देने का काम, चना पर बोनस देने का काम, ऐरीगेशन के प्रोजेक्ट में गतिशीलता आए, किसानों के सिंचाई के संसाधनबढ़ें उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया । हमें जो 24 प्रतिशत सिंचाई प्रतिशता मिला था, वह बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया । इसके साथ ही साथ अलग अलग योजनाओं का विस्तार किया गया । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देश में 99 परियोजनाओं में से राज्य की तीन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, एक विषय जो कांग्रेस की नीति रही है, यह नारे लगाते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे लगाकर 40, 50 साल देश में राज करते रहे । गरीब और गरीब होता गया । गरीब का मकान बिक गया । आज यदि गरीबों के लिए कोई कार्य योजना लेकर काम कर रहा है तो वह इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके लिए कार्य योजना बनाई है । 36 लाख घरों में चूल्हा देने की योजना बनी है । 11 लाख आवास की योजना, शत प्रतिशत घरो में शौचालय बन गया है, हर घर में बिजली पहुंचाने की योजना बनी है । किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है । वन क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 750 करोड़ रूपए के बोनस देने का काम, यदि एक साल हिसाब लगा दिया जाए तो 2400 और 700 करोड

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो करीब 3400 करोड़ से ज्यादा का बोनस का वितरण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हम कर रहे हैं । इसलिए जिस तेजी के साथ हम विकास की दिशा में आगे बढ़े हैं इससे विपक्ष में निराशा दिखती है । हम यह बोनस दिवाली के पहले दे रहे हैं। दिवाली के पहले गांव में उत्साह हो, ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली हो और गांव में खुशहाली होगी तो अन्नदाता प्रसन्न होगा । अन्नदाता प्रसन्न होगा तो उसका नतीजा भी बहुत अच्छा आएगा । उस नतीजे से घबराकर इनकी पीड़ा हैं । (मेजों की थपथपाहट) इनके लिए इतनी सारी योजनाएं एक साथ आ गईं हैं, अब इनको लगता है कि इन योजनाओं से कैसे निकले । मगर एक बात निश्चित है कि 2003, 2008, 2013 में जो हुआ था, 2018 में उससे बेहतर होगा । 65 प्लस याने 65 प्लस, आज इस विधान सभा के बाद हम अगली विधान सभा में मिलेंगे और फिर बात करेंगे । अध्यक्ष महोदय, आज यह बोलकर जा रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष गवाह हैं, आप भी गवाह है और बहुत सारे लोग जो इधर बैठे हैं, वह भी गवाह हैं, अगली बार मिलेंगे तो हमारी संख्या वहां तक पहुंच जाएगी, 65 प्लस तक हो जाएगी । (मेजों की थपथपाहट) 65 प्लस का टारगेट है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यहां से यहां तक पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं।

डॉ.रमन सिंह :- ये पूरी हमारी लंबाई क्षेत्र में बढ़ी रहेगी क्योंकि इस बार बोनस भी मिल रहा है, तिहार भी मना रहे हैं और इंद्रदेव की जब कृपा होती हो तो सारे बांध छलक रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, यह अच्छे संकेत होते हैं । जब अच्छा होना होता है, इंद्रदेव ने भी वर्षा कराई, सारे बांध भर गए, छलक गए तो ऐसा होता है कि जब अच्छे शुभ काम होते हैं तो ईश्वर का भी सहयोग रहता है । (मेजों की थपथपाहट) इस शुभ काम के लिए अच्छी बारिश का संकेत है कि इस बार भी अच्छी बरसात होगी और हमारी संख्या 49, 50 में रूक रही थी, वह 65 प्लस के ऊपर निकल जाएंगे । इसी आशा और विश्वास के साथ कि फिर से मुलाकात होगी । आपने कहा कि मुलाकात होगी और ट्रक के पीछे कुछ लिखा रहता है "फिर मिलेंगे" । (हंसी) जरूर आप सबसे मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\h15\.-.5

श्री भूपेश बघेल:- अध्यक्ष महोदय, पाप का घड़ा भी छलक गया। पाप का घड़ा भी छलक रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 13, 29, 36, 41 एवं 64 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़, अठहत्तर लाख, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए।

श्री भूपेश बघेल :- संशोधन करिए दो साल का जो नहीं दिये उसको भी जोड़िए।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

समय: **शासकीय विधि विषयक कार्य**

5.52 बजे **(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018)**

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) का पुर:स्थापन करता हूं।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पारित किया जाए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अभी भी मौका है, दो साल का बोनस बचा है बढ़ा दें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\h16\05.55-05.60

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को चिंता इस कारण नहीं है कि न केवल कांग्रेस की सरकार इन दोनों साल का बोनस देगी, अपितु आपने जो बोनस दिया है, उसका दुगुना बोनस इसी साल का देगी, सरकार में बैठने के बाद । इसलिए हम लोगों को कतई चिंता नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में देंगे ऐसा सोच रहे हैं आप ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- क्यों नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी बाहर बोलना है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- क्यों नहीं ।

<u>2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018</u>

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए । अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय जो बिलासपुर विश्वविद्यालय के नामकरण से संबंधित विधेयक है । जो इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर रखा जाना है । इस विधेयक को लाने के पीछे हेतु भी यही है कि स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का जो जीवन रहा है, जहां एक लेखक, साहित्यकार, कवि हृदय, देश विदेशों में इस देश की प्रतिष्ठा को लगातार बनाए रखते हुए और राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी अपनी उस संवेदनशीलता, सद्विचार और राष्ट्रधर्मिता के प्रति जो उनकी अपनी प्रतिबद्धता रही है, ऐसे व्यक्ति के नाम से यदि विश्वविद्यालय का नामकरण होता है तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और आने वाली पीढ़ियों को इस बात का अहसास रहेगा कि आखिर किस व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय है तो उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, कृतित्व क्या रहा है । सामान्य तौर पर हम अपने महापुरूषों के नाम पर इसलिए ही इन संस्थानों के नाम रखते हैं ताकि जो पीढ़ियां हैं वे उनकी व्यक्तित्व से, कृतित्व से आने वाले उतार चढ़ाव और जीवन संघर्षों के बारे में सकें ।

समय
5.57 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए.)**

मैं समझता हूं कि अभी कल ही सारे सदन ने पक्ष विपक्ष सबने मिलकर स्वर्गीय अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दी है तो इस विधेयक में भी कोई बहुत चीजें नहीं हैं, सारे लोग सहमत होंगे । इसलिए मैंने यह विधेयक यहां लाया है । मैं सदन से यह उम्मीद करूंगा कि इस पर सर्वानुमति से विचार करके पारण करें ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2018 (क्रमांक 15 सन 2018) पर विचार किया जाए । श्री टी.एस.सिंहदेव ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, नि:संदेश हम सब भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का बहुत सम्मान करते हैं । वे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे । यदि हम बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके स्मरण में रखें तो वह सर्वोचित होगा । हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ।

श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :- सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (कमांक 15, सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

-- श्री अग्रवाल -

अग्रवाल\12-09-2018\h17\6.00-05

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पारित किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पारित किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

समय :-

6:01 बजे (अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए.)

(3) छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018)

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम 1982 के भाग-3 में वन विकास उपकरण उद्गृहित एवं व्यय करने का प्रावधान है । अधिनियम की धारा 6 और 7 में वन विकास उपकर के अधिरोपण एवं व्यय की रीति का वर्णन है । इसके अंतर्गत वन विभाग द्वारा ईमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य व्यावसायिक महत्व के वनोपज के विक्रय पर छत्तीसगढ़ कराधान संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 7 की उपधारा 1 के अनुसार 3 प्रतिशत की दर से वर्तमान में वन विकास उपकर उद्गृहित तथा संग्रहित किया जा रहा है । उक्त उपकर की राशि का उपयोग सामाजिक वानिकी, वन रोपण, वन पुनरोद्धार तथा वन विकास से संबंधित कामों के लिए प्रयोजन के लिए अधिसूचित करने के लिए किया जा सकता है । विगत चार वर्षों में वन विभाग, वन विकास उपकर से औसतन वार्षिक आय 20 करोड़ एवं चालू वित्तीय वर्ष में संभावित प्राप्तियां 20 करोड़ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय करों एवं राज्य करों को समाहित करते हुए एक कर लागू किया है । एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को "Eage of doing business" के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को जारी रखते हुए वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी, अन्य काष्ठ तथा बांस के विक्रय पर अधिरोपित वन विकास उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । इससे राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा एवं सुगमता होगी ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 में संशोधन करना आवश्यक है इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । मैं सदन से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने का अनुरोध चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पर विचार किया जाए ।

श्री रामदयाल उइके (पाली तानाखार) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम 1982 क्रमांक 15, 16 में संशोधित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, इस पर मैं अपना वक्तव्य देना चाहता हूं । अधिनियम वन विकास 7 में दिया गया है कि लघु वनोपज जिससे आदिवासियों को फायदा मिलता है और इमारती लकड़ी, काष्ट को विक्रय करने से राज्य सरकार को कर के रूप में, उपकर के रूप में राजस्व मिलता था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो वनोपज है, जो आदिवासियों का मूल सम्पत्ति है, जिसके माध्यम से वे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, इसके मूल्य में जो कटौती की गई है जैसे रंगीली लाख, कोसम का लाख

जारी...श्री देवांगन

देवांगन\12-09-2018\h18\06.05-06.10

जारी... श्री रामदयाल उइके :- इसके मूल्य में जो कटौती की गई है, जैसे रंगेली लाख, कोशम का लाख 230 रुपया प्रति किलो था, उसको घटाकर सौ रुपया किलो किया गया।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिनियम से उसका कोई मतलब नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामदयाल उइके :- आप इसमें धारा 7 में वन विकास उपकर की व्याख्या को पढ़िये, इसमें स्पष्ट लिखा है कि वन उपज के विक्रय या प्रदाय पर उदगृहीत उपकर ।

श्री महेश गागड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी लगने के कारण जो वन उपकर है, वह खत्म किया जा रहा है। उसको कहां आप बोनस और वनोपज में लाकर जोड़ रहे हैं?

श्री रामदयाल उइके :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि वनोपज के मूल्य पर कटौती क्यों की गई है, इसको न किया जाए। अब जितनी भी लकड़ी सेल करेंगे, उस पर जो कर लगता है, उसको आप समाप्त कर दीजिए, रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन हमारा जो कोशम है, आपका चिरौंजी है, महुआ है..।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें एक लाइन का है। वैट, जो 3 परसेंट लगता था, उपकर लगता था, उसको समाप्त किया जाए या नहीं।

श्री रामदयाल उइके :- 320 रुपया प्रति किलो जो लाख बिकता था, उसको डेढ़ सौ रुपया कर दिया गया तो इसको यथावत रखा जाए, बाकी आप जो कुछ भी करें, हमें दिक्कत नहीं है। आदिवासी समाज का फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। हर्रा 11 रुपया किलो था, उसको 8 रुपया कर दिया गया। ये 3 रुपया क्यों? यह मेरा निवेदन है। बाकी आप सक्षम हैं, सरकार सक्षम है। आदिवासियों का ध्यान रखा जाए। वनोपज पर आधारित मूल्य को यथावत रखा जाए।

श्री नवीन मारकण्डेय (आरंग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उक्त संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17, सन् 2018)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक देश, एक बाजार, एक कर इसकी परिकल्पना कर के 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस विधान सभा में जीएसटी का एक्ट लाया गया था, उस समय ....

जारी श्रीमती सविता

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सविता\12-09-2018\h19\06.10-06.15

जारी श्री अमर अग्रवाल :- एक्ट लाया गया था तो इस सदन में उस समय कुछ शंकाएं, कुशंकाएं, चिन्ताएं आयी थीं, इस पर कई सदस्यों का मत था कि उस एक्ट में जो मतदान का अधिकार है, सारे राज्य भी एक तरफ हो जाएं और केन्द्र सरकार नहीं चाहे तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस सदन की चिन्ता थी कि ये जो वोटिंग पैटर्न है उसके बाद राज्यों की नहीं सुनी जाएगी, राज्यों के हितों का ख्याल नहीं रखा जाएगा और राज्य के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी कहा था कि ये जो एक्ट है ये आजादी के बाद अर्थक्षेत्र का सबसे बड़ा रिफार्मस् है देश, राज्य हित में है और वास्तव में आजादी के बाद को-ऑपरेटिव फेटलिजम का जीता जागता उदाहरण, अगर इस देश ने देखा है तो 1 जुलाई, 2017 के बाद देखा है कि देश के हित में विभिन्न दलों की सरकार, विभिन्न राज्यों की परिस्थिति, लेकिन राष्ट्र हित में सब एक प्रकार कैसे निर्णय लेते हैं ? आजादी के बाद इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला तो इस जी.एस.टी. में देखने को मिला और इस जी.एस.टी. के पीछे यही परिकल्पना थी। क्योंकि उस समय सब चिन्ताएं की गई थी तो मैं आवश्यक समझता हूँ कि जो हमारे राज्य के हित थे, जहां राज्य की आवाज थी, हमने कैसे-कैसे परिणाम तक पहुँचाया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। माननीय विमल चोपड़ा जी बैठे हैं। फर्शी पत्थर, हमारे यहां की कॉडेज इंडस्ट्री है, फर्शी पत्थर पर 28 प्रतिशत टैक्स लगा, अनेक बार सारे फर्शी पत्थर वाले आए, इसमें 50 हजार मजदूर इंवाल्व थे और क्योंकि फर्शी पत्थर हल्का होता है तो वह जब बाहर जाता है तो उनका माल 28 प्रतिशत जी.एस.टी. में नहीं बिक रहा था और राज्य ने इसका रिप्रजेंट किया, आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य के रिप्रजेंटेशन के कारण, लगातार बातचीत करने के कारण उसको हमने 5 प्रतिशत कराया और राज्य ने उस सारे फर्शी पत्थर उद्योग को जीवित करने का काम किया।

डॉ. विमल चोपड़ा :- मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो फ्लाईएश है, हमारे यहां ज्यादा होता है और जब फ्लाईएश ब्रिक्स पर भी टैक्स ज्यादा लगा। हमने इस बात की आवाज उठायी कि हमारे यहां फ्लाईएश है हम पूरे देश को पॉवर देते हैं और अगर हम उसका प्रदूषण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

झेलते हैं, फ्लाईएश का निपटारा करने के लिए टैक्स में रियायत नहीं मिलेगी तो छत्तीसगढ़ के साथ न्याय नहीं होगा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फ्लाईएश, सेनेटरी नेपकिन हो, हमने उसको कर मुक्त करवाया। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि एक नई व्यवस्था में बहुत से जो अनुभव सामने आएं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारे छत्तीसगढ़ में वेट था, उस समय हमारी कम्पोजिसन की सीमा 60 लाख रूपये थी, जब जी.एस.टी. कौंसिल की पहली बैठक हुई, कोई राज्य इससे सहमत नहीं था, थ्रेस होल्ड, वे चाहते थे कि 10 लाख हो जाए, कम्पोजिसन 25 लाख हो जाए, क्योंकि जो छोटे व्यवसायी हैं उनको एक सरलीकरण के लिए हमने कम्पोजिसन की सीमा 60 लाख रूपये जो हमारे यहां थी, उसका प्रस्ताव दिया था और हमने सारे राज्यों को सहमत कराया और आज जी.एस.टी. में 60 लाख रूपये कम्पोजिसन है, बाद में मांग उठी उसको पूरे देश में 1 करोड़ रूपये तक ....

जारी श्री चौधरी

चौधरी\12-09-2018\i10\06.15-06.20

पूर्व जारी... श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में मांग उठी, उसको पूरे देश में 1 करोड़ रुपये तक कराया गया। उसके भी हम चाहते थे कि ये सीमा और बढ़े, लेकिन चूंकि भारत सरकार में ये एक्ट पास हो गया था और उसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये थी तो हमने बाद में प्रस्ताव दिया कि आज जो मैक्सिमम सीमा है 1 करोड़ तक कम्पोजीशन हो जाये और इसको बाद में डेढ़ करोड़ तक ले जाना चाहिए। लेकिन चूंकि एक्ट में 1 करोड़ तक की सीमा थी, अध्यक्ष महोदय, आज जो संशोधन है वह 1 करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ का संशोधन एक धारा में है। कम्पोजीशन का अगर हम रेट देखें मात्र 1 प्रतिशत .5 सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट का सी.जी.एस.टी., .5 एस.जी.एस.टी., इतना मिनिमम रेट है। इसके बाद एक विषय और आया कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदेगा, उसको रिवर्स चार्ज लगेगा। पूरे देश के जो छोटे व्यवसायी हैं सबने इस बात का रिप्रेजेन्टेशन दिया कि ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिजम है, ये कठिन है। मैं कोई ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ राज्य ने, सारे राज्यों ने मिलकर और भारत सरकार ने भी तय किया। हमने रिवर्स चार्ज का भी जो एक्ट में प्रावधान था कि रिवर्स चार्ज मेन्डेटरी होगा, हमने कुछ समय के लिए स्थगित कराया। चूंकि एक्ट में मेन्डेटरी है, आज एक्ट में परिवर्तन करके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कुछ जगह छोड़कर हमने रिवर्स चार्ज को भी वापस लेने का आज ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये रिवर्स चार्ज का है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एक विषय आया कि हर महीना जो 3 रिटर्न देने पड़ते थे, साल में 36 रिटर्न देने पड़ते थे। बाद में सारे अनुभव, बातचीत, कठिनाई के आधार पर हमने इस पर चर्चा की और पूरी जी.एस.टी. कौन्सिल ने ये निर्णय लिया कि अब महीने में एक रिटर्न होगा। और जो छोटे व्यवसायी हैं, रूल नोटिफाईड होना हैं, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ तक का जिनका टर्न ओवर है उनको क्वाटरली रिटर्न फाईल करना पड़ेगा। उसमें जो सरलीकरण है उसका इस एक्ट में प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जी.एस.टी. कौन्सिल में ये जितने भी रिफार्मस हुए, उसमें जो ग्रूप ऑफ मिनिस्टर बने, चाहे वह रिवर्स चार्ज का हो, काम्पोजीशन का हो, छत्तीसगढ़ को इसका प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ सरकार इन 5 राज्यों में इन सारे नियमों में परिवर्तन कराने में सफल रही है, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि इसका रिप्रजेन्टेशन करने का अवसर छत्तीसगढ़ की सरकार को मिला। इस एक्ट में और जो सरलीकरण, नियम है, उसके प्रावधान हैं, जहां-जहां पर क्लीयरटी नहीं थीं, कुछ मिरर था, ये सारे प्रावधान इस एक्ट में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जी.एस.टी. कौन्सिल की जो व्यवस्था है, उसका जो एक्ट का संशोधन है, पहले इस देश की पार्लियामेन्ट में पास होगा और ऐजटीज बिना कोई इसको मिरर एक्ट बोल सकते हैं, ऐजटीज देश की सारे राज्य की विधानसभाओं में पास होना आवश्यक है। अगस्त में देश की संसद ने ये एक्ट पास कर दिया है और 1 अक्टूबर से ये सारे नियम ये जो एक्ट में परिवर्तन होना है, वह देश में लागू होना है। चूंकि ये मिरर एक्ट है जो जी.एस.टी. कौन्सिल ने पास किया है, पार्लियामेन्ट ने पास किया है, ये सारे संशोधन के लिए जी.एस.टी. कौन्सिल का ये एक्ट का परिवर्तन हम इस विधानसभा में लाये हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जी.एस.टी. को लेकर जो धारणाएं थीं, वह धीरे- धीरे पूरी जी.एस.टी. कौन्सिल का, सरकार का जो ओपन माईन्ड रहा, लगभग-लगभग हमने 300 अमेन्डमेन्ट किये हैं। क्योंकि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा दिमाग खुला हुआ है और जहां भी परेशानी जायेगी, इसमें हम संशोधन करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं ..(जारी)..

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरविन्द

अरविंद\12-09-2018\i11\06.20-06.25

..........जारी श्री अमर अग्रवाल :- मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि पहले जिस प्रकार से जी0एस0टी0 के लिए साल-डेढ़ साल तक डेलीगेशन आते थे, देश में कहीं भी जाओ, मालूम पड़ जाये कि जी0एस0टी0 कौंसिंल का मेम्बर है, तो एक कागज आ जाता था। लेकिन पिछले तीन महीने से कोई मेमोरण्डम नहीं आता है और मैं ऐसा समझता हूं कि ये सारे संशोधन के बाद जी0एस0टी0 एक अच्छी व्यवस्था के तहत जो हमारे देश की कल्पना है, उस दिशा में जा चुका है और आगे प्रगति होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा। मैंने इसी विधानसभा में कहा था कि जिस कन्ट्री में जी0एस0टी0 आया, उस कन्ट्री का जी0एस0डी0पी0 1 से 2 प्रतिशत बढ़ा है। आज इस एक साल के बाद मुझे प्रसन्न्ता है कि जिस भावना के साथ इस देश में जी0एस0टी0 लाया गया कि इस देश की आर्थिक प्रगति हो। इस साल के प्रथम तिमाही में इस देश का जी0डी0पी0 8.3 है, जो एक सर्वाधिक है। अगर उसका श्रेय जाता है तो इस जी0एस0टी0 को जाता है। इसलिए हमने ये सारे संशोधन आज एक्ट के माध्यम से लाये हैं। मेरा सारे सदस्यों से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पर विचार किया जाये। श्री टी0एस0 सिंहदेव।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी0एस0सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रारंभ में ही कहा कि जब जी0एस0टी0 बिल लागू होना था, उस पर चर्चा और जब यहां से प्रस्ताव जाने की बात आई, तो शंकाएं-कुशंकाएं और अन्य विचार इस सदन में व्यक्त हुए। स्वयं मंत्री जी ने अभी बयान किया, वह इस बात का प्रमाण है कि उस समय जिन शंकाओं को प्रकट किया था, वे कुशंकाएं नहीं थीं, वे वास्तविक परिस्थितियां थीं और इतनी जल्दबाजी में जिन लोगों ने देश के ऊपर जी0एस0टी0 को लादा, वे वही लोग थे जो कहा करते थे कि कभी जी0एस0टी0 को इस देश में लागू नहीं करना। हम जी0एस0टी0 को लागू नहीं होने देंगे। छाती हो 56 इंच की, 54 इंच की या 58 इंच, लेकिन देश में बिलकुल लागू नहीं होना है। उस समय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कई प्रकार की चर्चाएं थीं कि जी0एस0टी0 कहां लागू करना है- point of production या point of consumption करना, और अंततः हमने point of consumption जी0एस0टी0 को लागू किया। इतनी परेशानियां, इतनी पेचिदगियां, इतनी दुर्व्यवस्था बनी कि देश का जी0डी0पी0 क्या वास्तविक व्यवहार, व्यवसाय सारा प्रभावित हुआ। यहां तक कि रोजगार प्रभावित हुआ। अनेकों माइक्रो माइनर, मीडियम स्केल के उद्यम बंद हुए, 30 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित और बंद हुए। तो जोश विचार थे, ये केवल शंकाएं नहीं थीं। वह लोगों की वास्तविक सोच थी, जो धरातल पर व्यापार से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते थे। उन बातों का प्रमाण, मेरे को दो सौ का ध्यान था, माननीय मंत्री जी ने तीन सौ कहा। आपने कैसा खुलापन रखा, आप थोड़ा सा रूक जाते, थोड़ा सा सोच लेते, फिर लागू करते, देश के ऊपर आपने ऐसी व्यवस्था लागू की कि आपको अपने नियम को मेरे हिसाब से दो सौ और आपके हिसाब से तीन सौ बार परिवर्तित करना पड़ा। आज आपने जिन कण्डिकाओं को प्रस्तुत किया है, वह 31 कण्डिकाओं की न जाने कितनी उपधाराएं हैं। कहीं किन्तु, परन्तु है, कहीं विराम की जगह कुछ है, कहीं कामा की जगह कुछ है, इस प्रकार की भी बातें हैं। लेकिन इस प्रकार की बातें इसमें आई हैं। बहुत जल्दबाजी में जी0एस0टी0 लागू किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- छोटे-छोटे चिन्ह की जगह सीधा आपके ऊपर फुलस्टाप लगा दी जनता इधर आने के लिए। कामा भी नहीं, फुलस्टाप।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- बहुत कम दिन बचे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- ज्यादा मत फटफटाईये साहब, दो महीने बचे हैं। सीट के लिए तरस जाईयेगा।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटबंदी के साथ जी0एस0टी0 लागू करना इतनी छोटी सोच, कम सोच, अपरिपक्व सोच का परिचायक था। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था बेहद दवाब में काम कर रही है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है एक गंभीर और बड़ी चिंता का विषय है। जब ऐसी बातें प्रकाशित होती हैं कि जी0एस0टी0 के टारगेट यदि 01 लाख करोड़ रूपये प्रतिमाह वसूली का है तो 50 हजार करोड़ रूपये की वसूली ही जी0एस0टी0 के माध्यम से हो पाई है। तो बहुत सारी चीजें अभी भविष्य में है। बहुत जल्दबाजी में लागू किए हुए जी0एस0टी0 के कानून को इस देश में अनेकों स्लेबों में बांटा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

.........जारी श्री श्रीवास

श्रीवास\12-09-2018\i12\06.25-06.30

जारी...श्री टी.एस.सिंहदेव......जी.एस.टी. के कानून को इस देश में अनेक स्लैब में बांटा गया है । यह दुनिया का जटिलतम एक या दो देश हैं, जहां पर इतने जटिल जी.एस.टी. के रेट होंगे,अध्यक्ष महोदय, उसमें दुर्भाग्य हमारे देश का है, जीरो से लेकर 40 परशेंट तक उपकर लेकर हमारे यहां जी.एस.टी. के टैक्सेसन का स्लैब बनाये हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. वाली जो बात है, अभी ई-वे बिल की बात चल रही थी, इसी जी.एस.टी. का अंग था, स्टेट के अंदर भी ई-वे बिल, मैंने भी मुख्यमंत्री जी को लिखा था, पर संयोग से दूसरे दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी । चलिये पहले से सोचा था या पत्र भी काम आया । अध्यक्ष महोदय, बहुत परेशानियां एक दुकान से दूसरे दुकान स्टेट के अंदर ले जा रहे हैं, ई-वे बिल का माथा और पकड़ो । अभी भी बहुत अधिक जटिलताएं इस व्यवस्था में है । राज्यों की जो बात है, उनके निर्णय लेने का जो प्रतिशत है, 66-33 है, मेरे ख्याल से । राज्यों का वेट और केन्द्र का वेट । अध्यक्ष महोदय, यह तो राज्यों का अधिकार गये । वह तो चर्चा का विषय ही नहीं रहा । जहां आपने राज्यों को कर लगाने की बात थी, शेडयूल में अलग-अलग व्यवस्थाओं की बात थी, आज वह बात तो गई। इस कानून में वह बात गई । इसमें कोई दो बात ही नहीं है । आज भी जितनी बातों को आपने कहा, सुन लिया तो हो गया, आप स्वयं कितने लाचार हैं कि आपके राज्य की अगर कोई बात है तो आप उसको मनवा नहीं सकते । मान लिया तो बहुत बड़ी बात हो गयी । अध्यक्ष महोदय, वास्तविक फेडरलिज्म की बात हम करें तो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर इस कर से प्रभावित ही हुआ है । उसको स्वतंत्र रूप से फेडरल स्ट्रक्चर नहीं माना जा सकता । जब कोई भी राज्य अपनी व्यवस्था के अनुसार निर्णय नहीं कर सकता, जब तक केन्द्र सरकार की हामी न हो । वह अलग विषय है । जी.एस.टी. के संशोधन आये हैं, मैंने भी पढ़ने का प्रयास किया । वह इतनी बातें हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो केन्द्र का आयेगा, उसको डिनाय करना है, उसमें बहुत सारी बातें कुछ सोचने, समझने की, नहीं रह जाती । किन्तु जी.एस.टी. बहुत बड़ी परेशानी का सबब अभी भी बना हुआ है । न जाने 200 और 300 के बाद भी और कितने संशोधनों का हमको इंतजार करना पड़ेगा । आप बिल लेकर आये हैं । अगर डिटो करना है, वह तो पास आप करा ही लोगे । क्योंकि जी.एस.टी. के पाले में संकोच होता है, लगता है कि सर्वसम्मति से करा दें । पता नहीं क्या-क्या इसमें कोई और ऐसी बात न हो । प्रदेश में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यवसायियों में बहुत नाखुशी जी.एस.टी. को लेकर है । बहुतबहुत परेशानी से गुड एवं सर्विसेज टैक्स की व्यवस्था से हम सब नागरिक जूझ रहे हैं । आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री श्याम बिहारी जायसवाल ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पेश किये गये जी.एस.टी. बिल संशोधन के संदर्भ में मैं उसका समर्थन करता हूँ । आपने समय दिया, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, क्योंकि मैं वर्ष 2003 से इम्पावर पॉवर कमेटी में रहा, जो बाद में जी.एस.टी.काउंसिल में रही । इस देश में जी.एस.टी. के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 56 इन्च का सीना वाले कहते थे कि देश में जी.एस.टी. कभी नहीं आ सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ भी शुरू में इंपावर कमेटी जी.एस.टी. का निर्माण कर रही थी, मैं उस इम्पावर कमेटी का सदस्य रहा हूँ, हमने बोला है । हमने कभी जी.एस.टी. का विरोध नहीं किया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन साहब हम लोग टी.वी. में देख रहे थे कि मोदी जी ने किया है ।

श्री अमर अग्रवाल :- हमने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन विषय की चर्चा स्टेट के आटोनामस की माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कर रहे थे, वही विषय हम कहते थे । स्टेट की ऑटोनामी ....

जारी...श्रीमती यादव

नीरमणी\12-09-2018\i13\06.30-06.35

श्री अमर अग्रवाल :- हां-हां, मैं बता रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जिन विषयों की चर्चा स्टेट के ऑटोनामी की अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कर रहे थे, वही विषय हम कहते थे कि स्टेट की ऑटोनामी । माननीय चिदंबरम जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, श्री प्रणब जी उस मीटिंग में उनके भी तर्क सुने, सब हुआ और राष्ट्रहित में जब हमने एक निर्णय लिया उस समय देश के वित्तमंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी जी और बाद में चिदम्बरम जी आये । सी.एस.टी. जो 4 परसेंट था, जो जी.एस.टी. में जीरो होना है । उस समय 2 परसेंट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कराया गया, 2 परसेंट कराया गया और राज्यों को यह कहा गया कि जी.एस.टी. की यह पहली शुरूआत होगी, आप लोगों का विश्वास जमेगा, 2 परसेंट कम करिये और 2 परसेंट कम करने के बाद जो घाटा होगा उसकी पूर्ति भारत सरकार करेगी । उसमें सबकी सहमति थी, सारे राज्यों ने किया, 4 में से 2 कांग्रेस शासित राज्य भी थे, बीजेपी शासित राज्य भी थे, कम्प्युनिस्ट शासित राज्य भी थे, हमने 4 से 2 किया लेकिन यह विश्वास क्यों टूटा। 2 साल देने के बाद तीसरे साल भारत सरकार ने मना कर दिया, हमारा टैक्स कम करा दिया और मना कर दिया कि हम कोई कम्पनसेशन नहीं देंगे और 1 हजार करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ सरकार का रोका और लगभग-लगभग 22 हजार करोड़ रूपये सारे राज्यों का उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 22 हजार करोड़ रूपये भारत सरकार ने रोका, अविश्वास वहां से पैदा हुआ और जब उस समय यूपीए की गवर्नमेंट चली गयी और उसके बाद फिर इम्पॉवर कमेटी में श्री अरूण जेटली जी जब वित्तमंत्री बनकर आये तो उन्होंने पूछा कि आखिर जीएसटी का विरोध क्यों है तो हमने कहा कि साहब हम जीएसटी के विरोध में नहीं हैं, न उस समय थे और न आज हैं । उसमें गुजरात भी शामिल था लेकिन जो बात होती है, जो कमिटमेंट होता है वह जब फुलफिल नहीं होता तो यह जो फेरलिजम कॉपरेटिव की बातचीत हो रही है उसमें अगर अविश्वास होता है तो इस देश में जीएसटी आ नहीं सकता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कोई निर्णय करते हैं और उस निर्णय में जो बाधा है उसकी जड़ तक जाते हैं कि वह निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें प्रावधान क्या है और वहां से वे शुरूआत करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पहला काम किया । जीएसटी की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि भारत सरकार, भारत सरकार है । चाहे यूपीए की हो, चाहे एनडीए की हो, यदि कोई कमिटमेंट है तो उसको हम पूरा करेंगे और उन्होंने 22 हजार करोड़ रूपया बिना जीएसटी की शुरूआत के राज्यों का विश्वास जीतने के लिये सारे राज्यों को दे दिया, उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं । (मेजों की थपथपाहट) यह होता है विश्वास, यह होती है लीडरशिप । जब अविश्वास हो, राज्यों के हित चले जायें, राज्यों के रेवेन्यू चली जाये तो क्यों नहीं कहेंगे कि इस देश में जीएसटी नहीं आ सकता और जब विश्वास होता है तो राष्ट्रहित में राज्यहित भी पीछे करने पड़ते हैं तो वह हमने किया है । दूसरी बात मैं समझ नहीं पाया हूं आज तक कि जीएसटी कौंसिल जो है वह कोई भारत सरकार की प्रतिनिधि नहीं है । जीएसटी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कौंसिल सारे राज्यों के वित्तमंत्री और भारत सरकार के वित्तमंत्री की जीएसटी कौंसिल है । कौन से दल नहीं हैं उसमें, इस देश में सारे राज्य और सारे दलों की सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक बैठक को छोड़कर सारी बैठकों में रहा हूं जो भी निर्णय हुए हैं, जो भी एक्ट पास हुआ है चाहे शुरूआत में हुआ है, आमसहमति से हुआ है । कभी वोट की स्थिति नहीं आयी, आम सहमति से हुआ है और उसमें कांग्रेस की भी सहभागिता है । मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वहां पर जो कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं, वे उस पर मोहर लगाते हैं, पॉर्लियामेंट में मोहर लगाते हैं और बाहर जिस प्रकार का अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि वह एक्ट जल्दबाजी में लाया गया तो वह एक्ट पास किसने किया, जीएसटी कौंसिल ने किया । उसमें कांग्रेसियों के प्रतिनधित्व हैं और मैं तो कई बार बोलता हूं कि या तो इनके कांग्रेस के जो वित्त मंत्री हैं उनका इनकी पार्टी का कंट्रोल ही नहीं है वहां पर वे केवल ठप्पा लगाकर आ जाते हैं या फिर वे इनकी सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं । वे यह मानते हैं कि अच्छा हो रहा है । पार्टी को जो बोलना है बोलने दो ।..............जारी

........श्री यादव

यादव\12-09-2018\i14\06.35-06.40

............(जारी श्री अमर अग्रवाल) :- या तो इनके कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं, उन पर इनकी पार्टी का कंट्रोल ही नहीं है । वहां वह केवल ठप्पा लगाकर आ जाते हैं या वह इनकी सुनते नहीं है, मानते नहीं हैं । वह यह मानते हैं कि अच्छा हो रहा है, पार्टी को जो बोलना है बोलने दो । शुरू में भी जो एक्ट आया, वह सर्वानुमति से आया ।

श्री अजय चंद्राकर :- जी एस टी कौंसिल में कांग्रेस कितने वित्त मंत्री हैं ?

श्री अमर अग्रवाल :- दो, चार हैं, पंजाब के हैं, पांडिचेरी के हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 25 प्रतिशत से कम हैं । 75:25 हैं या नहीं ?

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं, वोटिंग नहीं हुई । मैंने पहले ही कहा कि आम सहमति ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वोटिंग नहीं, लेकिन एक्ट में क्या प्रावधान हैं, यह तो बता दीजिए?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमर अग्रवाल :- आम सहमति । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जी एस टी कौंसिल में जो इनके प्रभारी रहे हैं, वह नारायण सामी जो चीफ मिनिस्टर पांडिचेरी हैं, वह भी उसमें मुहर लगाते हैं । नारायण सामी इन सबके प्रभारी रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी चीज सर्वानुमति से होना, पार्लियामेंट में सर्वानुमति से पास होना, उसके बाद बोले कि एक्ट जल्दबाजी में आ गया । कोई भी एक्ट होता है और जो भी एक नई व्यवस्था लगी, उसमें इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार का ओपन माईंड है, जो जो परेशानी जाएगी, उसका हम समाधान करेंगे । केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया और दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जी एस टी जहां पर आया इतनी जल्दी जी एस टी को एक मूर्तरूप तक पहुंचाकर एक मॉडल एक्ट बनाया । (मेजों की थपथपाहट) दुनिया का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन भारत में हुआ और क्यों हुआ, सरकार का ओपन माईंड, सरकार ने कभी इस बात की जिद्द नहीं की कि हम एक्ट में परिवर्तन नहीं करेंगे । यदि कोई परेशानी आई जी ओ एम बना, कांग्रेस के वित्त मंत्री भी उसके सदस्य रहे । एक्ट भी सोच समझकर बना था, उसमें जो बातचीत आई, वह हुआ । जहां तक सवाल है तो मैंने पहले ही कहा कि जितने मेमोरेंडम आए, व्यापार की जितनी परेशानी थी, सबका समाधान किया है । अभी मैं फिलहाल कमर्शियल टैक्स देख रहा हूं, लेकिन तीन महीने से कोई बिजनेस, कोई ट्रेडर्स न मुख्यमंत्री जी के पास जाता, न हमारे पास जाता और कल भी मेरी कुछ लोगों से पी एच डी टेंबर में मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी जी एस टी को अच्छे रूप से भारतवर्ष में लागू किया है, यह अपने आप में एक उदाहरण है । आज यह बोलते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आज कोई परेशानी नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- वैसे आप भाषण अच्छा करते हैं, लागू करना हो तो भी और न लागू करना हो तो भी । दोनों के पक्ष में भाषण अच्छा करते हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि जो यह नहीं करा पाए, ठीक है, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ होगा, वह एन डी ए की सरकार ने किया और अच्छे रूप से किया, जी एस डी पी के लिए किया । जहां तक आर्थिक प्रगति का सवाल है, मैंने आंकड़े दिये कि यह प्रथम तिमाही पर जो जी एस डी पी 8.3 है, आर्थिक प्रगति हुई है । मालूम नहीं इनको क्यों लगता है कि कभी जी एस टी का लाभ मिल जाए, कभी लगता है नोटबंदी का मिल जाए, कभी लगता है कि डीजल, पेट्रोल का लाभ मिल जाए । ठीक है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अपोजिशन में है, इनका कर्त्तव्य है, लेकिन जनता बहुत अच्छे से जानती है । पहली जो गवर्नमेंट थी उसको पैरालाईज गवर्नमेंट बोलते थे, पैरालाईज डिसीजन बोलते थे । आज की सरकार सारे निर्णय करती है । जनता खूब जानती है । इनके गवर्नर रघुराम राजन, जिनको इन्होंने गवर्नर बनाया, उन्होंने कहा कि मैंने बैंक फ्राड की सूचना दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने फ्राड होने दिया, यह आज ही आया है । यह उनकी तरफ से आया जो आर बी आई के गवर्नर रहे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 2016 में उन्होंने यह सूचना दी थी, उस समय कौन सी सरकार थी? रघुराम राजन का स्टेटमेंट आया है 2016 में सूचना दी, आप फिर से उसको उठाकर देख लीजिए । 2016 में उन्होंने लिखकर दिया था और चिन्हांकित लोगों के नाम, उसका खुलासा नहीं किया, उसकी जानकारी पी एम ओ पर थी और उन्होंन कहा था कि इसके ऊपर कार्यवाही करिए । धन्य हो आपके प्रचार तंत्र का कि 2016 को भी आपने 2011 बना दिया । यह इनकी सरकार के समय का था । धन्य हो, धन्य हो ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद नेता जी फिर से सन् गलत बोल रहे हैं । बहुत स्पष्ट तौर पर रघुराम राजन ने जो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के इंचार्जशिप में कमेटी बनी है और उस कमेटी में नीति आयोग के सदस्य सुब्रमणियम के द्वारा वहां पर जो बयान दिया गया कि इसके बारे में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी............(जारी)

श्री मिश्रा

मिश्रा\12-09-2018\i15\.-.5

जारी.. श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय :- और उस कमेटी में नीति आयोग के सदस्य सुब्रमणियम के द्वारा वहां पर जो बयान दिया गया इसके बारे में पूर्व गवर्नर रघुराजन जी अच्छे से बतायेंगे कि क्यों एन.पी.ए. है तो उनका स्पष्ट बयान है कि सारे बैंक के जितने बड़े लोन की गड़बड़ी हुई है वह वर्ष 2006 से वर्ष 2008 के बीच में अति उत्साह में हुई है और सरकार निष्क्रिय रही इस कारण से हुआ। बार-बार पी.एम.ओ. को कहा और वह वर्ष 2011 के समय का ही उल्लेख है, वर्ष 2016 में नहीं है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपको देखना है तो मैं दिखा दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- वर्ष 2006 में नीरव मोदी भी चले गये थे।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और ये सोचते हैं कि कभी नोटबंदी, कभी जी.एस.टी., कभी डीजल-पेट्रोल और वैसे अच्छी बात है, हालॉकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि न तो ये सत्ता को चला पाये और न ये विपक्ष को ठीक से चला पा रहे हैं। ये दोनों में फेल हैं यह हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लेकिन ये शुरूआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं इनको जनता फिर से विपक्ष में बैठायेगी, संख्या क्या कम होगी वह एक अलग बात है, अभी सी.एम. साहब बता रहे थे कि इसमें से थोड़ी संख्या कम हो जायेगी। ये सब करते रहें और इस प्रकार के जी.एस.टी. जैसे जो अच्छे निर्णय हैं वह देश को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारी सहभागिता रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 से 31 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 2 से 31 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

समय:
18.43 बजे **नियम 239 के अंतर्गत सदन की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- श्री टी.एस. सिंहदेव, माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा एवं माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, चुन्नीलाल साहू, संतराम नेताम, दीपक बैज एवं दिलीप लहरिया द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं दिनांक 12/09/2018 मेरे समक्ष विचाराधीन हैं।

समय:
18.44 बजे **सत्र का समापन**

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अब आगे और कोई सत्र तो नहीं होगा ना? अब आगे और कोई बात आये तो फिर बुला लें?

अध्यक्ष महोदय :- चतुर्थ विधानसभा का यह दो दिवसीय सत्रहवां सत्र जो विशेष सत्र भी है का आज अंतिम कार्यदिवस है। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस विशेष सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सहभागिता और सहयोग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अब तक के संसदीय इतिहास में यह कीर्तिमान है कि इस चतुर्थ विधानसभा में सबसे अधिक कुल सत्रह सत्र आहूत हुये तथा इन 17 सत्रों में कुल 145 बैठकों में 845 घंटे 47 मिनट चर्चा हुई। विगत सत्र के अंतिम कार्यदिवस में जब हमने सदन में एक दूसरे को शुभकामनाएं दी थीं, तो हममें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि चतुर्थ विधानसभा के विघटन के पूर्व एक बार फिर सदन में हमारी उपस्थिति होगी, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे किसान भाईयों की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ही उनकी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए इस विशेष सत्र को आहूत किया गया और हम पुन: इस सदन में उपस्थित हुए हैं। श्री कुरैशी

कुरैशी\12-09-2018\i16\06.45-06.50

जारी..........अध्यक्ष महोदय :- उनकी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए इस विशेष सत्र को आहुत किया गया और हम पुन: इस सदन में उपस्थित हुए हैं । छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है यहां की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और जब तक यहां का किसान सम्पन्न और सुखी नहीं होगा तब तक राज्य के विकास की परिभाषा पूर्ण नहीं मानी जावेगी तथा किसान भाईयों के लिए जो आपने संवेदनशीलता प्रदर्शित की उसके लिेए आप सभी बधाई के पात्र हैं । यह उल्लेखनीय है कि राज्य के हमारे किसान भाईयों को धान की खरीदी के साथ बोनस प्राप्त होगा, यह निर्णय हमारे किसान भाईयों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण है । राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के चलते माननीय सदस्यों के मत में भले ही भिन्नता हो, परंतु आप सभी की भावना छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि को समर्पित् है । मेरा यह भी विश्वास है कि आप सभी ने अपनी राजनीतिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से परे लोकहित और लोक कल्याण को ज्यादा महत्व दिया है । आप सबकी इस भावना के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद् देता हूं ।

इस सत्र के प्रथम दिवस माननीय राज्यपाल बलरामदास जी टंडन, भारत रत्न एवं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूज्य श्री अटल बिहारी बाजपेयी, पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी जी एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्तमंत्री माननीय श्री रामचंद्र सिंहदेव जी के निधन पर हमने श्रद्धांजलि अर्पित की । आईए हम सब मिलकर इन महान् विभूतियों के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और उसे जीवन में व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करें और एक आदर्श नागरिक तथा एक जनप्रिय जनसेवक बनने का संकल्प लें । हमारी यह भावना, इन महान व्यक्तित्वों के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि होगी ।

इस विशेष सत्र में कुल दो बैठकें सम्पन्न हुईं, जिसमें लगभग 8 घंटे 48 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 4 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुईं और सभी विधेयक पारित हुए । वित्तीय कार्यों के अंतर्गत द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर 5 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई । मैं इस विशेष सत्र के सुव्यवस्थित संचालन में सभापति तालिका के सभी माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रिगणों सहित सभी माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं । मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माननीय पत्रकार साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस सत्र के दौरान सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी । मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

आज तीज का पर्व है, आज तीज का पर्व है मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से छत्तीसगढ़ की सभी माता-बहनों को लोक पर्व तीजा की शुभकामनाएं देता हूं । कल से विध्नहर्ता श्री गणेश जी की स्थापना का पर्व प्रारंभ हो रहा है । मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं औ कामना करता हूं कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे । यह सत्र अब अंतिम सत्र कहा जा सकता है । क्योंकि शीघ्र ही राज्य में पांचवी विधान सभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होगी । मैं आप सभी के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हुए आहवान करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें । धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, सत्र के समापन के अवसर पर आपके द्वारा किए गए औपचारिक उल्लेख में व्यक्त भावनाओं के साथ जोड़ते हुए कुछ अनौपचारिक बातें कहना चाहता हूं । हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं । किसी न किसी दल से जुड़कर चुनाव लड़ते हैं, सदन में आते हैं । रोज सुबह सुबह एक प्रश्न सबके मन में आता होगा। हम क्यों आए हैं ? हम नया क्या कर सकते हैं ? आज का दिन हम कैसे सार्थक कर सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि वह दिन सबसे बेहतर होता है । जब दिन की समाप्ति में लगे कि आज मैंने कुछ काम किया । आज का दिन मुझे लगता है कि आज भी हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है । यह दिन की सार्थकता है कि हम कुछ नया करें और न या करने में ही उत्साह रहता है । जब नया करने की सोच आती है तो मुझे लगता है कि आज का विषय, वित्त मंत्री के रूप में मुझे लगा कि इस राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या धनराशि इंतजाम हो जाएगा । .... -- श्री अग्रवाल --

अग्रवाल\12-09-2018\i17\6.50-55

जारी...डा. रमन सिंह :- वित्त मंत्री के रूप में मुझे लगा कि इस राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या धनराशि का इंतजाम हो जाएगा, उसके लिए आज मैंने मंत्रिमण्डल के साथियों से बातचीत किया और सबने मिलकर ये निर्णय लिया और आज उसकी परिणीति हुई है। ये हमारे सार्वजनिक जीवन में आने का और कुछ न कुछ नई सोच के साथ काम करने का एक उदाहरण है । मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन के पवित्र मन से पिछले पूरे कार्यकाल के दौरान हम सबने इसका बेहतर उपयोग किया । अध्यक्ष जी, इस भूमिका को निभाने के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा । उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगण का आभारी हूं । हमारे विद्वान नेता प्रतिपक्ष सिंहदेव जी का, जो उनका रचनात्मक सुझाव मिलता है, उसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा । विधायक दल के सभी साथी, मेरे मंत्रिमण्डल के सभी सहयोगी, जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, विशेष सराहना के पात्र हैं । उनके सहयोग के बिना से सब संभव नहीं था । मुख्य सचिव, विधान सभा के सचिव, उनके सभी सहयोगी इस सदन के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुए । इस संक्षिप्त सत्र को आहूत करने में भी इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मीडिया के हमारे मित्र इस बार सड़क से सदन तक विधानसभा की हर कार्यवाही को तत्परतापूर्वक कवरेज किया, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं । पुन: एक बार गौरवशाली छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विकास और सुव्यवस्था के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने के साथ, संकल्प के साथ धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़ । फिर मिलेंगे, सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सफल हों । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम सत्र के अंतिम कार्यवाही के लिए, उसके संचालन के लिए आपका पुन: बहुत आभार । इस सत्र में भी दो ही दिन का रहा, लेकिन नये अनुभव हुए । बैलगाड़ी से लेकर सायकल तक के अनुभव हुए, आपस में विचारों के आदान-प्रदान का भी अनुभव हुआ । कटाक्षों का भी अनुभव हुआ, लेकिन सबके बीच में जो बात मन में बैठती है, वह आपसी संबंधों को प्रगाढ़ होने का भी होता है कि जितने आदान-प्रदान के बाद हम पुन: मुस्कुराकर मिल लेते हैं, वह उस बात को भी प्रमाणित करता है कि हममें एक दूसरे के प्रति वह भाव भी हैं कि ऐसी परिस्थितियों के आगे भी जाकर हम लोग और अच्छे तरीके से साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम करेंगे । ये भी बात आई कि बात कभी-कभी मानी जाती है तो अब जगह बदलने की बात मान ली जाएगी, मुझे लगता है (हंसी) और हम लोग और हंसी-खुशी अगली बार यहां मिलेंगे और अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार, मंत्रिमण्डल के सभी साथियों का पुन: आभार, सत्ता पक्ष के सभी विधायक साथियों का, अपने दल के सभी वरिष्ठ साथियों का, हमारे सचेतक, उप सचेतक, सभी सचिव महोदय का, साथ में उनके काम करने वाले सहयोगियों का और पूरे स्टाफ का और आखिर लेकर बहुत अधिक मीडिया के सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बगल से भी हम लोग आदान-प्रदान करते रहते हैं, परदे के पीछे करते हैं कि ज्यादा दिखाई न दे और खुशी होती है कि जब अच्छी बातों को मान भी लिया जाता है, कभी-कभी सुझाव भी मिलते हैं और जो हमारे प्रशासन के साथियों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, अन्य वरिष्ठ सभी अधिकारियों ने, डी.जी.पी. साहब मेरे ख्याल से नहीं आ सके होंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति मानकर उनके सभी कैडर के साथियों का भी सहयोग, हमारे जितने कर्मी साथ में यहां काम करते हैं, अंदर से लेकर बाहर तक, सभी का गहरा आभार और जरूर मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे ही दिया है कि यहां से वे कहां तक पहुंचेंगे । धन्यवाद । **श्री देवांगन**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देवांगन\12-09-2018\i18\06.55-06.60

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चंद्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के सत्र को आपने विशेष सत्र कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ में ही संभव है । हमने कभी माननीय पाण्डेय जी जब अध्यक्ष थे तो नक्सलियों पर बंद कमरे में क्लोज डोर मीटिंग की। आज किसानों पर विशेष सत्र हुआ और हम सबने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और नेता प्रतिपक्ष जी के सहयोग से इस विधान सभा ने यह साबित किया कि संसाधनों पर यदि हमारे पास कुछ भी अतिरिक्त है तो उसमें छत्तीसगढ़ के आम लोगों का और विशेष तौर पर किसानों का हक है। पिछले सत्र में हमने अपनी सहमति/असहमति, लोकतंत्र सब पर बात की थी। आज जिस रूप में भी सदन में आये हों, जो भी बात कही हो, वे अपने तौर-तरीके, अपने विश्वास हो सकते हैं पर सर्व स्थापित तथ्य यह है कि विशेष सत्र बुलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो इंकम दोगुनी करने का या उनको सुविधा देने का या अपने मेनोफेस्टो को विश्वसनीय बनाने के जो संसाधन थे, उसमें सबके प्रत्यनों से खरा उतरने की एक ईमानदार कोशिश हुई। आपने विशेष सत्र कहा है, इसलिए आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जब भी हमारे संसाधन होंगे तो एक उदाहरण और एक नजीर बनेगा। छत्तीसगढ़ के पास संसाधन हैं, आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के पास संभावनाएं बहुत होंगी, जिस तरह से नेतृत्व उनको आगे ले जा रहा है, यदि छत्तीसगढ़ के प्रति हमारी भावनाएं इस तरह से जीवंत रही तो निश्चित रूप से जो हम परिकल्पना करते हैं, संसाधनों से परिपूर्ण यह प्रदेश सबसे आगे जायेगा, निश्चित रूप से आगे जायेगा। यह हम लोग आज जो स्वरूप में चल रहे हैं, उसमें विश्वास व्यक्त कर सकते हैं।

इस संक्षिप्त सत्र के संचालन के लिए आपका मार्गदर्शन । आज भी हमारे कुछ अवरोध हुए पर आपने उसको आगे बढ़ाया और आज भी, जैसा नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे, फिर मुझे दुख होता है, वे मेरा नाम बस नहीं लेते। लेकिन चलो, आज कोई बात नहीं, समय कम है तो हम बढ़े, हम लड़े, लेकिन आपके नेतृत्व में जो करना था, वह किया।

नेता प्रतिपक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी के बिना तो सदन अधूरा है, लेकिन आज वे स्वांग वगैरह कर दिये, जो उनके स्वभाव के विपरीत है। सहज, सरल, आपकी जो मिलनसारिता है, वह ओरिजनल है। ये पटका-वटका आपका ओरिजनल नहीं है। हम लोग आपको उस रूप में नहीं देखते। स्वभाविकता आपकी पूंजी है। विद्वता आपकी पूंजी है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चाय फ्रेण्ड के लिए मैं बोलना भूल गया था। मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन सदन के संचालन में आपकी भी जो सदैव भूमिका बनी रहती है, मैं उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारे सदन के नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भावना के साथ विशेष सत्र के लिए सरकार ने काम किया। मैं सदन की ओर से, दल की ओर से, सब की ओर से उस प्रतिबद्धता के लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि किसानों के लिए उन्होंने तत्काल कार्यवाही की। जब उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर देखा कि एक संसाधन हो सकता है तो उस संसाधन में पहला अधिकार यहां के किसानों का है। हमारे विधान सभा के सचिव साहब विदेश का दौरा छोड़कर आए, हम उनको भी कह सकते हैं कि किसानों के लिए आए।

अध्यक्ष महोदय:- विदेश यात्रा बीच में ही छूट गई। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- उनके सभी साथियों का, सी.एस. साहब और पूरा प्रशासन बहुत संक्षिप्त समय में किसानों के लिए सारी तैयारियां की और बाकी व्यवस्थाओं के लिए भी उनके सहयोगी डी.जी.पी. साहब समेत उनके प्रति आभार और हमारे ऊपर के साथी लोग, जो इसकी जीवंतता को लोगों तक पहुंचाते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में सत्र चल रहा है। उस समय आप ही के लोगों को मैं श्रेय देता हूं, जो ऊपर बैठे हैं। विधानसभा में चारों तरफ देखें तो मॉल की तरह लगता है। लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मिल-जुल रहे हैं। एक जीवंतता दिखती है। लोक पंचायत जैसा दिखना चाहिए, वैसा महसूस होता है। माननीय भूपेश बघेल जी लेट से प्रवेश हुए पर उनकी भी इस पूरे पांच साल में अपनी एक शैली रही है। आप भारी दिख रहे हैं साहब। भारी दिखें, इस अपेक्षा के साथ सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्य-गण राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय

7.00 बजे **<u>राष्ट्रगान</u>**

(राष्ट्रगान 'जन गण मन' की धुन बजाई गई।)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 7 बजकर 01 मिनट पर विधान सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

रायपुर

दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं